www.indiatodayhindi.in

माओवादः शीर्ष पर आघात

भाजपा-सपाः एक-दूसरे के गढ़ों में सेंधमारी

मणिपुर में उग्रवाद पनपने की आशंका

1 दिसंबर, 2021 50 रुपए

इंडिया टुडे

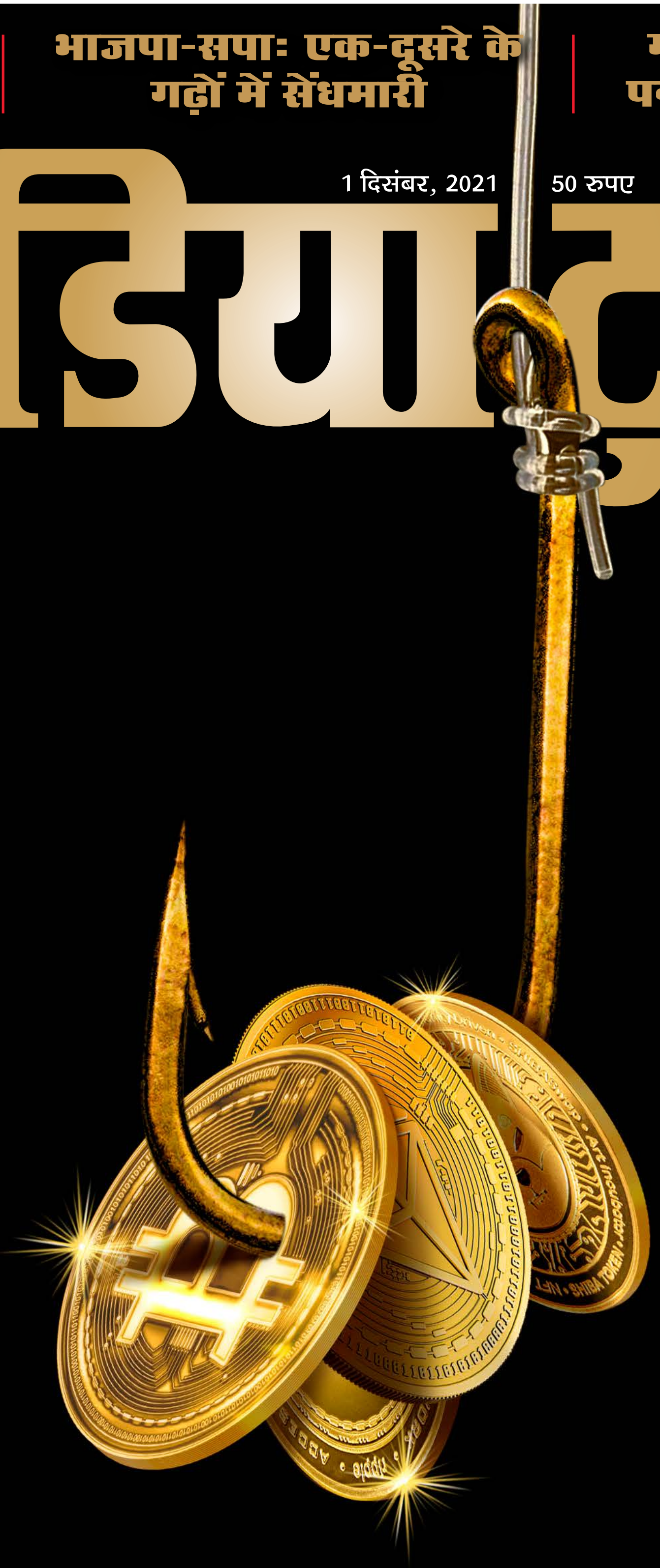

क्रिप्टो का कांटा

डेढ़ करोड़ से ज्यादा भारतीय क्रिप्टोकरेंसी पर लगा रहे हैं ऊंचा दांव. मोटी कमाई के प्रलोभन ने देश में इसके प्रति दीवानगी उफान पर पहुंचाई लेकिन नियम-कायदों की कमी बनी हुई है चिंता की बड़ी वजह

RNI NO 45823/86 REGISTERED NO. DL(ND)-11/6042/2021-22-2023; LICENSED TO POST WPP NO U(C)-31/2021-23; FARIDABAD/46/2020-22

अग्रिम सप्ताह के लिए प्रत्येक शनिवार को प्रकाशित; एलपीसी दिल्ली-आरएमएस-दिल्ली-110006 से प्रत्येक शनिवार और सोमवार को प्रेषित; कुल पन्नों की संख्या 74 (आवरण सहित)

OC

VISIT…

LANZAROTE
Caliente.com

50% से 80% लोगों को Vitamin D, B12, Calcium, Iron, Omega, Vitamin C, Zinc और Protein की कमी है

जिसकी वजह से वो low immunity, arthritis, खून की कमी, कमजोरी, कैन्सर, autoimmune disease, brain और nervous system की ख़तरनाक बीमारियों से जूझ रहे हैं।

Nutrela™ के Bio-fermented, ऑर्गेनिक, प्राकृतिक एवं 100% शाकाहारी पोषण अपनायें, स्वस्थ रहें और रोगों से लड़ने की शक्ति पायें

Ruchi
Ruchi Soya Industries Limited

पतंजलि®
Nutrela™
NUTRITION

COLLAGENPRASH
त्वचा की झुर्रियाँ हटाकर
सालों तक जवान
रहने के लिए अपनाइए
Collagenprash

DAILY ACTIVE
Multivitamin
41 पोषक तत्वों से निर्मित,
13 विटामिन, 8 ऑर्गेनिक
जड़ी-बूटियाँ, 12 मिनरल एवं
8 आवश्यक अमाइनो ऐसिड

VIT. & PROTEIN POWDERS
100% veg. और Plant
based Bio-fermented
न्यूट्रिशन आपके सम्पूर्ण
स्वास्थ्य के लिए
100% सुरक्षित

India's Most Certified Nutrition

Nutrela MENs SuperFood
Nutrela KID's SuperFood
Nutrela WOMEN's SuperFood
Nutrela VEG COLLAGEN
Nutrela COLLAGENPRASH
Nutrela ISO VEDA
Nutrela 100% WHEY PERFORMANCE
Nutrela DIABETIC CARE
Nutrela WEIGHT GAIN
Nutrela MOTHER'S PLUS
Nutrela ORGANIC OMEGA
Nutrela DAILY ENERGY
Nutrela DAILY ACTIVE
Nutrela BONE HEALTH
Nutrela VITAMIN D-2K
Nutrela IRON COMPLEX
Nutrela VITAMIN B12
Nutrela NATURAL VITAMIN C + ZINC
Nutrela NATURAL SPIRULINA
ऑर्गेनिक ओमेगा
B-complex प्राकृतिक विकल्प
Bio-Fermented मल्टीविटामिन
मोती पिष्टी से निर्मित
लाईकेन से निर्मित
प्राकृतिक आयरन
कॉर्न इक्स्ट्रैक्ट से निर्मित
रोज़ हिप से निर्मित
प्राकृतिक Spirulina

Nutrela Sandesh

Online Store: Amazon, Orderme app, www.nutrelanutrition.com
Retail Store: आपके नज़दीकी सभी पतंजलि चिकित्सालय, पतंजलि स्टोर और सभी प्रमुख स्टोर पर उपलब्ध।

Join us on social media:

Ruchi Soya Industries Limited, Regd. Office: Ruchi House, Royal palms, Survey no. 169, Aarey Milk Colony,
Near Mayur Nagar, Goregaon (E), Mumbai-400065
Website - www.nutrelanutrition.com | E-mail - wecare@nutrelanutrition.com | Phone - 18601800180

प्रधान संपादक की कलम से

अगर आप नई सहस्राब्दि पीढ़ी (मिलेनियल या फिर जेन ज़ी) के नहीं हैं तो मुमकिन है क्रिप्टोकरंसी सुनकर आपका माथा चकरा जाए. महामारी ने दुनिया भर में डिजिटल बदलाव को हवा दे दी है. बिटकॉइन जैसी क्रिप्टोकरंसी भी उसी बदलाव में से उभरी है. ऑनलाइन लेजर (बही-खाता) और एन्क्रिप्टेड डेटा के जरिए एक डीसेंट्रलाइज्ड सिस्टम सारी जमा-निकासी की जांच-पड़ताल करता है और उसका रिकॉर्ड रखता है. इसे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कहा जाता है. तमाम तरह की वित्तीय जमा-निकासी में अमूमन इसी का इस्तेमाल किया जाता है.

कई दशकों से देश में लोग अपनी बचत जमीन-जायदाद या रियल एस्टेट और सोने में निवेश करते रहे हैं. पिछले तीन दशकों से शेयर बाजारों में उछाल ने एक तीसरा रास्ता खोल दिया है. निवेश बैंकर गोल्डमैन सैक्स की एक हालिया रिपोर्ट का अनुमान है कि भारत का मार्केट कैपिटलाइजेशन यानी ट्रेडिंग वाले सारे शेयरों की कुल कीमत मौजूदा 30 खरब डॉलर से बढ़कर 2024 में करीब दोगुना 50 खरब डॉलर तक पहुंच जाएगी. फिक्स्ड डिपॉजिट पर कम ब्याज दर और रियल एस्टेट क्षेत्र में मंदी के माहौल में महामारी के दौरान निवेशकों का ध्यान चढ़ते शेयर बाजारों की ओर लगा रहा.

बाजार में पैसे की तेज आवक ने भी क्रिप्टोकरंसी के बाजार में भीड़ बढ़ा दी है. वजह साफ है. पिछले दो साल में कीमतों में विस्फोट-सा हुआ है. मार्च 2020 में जब महामारी का प्रकोप शुरू हुआ, एक बिटकॉइन की कीमत 6,483 डॉलर या करीब 4.8 लाख रुपए थी. अब इसकी कीमत 64,862 डॉलर या तकरीबन 48 लाख रुपए है. यानी कीमत में दस गुना बढ़ोतरी हुई. दूसरी क्रिप्टोकरेंसी की कीमतों में भी उछाल दर्ज हुआ है. इस तरह अपना पैसा बढ़ाने को लालायित देश के करोड़ों लोगों ने क्रिप्टोकरंसी की ओर रुख किया है. बिटकॉइन, इथेरियम, बिनांस कॉइन, सोलाना, टीथर, कार्डोनो, एक्सआरपी, पॉलकॉट, डोगेकॉइन और यूएसडी कॉइन जैसी क्रिप्टोकरंसी में 1.5 से 2 करोड़ भारतीयों ने तकरीबन 6 अरब डॉलर (44,400 करोड़ रु.) निवेश किए हैं. दिलचस्प यह है कि सिर्फ खरीद-बिक्री के लिए ही नहीं, देश के लोग क्रिप्टोकरंसी को रियल एस्टेट और सोने की तरह संपत्ति जैसा भी मान रहे हैं.

नैस्कॉम की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक, क्रिप्टो टेक इंडस्ट्री में अब 50 हजार लोग काम कर रहे हैं. यह उद्योग 2030 तक 24.1 करोड़ डॉलर के कारोबार तक बढ़ सकता है, और इससे 8 लाख लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद है. साठ फीसद भारतीय राज्यों ने क्रिप्टो टेक्नोलॉजी को अपना लिया है. 2020 में तमिलनाडु पहला राज्य बना, जिसने सभी सरकारी विभागों और एजेंसियों में ब्लॉकचेन इन्फ्रास्ट्रक्चर पेश किया. सितंबर में महाराष्ट्र सरकार ने आरटी-पीसीआर टेस्ट के नतीजों पर नजर रखने और फर्जीवाड़े से निबटने के लिए दो भारतीय ब्लॉकचेन स्टार्ट-अप्स की मदद ली.

क्रिप्टोकरंसी की शुरुआत 2008 के विश्वव्यापी आर्थिक संकट के बाद वित्तीय लेनदेन के परंपरागत तौर-तरीकों में भरोसा घटने से हुई. उस वक्त एक अज्ञात शख्स ने क्रिप्टोकरंसी की शुरुआत की, जिसे अब बिटकॉइन के नाम से जाना जाता है. लगभग दशक भर तक उसे लेकर तमाम तरह की झिझक और संकोच कायम रहा. भारत में तो उसे संदेह की नजर से देखा जाता रहा. इसकी एक वजह तो यह है कि इसका कारोबार बैंकिंग व्यवस्था के दायरे के बाहर होता है और सरकारी नियंत्रण से दूर है.

भारतीय रिजर्व बैंक ने 2018 में क्रिप्टोकरंसी में कारोबार पर प्रतिबंध लगा दिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की तीन जजों की पीठ ने पिछले साल मार्च में इस प्रतिबंध को हटा दिया. इससे क्रिप्टोकरंसी के कारोबार में तेजी आ गई. इस साल इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में एक कारोबारी टेक्नोलॉजी कंपनी के सह-संस्थापक तथा सीईओ कुणाल नंदवाणी ने क्रिप्टोकरंसी की तुलना किसी बीज से की, ''यानी जितना इसे गाड़ोगे, यह उतना ही उगेगा.''

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में 13 नवंबर को एक उच्चस्तरीय बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें सूत्रों के मुताबिक, क्रिप्टोकरंसी के विज्ञापनों में ''भ्रामक, कहीं ज्यादा का वादा और पारदर्शिता न होने'' के मसले पर विचार किया गया. बैठक में यह भी तय हुआ कि क्यों ''बेलगाम क्रिप्टो मार्केट को मनी लॉन्ड्रिंग और आतंक के लिए पैसा मुहैया करने का साधन बनने की मंजूरी नहीं दी जा सकती.''

इलस्ट्रेशनः नीलांजन दास

सरकार ने क्रिप्टोकरंसी को कानूनी लेनदेन या सामान्य करंसी या मुद्रा बनने की अनुमति देने से साफ इनकार कर दिया है. इसके बदले बहस इस बात पर है कि क्रिप्टो को संपत्ति या जायदाद की तरह मानकर उसका कारोबार किया जाए. फिर उसे कैसे नियमित/नियंत्रित किया जाए और कैसे उस पर टैक्स लगाया जाए. सरकार जल्दी ही नए नियम-कायदों का ऐलान कर सकती है. शायद संसद के शीतकालीन सत्र में क्रिप्टोकरंसी पर व्यापक विधेयक पेश किए जाने की उम्मीद है.

हमारी आवरण कथा 'क्रिप्टो कांटा' के लेखक एग्जीक्यूटिव एडिटर एम.जी. अरुण हैं. इसमें नई उछाल के नफे-नुक्सान और आगे की राह की पड़ताल है. क्या हम एक नया डिजिटल सवेरा देख रहे हैं या कि ये करंसियां किसी बुलबुले की तरह फट जाएंगी? सरकार को चाहिए कि वह निवेशकों के हितों के संरक्षण के लिए क्रिप्टोकरंसी को नियंत्रित करे. निवेशकों को वह पुरानी कहावत याद रखनी चाहिए कि ठोक-बजाकर खरीदो.

अपनी बात करूं तो मेरे मन में क्रिप्टोकरंसी को लेकर हमेशा ही संदेह था. मेरी नजर में यह टेक्नोलॉजी से खेलनेवालों का खेल भर था. मेरे सामने यह सवाल हमेशा बना रहा कि क्या क्रिप्टोकरंसी आपके बैंक खाते में नकदी में बदल सकती है? हाल में एक लड़के ने मेरे सामने इस ट्रांजैक्शन को करके दिखाया. तब मैंने खुद से कहा कि यह तो असली है और इसे बेहतर ढंग से समझने के लिए मैंने दो क्रिप्टोकरंसी में छोटा-मोटा निवेश किया. अगर यही भविष्य है तो मैं इसका हिस्सा बनना चाहता हूं.

अरुण पुरी

(अरुण पुरी)

इंडिया टुडे
www.indiatodayhindi.in

चेयरमैन और प्रधान संपादक: अरुण पुरी
वाइस चेयरपर्सन: कली पुरी
ग्रुप चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर: दिनेश भाटिया
ग्रुप एडिटोरियल डायरेक्टर: राज चेंगप्पा
चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर: मनोज शर्मा
एडिटर: सौरभ द्विवेदी
सीनियर एडिटर: मोहम्मद वक़ास
एसोसिएट एडिटर: शिवकेश मिश्र, आशीष मिश्र (लखनऊ)
असिस्टेंट एडिटर: मनीष दीक्षित, सुजीत ठाकुर
राज्य ब्यूरो:, अमिताभ श्रीवास्तव (पटना), रोहित परिहार (जयपुर), एम.जी. अरुण (मुंबई), राहुल नरोन्हा (भोपाल), अमरनाथ के. मेनन (हैदराबाद)
ग्रुप क्रिएटिव एडिटर: नीलांजन दास
एसोसिएट आर्ट डायरेक्टर: चंद्रमोहन ज्योति
असिस्टेंट आर्ट डायरेक्टर: असित रॉय
ग्रुप फोटो एडिटर: बंदीप सिंह
फोटो डिपार्टमेंट: यासिर इकबाल, राजवंत रावत, चंद्रदीप कुमार, मंदार सुरेश देवधर (मुंबई)
चीफ फोटो रिसर्चर: प्रभाकर तिवारी
प्रिंसिपल फोटो रिसर्चर: सलोनी वैद
प्रोडक्शन चीफ: अभिनव पुगला

एसोसिएट पब्लिशर: विद्या मेनन (इंपैक्ट)
इंपैक्ट टीम
नेशनल हेड: सुपर्णा कुमार (गवर्नमेंट ऐंड पीएसयू)
सीनियर जनरल मैनेजर: जीतेंद्र लाड (वेस्ट)
जनरल मैनेजर: मयूर रस्तोगी (नॉर्थ), उपेंद्र सिंह (बेंगलूरू)
डिप्टी जनरल मैनेजर: इंद्रनील चटर्जी (ईस्ट)
ग्रुप चीफ मार्केटिंग ऑफिसर: विवेक मल्होत्रा
सेल्स एवं ऑपरेशन
सीनियर जनरल मैनेजर: दीपक भट्ट (नेशनल सेल्स)
जनरल मैनेजर: विपिन बग्गा (ऑपरेशंस)
डिप्टी जनरल मैनेजर: राजीव गांधी (नॉर्थ)
डिप्टी रीजनल सेल्स मैनेजर: योगेश गोधनलाल गौतम (वेस्ट)
डिप्टी रीजनल सेल्स मैनेजर: एस. परमशिवम (साउथ)
सीनियर सेल्स मैनेजर: पीयूष रंजन दास (ईस्ट)

INDIA TODAY GROUP

वर्ष: 36; अंक: 1; 25 नवंबर-1 दिसंबर, 2021; प्रत्येक शनिवार को प्रकाशित

- **संपादकीय कॉर्पोरेट कार्यालय:** लिविंग मीडिया इंडिया लिमिटेड, इंडिया टुडे ग्रुप मीडियाप्लेक्स, एफसी-8, सेक्टर 16-ए, फिल्म सिटी, नोएडा-201301, फोन: 0120-4807100;
- **ग्राहकी चंदा भेजें:** इंडिया टुडे (हिंदी), पो. बॉक्स 114, नई दिल्ली-110001
- **ग्राहक सेवा:** कस्टमर केयर, इंडिया टुडे ग्रुप, सी-9, सेक्टर-10, नोएडा (उत्तर प्रदेश)-201301, टोल फ्री फोन नं. 1800 1800 100 (बीएसएनएल/एमटीएनएल लाइनों से) फोन: दिल्ली, फरीदाबाद से (95120) 2479900; शेष भारत से (0120) 2479900. (सोम से शुक्र-सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक), फैक्स: (0120) 4078080. ई-मेल: wecare@intoday.com
- **सर्कुलेशन कार्यालय:** लिविंग मीडिया इंडिया लिमिटेड, सी-9, सेक्टर-10, नोएडा (उत्तर प्रदेश)-201301
- **इंपैक्ट कार्यालय:** 1201, 12वां तल, टावर 2ए, वन इंडियाबुल्स सेंटर, (जुपिटर मिल्स) एस.बी. मार्ग, लोअर परेल (पश्चिम)-मुंबई-400013. फोन: 022-66063355 फैक्स: 022-66063226
- **क्षेत्रीय विज्ञापन कार्यालय:** ए1-ए2, एनके सेंटर, विनुज्य निकुंज, उद्योग विहार, फेज-5, गुड़गांव, हरियाणा, फोन: 0124-4948400;
- 201-204 रिचमंड टावर्स, द्वितीय मंजिल, 12 रिचमंड रोड, बंगलुरू-560 025 फोन: 2212448, 226233, टेलेक्स: 0845-2217 INTO IN. फैक्स: 080-2218335.
- रजिस्टर्ड कार्यालय: एफ-26, फर्स्ट फ्लोर, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली-110001
- लिविंग मीडिया इंडिया लि. विश्व भर में सर्वाधिकार सुरक्षित. किसी भी रूप में सामग्री की नकल प्रतिबंधित. इंडिया टुडे अनिमंत्रित प्रकाशन सामग्री को लौटाने की जिम्मेदारी स्वीकार नहीं करता.
- सभी विवादों का निबटारा दिल्ली/नई दिल्ली की सीमा में आने वाली सक्षम अदालतों और फोरमों में किया जाएगा.
- **लिविंग मीडिया इंडिया लि. के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक मनोज शर्मा द्वारा एफ-26, फर्स्ट फ्लोर, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली-110001 से प्रकाशित और थॉमसन प्रेस इंडिया लि., 18-35, माइलस्टोन, दिल्ली-मथुरा रोड, फरीदाबाद-121 007 (हरियाणा) में मुद्रित.**

संपादक: राज चेंगप्पा

भीतर

सुर्खियां

नौकरशाही का विस्तार: अब लंबा कार्यकाल
पेज 6

कोविड-19 बच्चों का टीका: चलना है संभल-संभल के
पेज 20

फुरसत

स्मृति/मन्नू भंडारी: कभी न होगा उनका अंत
पेज 69

सवाल-जवाब/कार्तिक आर्यन: अपनी जिंदगी का ऐंकर
पेज 72

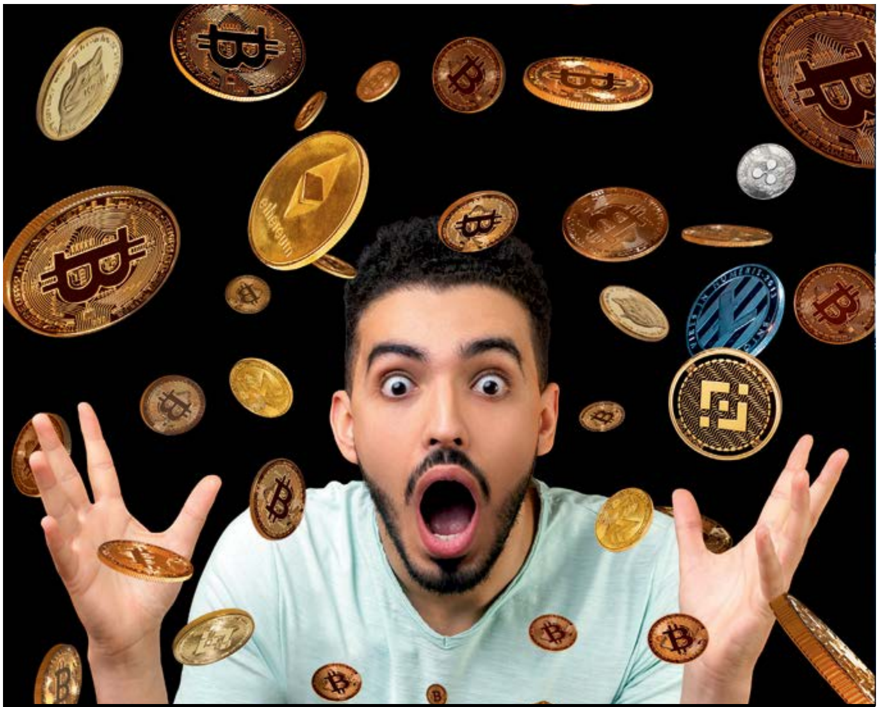

फोटो इलस्ट्रेशन: बंदीप सिंह, डिजिटल इमेजिंग: अमरजीत सिंह नागी

आवरण कथा

22 क्रिप्टो करेंसी का जुनून

क्रिप्टो के उन्माद को हवा दे रहा है डिजिटल मुद्रा में युवा भारतीयों का 6 अरब डॉलर का निवेश. क्या यह बुलबुला है जो फूटने का इंतजार कर रहा है?

मणिपुर हमला

34 उग्रवाद की वापसी!

म्यांमार सीमा के पास एक सैन्य काफिले पर भीषण हमले ने राज्य में हालिया अतीत में कायम शांति को छिन्न-भिन्न कर दिया है.

माओवादी

38 शीर्ष पर हमला

माओवादी उग्रवाद के लिए नवंबर खराब महीना साबित हुआ. चार शीर्ष नेताओं का काम तमाम होने के बाद उनका नेतृत्व चरमरा गया.

उत्तर प्रदेश

42 घरों में होने लगी घुसपैठ

अगले विधानसभा चुनावों के लिए भाजपा ने सपा के मजबूत इलाकों में तो सपा ने भाजपाई गढ़ों में घुसपैठ के दांव चलने शुरू किए.

ऑटो रिपोर्ट

53 हवाई सफर का एहसास

कैसी है इलेक्ट्रिक वाहनों की नई खेप? जाड़े के दिनों में गाड़ी चलाते समय किन बातों का रखें ख्याल?

टूरिज्म सर्वे ऐंड अवाड्‌र्स

62 फिर जमने लगे कदम

कोविड से सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्रों में से एक रहा है पर्यटन. पर यह एक बार फिर पटरी पर आने लगा है.

इंडिया टुडे
इंडिया टुडे मैगजीन मिलने में दिक्कत हो रही है?
7303086006 पर नाम पता या 'हेलो' संदेश भेजें.
या मेल करें: wecare@intoday.com
हम आपसे संपर्क कर लेंगे.

आवरण: **नीलांजन दास**; डिजिटल इमेजिंग: **अमरजीत सिंह नागी**

पाठकों के लिए सूचना: कभी-कभी आपको इंडिया टुडे पत्रिका में 'इम्पैक्ट फीचर' या 'एडवरटोरियल' या 'फोकस' के पन्ने नजर आएंगे. ये विज्ञापन होंगे और इन्हें बनाने में पत्रिका के संपादकीय स्टाफ शामिल नहीं होते.

INDIA TODAY GROUP

पाठकों को सलाह दी जाती है कि पत्रिका में प्रकाशित किसी भी सेवा या व्यक्ति के विज्ञापन और प्रचार से संबंधित सामग्री से वचनबद्धता कायम करने, पैसा भेजने या खर्च करने से पहले उचित जांच-पड़ताल कर लें. विज्ञापनदाताओं के किसी भी दावे का उत्तरदायित्व इंडिया टुडे ग्रुप का नहीं है. ऐसे किसी भी तरह के दावों को विज्ञापनदाता अगर नहीं पूरा करता है तो इंडिया टुडे ग्रुप के प्रकाशनों के मुद्रक, प्रकाशक, एडिटर-इन-चीफ और एडिटर इसके लिए जिम्मेदार नहीं होंगे.

अतुल्य!भारत

उत्तराखंड में होम
स्टे उपलब्ध हैं

सुकून के पलों और खूबसूरत यादों के लिए

आइए
उत्तराखंड

दिलकश और मंत्रमुग्ध कर देने वाले नजारे

आइए देखिए उत्तराखंड की खूबसूरती। मनोरम पर्यटक स्थलों अल्मोड़ा, औली, नैनीताल, हरिद्वार, उखीमठ, जोशीमठ, खरसाली, मुखबा, जिम कार्बेट नेशनल कांफ्रेंस, लैंसडाउन, चोपटा, बिनसर, कौसानी, मक्तेश्वर, खिरसू आदि।

उत्तराखण्ड
सचमुच स्वर्ग !
www.uttarakhandtourism.gov.in

उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद
पं. दीनदयाल उपाध्याय, पर्यटन भवन, निकट ओ.एन.जी. सी. हैलीपैड, गढ़ीकैन्ट, देहरादून फोन न.: 0135 2559898, फैक्स न.: 0135 2559988

कृषिः खाद का संकट
पेज 10

कोविड-19 बच्चों का टीकाः चलना है जरा संभल-संभल के
पेज 20

सुर्खियां

पश्चिम बंगालः क्यों इतना अहम है देवचा पचमी कोल ब्लॉक?
पेज 16

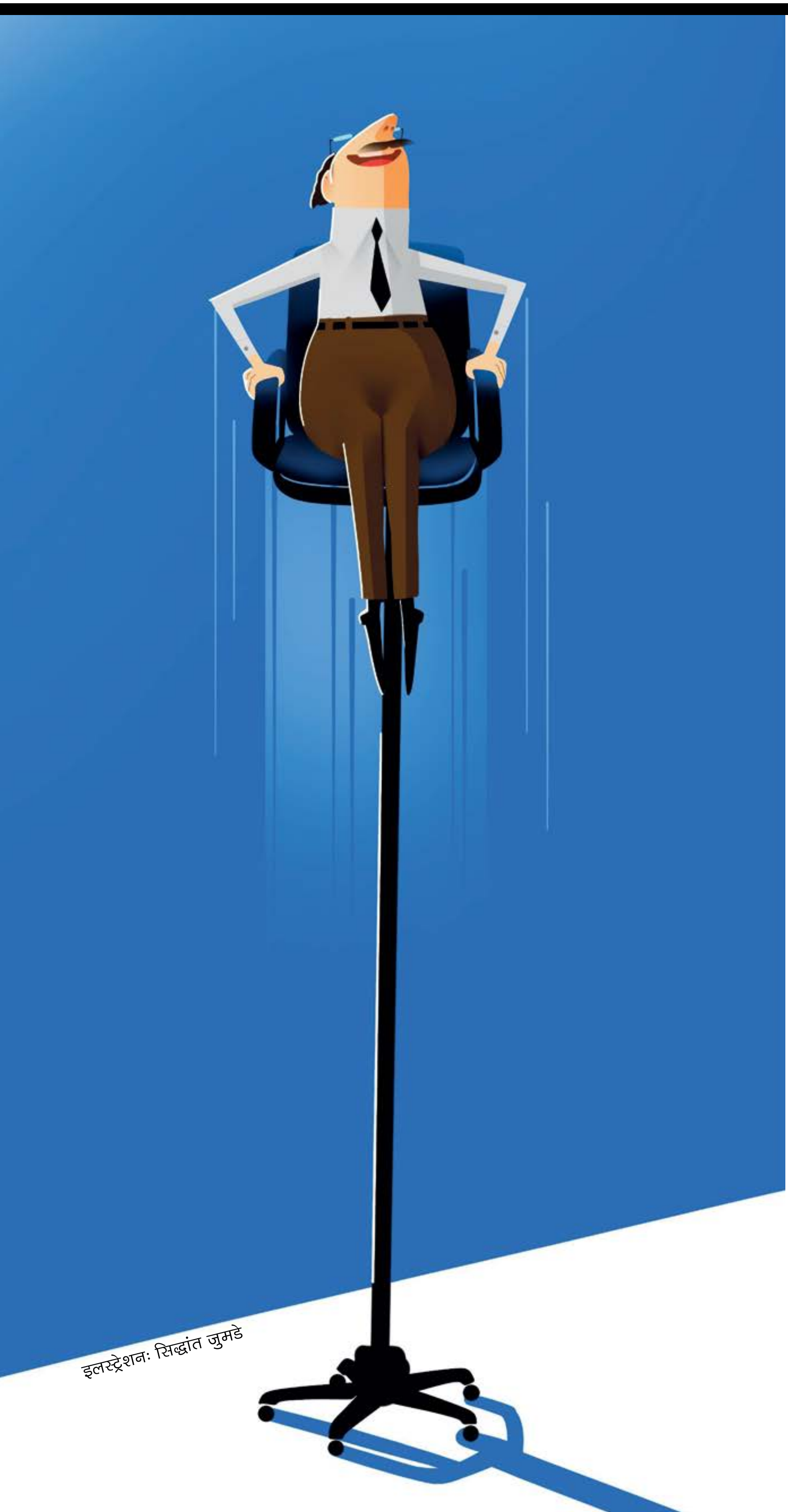

इलस्ट्रेशनः सिद्धांत जुमडे

नौकरशाही का विस्तार

अब लंबा कार्यकाल

कौशिक डेका

नवंबर की 14 तारीख को, संसद का शीतकालीन सत्र शुरू होने से दो हफ्ते पहले, केंद्र सरकार ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआइ) के निदेशकों के कार्यकाल को पांच साल तक बढ़ाने के लिए एक अध्यादेश पारित किया. दोनों पदों का दो साल का निश्चित कार्यकाल था, भले ही उनकी सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष हो.

इसे लागू करने के लिए केंद्र सरकार ने दिल्ली पुलिस विशेष प्रतिष्ठान (डीपीएसई) अधिनियम और केंद्रीय सतर्कता अधिनियम (सीवीसी) में संशोधन करने के अलावा, 2005 में पेश किए गए केंद्रीय सिविल सेवा के मौलिक नियमों में भी संशोधन किया है. यह केंद्र सरकार को रक्षा सचिव, गृह सचिव, इंटेलिजेंस ब्यूरो (आइबी) के निदेशक और रिसर्च ऐंड एनालिसिस विंग (रॉ) के सचिव के कार्यकाल को दो साल तक के लिए बढ़ाने की शक्ति देता है. इन अधिकारियों का भी अधिकतम कार्यकाल दो साल का होता है.

विपक्षी नेताओं ने सरकार के इस कदम के समय को लेकर हंगामा किया है. राजद (राष्ट्रीय जनता दल) के राज्यसभा नेता मनोज झा कहते हैं, ''संसद बुलाने से ठीक पहले सीबीआइ और ईडी प्रमुखों का कार्यकाल बढ़ाने का अध्यादेश केंद्र की मंशा पर संदेह पैदा करता है.'' 17 नवंबर को, तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा ने सुप्रीम कोर्ट का रुख करते हुए अध्यादेश को सीबीआइ और ईडी प्रमुखों के कार्यकाल पर शीर्ष अदालत के पिछले फैसलों का उल्लंघन बताते हुए चुनौती दी. उसी दिन, सरकार ने ईडी के निदेशक संजय कुमार मिश्र का कार्यकाल एक साल के लिए बढ़ा दिया. वह 18 नवंबर को सेवानिवृत्त होने वाले थे.

हालांकि, सरकारी सूत्रों का कहना है कि हाइ-प्रोफाइल जांच में निरंतरता बनाए रखने के लिए

देखिए
RAJASTHAN
गराडिया महादेव, कोटा

www.tourism.rajasthan.gov.in, www.rtdc.tourism.rajasthan.gov.in

rajasthantourism my_rajasthan rajasthan_tourism Rajasthan Tourism Channel

Department of Tourism, Government of Rajasthan

पधारो म्हारे देस
RAJASTHAN TOURISM
राजस्थान
भारत का अतुल्य राज्य !

पारी का विस्तार

इन पदों का कार्यकाल दो साल का होता है, सेवानिवृत्ति की उम्र भले ही 60 साल है. नया अध्यादेश ईडी और सीबीआइ के निदेशकों को अधिकतम 3 साल और अन्य को 2 साल तक सेवा विस्तार की अनुमति देता है

पद	अधिकतम विस्तार
डायरेक्टर, ईडी	तीन साल
डायरेक्टर, सीबीआइ	तीन साल
डायरेक्टर, इंटेलिजेंस ब्यूरो	दो साल
सेक्रेटरी, रॉ	दो साल
रक्षा सचिव	दो साल
गृह सचिव	दो साल

कई सिविल सेवकों का मानना है कि इससे नौकरशाही में उत्तराधिकार की शृंखला प्रभावित होगी, इसलिए वे नाराज हैं

इस तरह के विस्तार की जरूरत होती है, वहीं, कांग्रेस के मीडिया प्रभारी रणदीप सुरजेवाला का दावा है कि तीन साल के सेवा विस्तार का मकसद कुछ नौकरशाहों को 2024 की लोकसभा तक अपने विभागों के प्रमुख के रूप में बनाए रखना है, ताकि विपक्षी नेताओं के खिलाफ जांच का प्रबंधन लचीले अफसरों के जरिए किया जा सके. वे कहते हैं, ''ईडी भाजपा का इलेक्शन डिपार्टमेंट बन गया है और सीबीआइ अब 'कॉम्प्रमाइज्ड ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन' है.''

उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव (यूपी में अगले साल की शुरुआत में चुनाव होने हैं) के अलावा हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपिंदर सिंह हुड्डा, पूर्व केंद्रीय मंत्री पी. चिदंबरम, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी और महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजीत पवार ईडी जांच का सामना करने वाले विपक्षी नेताओं में शामिल हैं.

सुप्रीम कोर्ट ने अगस्त में जनप्रतिनिधियों के खिलाफ ईडी/सीबीआइ मामलों की जांच में अत्यधिक देरी पर चिंता व्यक्त की थी. मौजूदा या पूर्व 51 सांसदों और 112 विधायकों के खिलाफ सीबीआइ के 121 मामले हैं. कथित अपराध कई साल पहले के होने के बावजूद 45 मामलों में आरोप तय नहीं किए गए हैं. ईडी 51 मौजूदा/पूर्व सांसदों और 71 मौजूदा/पूर्व विधायकों या एमएलसी के खिलाफ 122 मामलों की जांच कर रहा है.

विपक्षी दल नरेंद्र मोदी सरकार पर हर विभाग में अपने पसंदीदा अधिकारियों को सेवा विस्तार देने का भी आरोप लगाते हैं. मई में, केंद्र ने आइबी प्रमुख अरविंद कुमार और रॉ सचिव सामंत कुमार गोयल के कार्यकाल को एक साल के लिए बढ़ा दिया. अगस्त में, केंद्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला को एक साल का विस्तार दिया गया था. कैबिनेट सचिव राजीव गौबा को भी एक साल का विस्तार मिला, जो 30 अगस्त को सेवानिवृत्त होने वाले थे.

पी.के. सिन्हा, जिन्हें 2015 में कैबिनेट सचिव नियुक्त किया गया था, को 2019 तक उस कार्यालय में बने रहने के लिए तीन सेवा विस्तार मिले—वह अब तक के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले कैबिनेट सचिव हैं. मोदी के नेतृत्व में सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले नौकरशाह के. कैलाशनाथन रहे हैं, तब मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे. 2013 में सेवानिवृत्त होने के बाद, कैलाशनाथन को भूपेंद्रभाई पटेल सहित गुजरात के तीन मुख्यमंत्रियों के मुख्य प्रधान सचिव के रूप में जारी रखने के लिए सात सेवा विस्तार मिले हैं.

विस्तार की संस्कृति भारतीय राज्यों के लिए नई बात नहीं है. दिसंबर 2020 में, दो सेवा विस्तार के बाद आंध्र प्रदेश के मुख्य सचिव के रूप में सेवानिवृत्त हुई नीलम साहनी को तुरंत मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी का प्रमुख सलाहकार नियुक्त किया गया. उसी महीने, ओडिशा के मुख्य सचिव असित कुमार त्रिपाठी, अपनी सेवानिवृत्ति के तुरंत बाद, मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के प्रमुख सलाहकार बने. इसी साल मई में, ममता बनर्जी ने मुख्य सचिव अल्पन बंद्योपाध्याय को उनकी सेवानिवृत्ति के बाद अपना मुख्य सलाहकार नियुक्त किया. महाराष्ट्र में, मुख्य सचिव के रूप में दो विस्तार के बाद, अजय मेहता को जून में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का प्रमुख सलाहकार नियुक्त किया गया था.

एक ओर जहां सीबीआइ और ईडी प्रमुखों का कार्यकाल लंबा करने की मांग की जाती रही है, वहीं पूर्व नौकरशाहों का कहना है कि मनमाने ढंग से विस्तार करना इसका कोई तरीका नहीं है. ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च ऐंड डेवलपमेंट के पूर्व महानिदेशक एन.आर. वासन का मानना है कि लंबे कार्यकाल में नियुक्ति के लिए एक मजबूत तंत्र होना चाहिए. सीबीआइ और राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआइए) में भी काम कर चुके वासन कहते हैं, ''यह निर्णय तीन व्यक्तियों के बीच आधे घंटे की बैठक में नहीं लिए जाने चाहिए, जैसा कि अब होता है. पूर्व में कदाचार की घटनाओं को देखते हुए ऐसे अधिकारियों को हटाने के लिए एक पारदर्शी व्यवस्था भी होनी चाहिए.''

वासन अपने कई सहयोगियों से सहमत हैं कि सभी दलों की सरकारों ने पसंदीदा अफसरों को बनाए रखने के लिए सेवा विस्तार का इस्तेमाल किया है. यूपीए शासन के दौरान मनमोहन सिंह ने टी.के.ए. नायर को तीन साल के लिए प्रमुख सचिव के रूप में नियुक्त किया था. वह चार सेवा विस्तार से सात साल तक पद पर बने रहे, और फिर उन्हें पीएमओ का सलाहकार बनाया गया.

पूर्व केंद्रीय गृह सचिव जी.के. पिल्लै अधिकारियों के लंबे कार्यकाल के खिलाफ नहीं हैं, बशर्ते इसकी निश्चित शर्तें हों और वार्षिक विस्तार के रूप में नहीं सौंपे गए हों. पिल्लै कहते हैं, ''संदेश स्पष्ट है—आप लंबे समय तक पद पर बने रह सकते हैं और सेवानिवृत्ति के बाद के लाभों की अपेक्षा कर सकते हैं यदि आप (अपने) राजनैतिक आकाओं को खुश करते हैं. इसने 1997 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले (जिसने सीबीआइ निदेशक के लिए न्यूनतम दो साल का कार्यकाल निर्धारित किया) की अहमियत को कम कर दिया है.'' वह कहते हैं, ''हाल ही में, हमने देखा कि कैसे केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के प्रमुख को तीन सेवा विस्तार दिए गए और सेवानिवृत्ति के बाद, वह राज्यसभा के महासचिव बनाए गए.''

इन विस्तारों की नैतिकता या प्रासंगिकता पर विवाद के अलावा, केंद्रीय सिविल सेवाओं के मौलिक नियमों में बदलाव से सेवारत सिविल सेवकों में बहुत नाराजगी है, जो मानते हैं कि नौकरशाही में उत्तराधिकार की शृंखला के प्रभावित होने का अंदेशा है. ज्यादातर नौकरशाहों को इस बात का डर है कि इससे कॉडर का मनोबल गिर सकता है. संसद के आगामी सत्र में इस मुद्दे पर विपक्ष के हमले की तैयारी कर रही मोदी सरकार के लिए शायद इससे निपटना एक बड़ी चुनौती है. ■

WE AREN'T A COURT OF JUDGEMENT

To tell you what's good or bad,
what mindset you should have,
what ideology you should follow,
who is right or wrong.

These are your decisions to make.
Never ours.

We believe in just one thing.
Your voice matters.
Irrespective of who you are,
where you come from,
where you stand,
what you do
and, who you support.

We are the India Today Group.
Where every voice finds its right.
And every right finds a voice.

WE'RE ALWAYS IN CONVERSATION WITH YOU.

INDIA TODAY GROUP

INDIA'S DEMOCRATIC
NEWSROOM

कृषि

असंतोष की खाद

राहुल नरोन्हा

IFFCO
इफको किसान सेवा
खाद तो खाद बीमा
सभी फसलों की दवाईयां उपल
साद सुरेश चन्द्र
3 एजेन्ट
162

प्रभजोत गिल

इन दिनों देश भर के किसान खाद (उर्वरक) और खासकर डायअमोनियम फॉस्फेट (डीएपी) और यूरिया की कमी से परेशान हैं. रबी का सीजन चल रहा है और ये दोनों ही इस सीजन में खेती के लिए जरूरी हैं. इनकी किल्लत से बुआई में देरी हो रही है, जिससे उपज कम होगी और किसानों की आमदनी घटने का खतरा है. इस संकट की वजह से राजनैतिक पार्टियों का समर्थन-आधार भी टूटने का खतरा है. खासकर, उत्तर प्रदेश और पंजाब में चुनाव होने वाले हैं और इन दोनों ही प्रदेशों में किसान अहम राजनैतिक धड़े हैं. लिहाजा यहां इस संकट के ज्यादा तीखे नतीजे हो सकते हैं.

डीएपी की कमी के पीछे बहुत कुछ अंतरराष्ट्रीय वजहें हैं. मगर यह भी सच है कि केंद्र सरकार ने उर्वरकों पर सब्सिडी का ऐलान देर से किया, जिसकी वजह से ऑर्डर देने में देरी हुई. देश को एक साल में 90 लाख टन डीएपी की जरूरत होती है, जिसमें से 61 लाख टन आयात के माध्यम से पूरी होती है. दरअसल, भारत दुनिया में डीएपी का सबसे बड़ा आयातक देश है. इस मामले में भारत के बाद पाकिस्तान, अमेरिका, तुर्की और वियतनाम का स्थान है. खाद की इस जबरदस्त किल्लत की दूसरी वजह यह है कि बीते दशक में भारत ने छह बड़े उर्वरक कारखाने बंद कर दिए, क्योंकि पता चला कि उत्पादन के मुकाबले आयात कहीं ज्यादा सस्ता है. वह फैसला अब बड़ा संकट लेकर आया है. दरअसल, चीन ने फॉस्फेट के निर्यात पर पाबंदी लगा दी और इसका असर दुनिया के साथ हम पर भी पड़ा. उर्वरकों का सबसे बड़ा उत्पादक देश चीन, भारत को डीएपी का सबसे बड़ा सप्लायर भी है.

केंद्रीय उर्वरक मंत्रालय के शीर्ष अधिकारी खाद की कमी की बात से इनकार करते हैं. मगर वे अधिकारी इस बात की शिकायत भी करते हैं कि 'दहशत और अफवाहों' के कारण 'जमाखोरी हो रही है'. पिछले हफ्ते पंजाब के कृषि मंत्री रणदीप सिंह नाभा ने केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री मनसुख मांडविया से मिलकर राज्य में उर्वरकों की कमी का मुद्दा उठाया है. पंजाब के किसान केंद्र सरकार के नए कृषि कानूनों को लेकर पहले ही आगबबूला हैं. अब खाद के इस संकट से उनका आक्रोश और बढ़ गया है. दूसरी तरफ, पंजाब के पड़ोसी राज्य हरियाणा में तो राज्य सरकार को उर्वरक बिक्री केंद्रों पर पुलिस लगानी पड़ी. यहां तक कि कुछ इलाकों में पुलिस थानों से खाद का वितरण करना पड़ा.

डीएपी की गंभीर किल्लत की वजह से उसकी जमाखोरी और कालाबाजारी हो रही है. यह भी आरोप है कि मिलीभगत से निजी व्यापारियों को खाद की खेप दे दी गई है

मध्य प्रदेश में यह संकट अक्तूबर के तीसरे हफ्ते में सबसे पहले भिंड और मुरैना के उत्तरी जिलों से शुरू हुआ, जहां किसानों ने हाइवे पर जाम लगा दिया. सरकार की ओर से संचालित प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी (पीएसीएस) के बिक्री केंद्रों के बाहर लंबी कतारें लग गईं और कानून-व्यवस्था संभालना मुश्किल हो गया. कुछ जगहों पर तो किसानों पर लाठी चार्ज करना पड़ा. उर्वरकों की लूट की भी खबरें आईं.

आधिकारिक तौर पर तो मध्य प्रदेश सरकार भी इस बात से इनकार करती है कि खाद की कमी है. मध्य प्रदेश के अतिरिक्त मुख्य सचिव, कृषि, अजित केसरी कहते हैं, "पर्याप्त खाद उपलब्ध है, हालांकि आशंका से भरे खरीद का रुझान भी देखा गया है. माल आते ही उठाया जा रहा है, इसीलिए गोदामों में इसके अंबार दिखाई नहीं देते. बुआई निर्धारित समय सीमा में पूरी हो जाएगी."

खाद की कमी के चलते कालाबाजारी भी हो रही है. भारतीय किसान यूनियन के मध्य प्रदेश इकाई के महासचिव अनिल यादव कहते हैं, "सरकार का दावा है कि कोई कमी नहीं है. उसका यह भी कहना है कि 70 फीसद माल पीएसीएस और 30 फीसद निजी व्यापारियों के जरिए दिया जा रहा है. अगर ऐसा है तो फिर पीएसीएस में कमी क्यों है और निजी

किल्लत
हिसार की अनाज मंडी में डीएपी की खेप आने का इंतजार करते किसान

खेती का सवाल

1.2

लाख करोड़ रुपए

की सब्सिडी दी केंद्र ने इस साल उर्वरकों पर; किसानों को बढ़ती कीमतों से राहत देने के लिए इस रबी सीजन में **25,000 करोड़ रुपए** ढीले करने होंगे

61

लाख टन

डीएपी भारत हर साल आयात करता है कुल **90 लाख टन** की सालाना जरूरत पूरी करने के लिए. भारत दुनिया में डीएपी का सबसे बड़ा आयातक देश है

स्रोतः एरगस और केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय

व्यापारियों के पास कमी क्यों नहीं है? जाहिर है मिलीभगत का खेल चल रहा है.'' यादव का दावा है कि डीएपी का 1,200 रुपए में मिलने वाला एक बोरा 1,500 रुपए में, या खरीदने की तत्काल जरूरत और उतावली देखकर उससे भी ऊंचे दाम में बेचा जा रहा है.

किसान कह रहे हैं कि बुआई में देरी का बुरा असर उपज पर पड़ेगा. धार जिले की बदनावर तहसील के साहबनगर गांव के किसान संजय पटेल कहते हैं, ''मैंने एचआइ 1544 प्रजाति की बुआई का मंसूबा बनाया, जिसे तीन सिंचाई की जरूरत होती है. मैं जितनी देर से बुआई करूंगा, मेरे ट्यूबवेल सूखने की आशंका उतनी ही बढ़ जाएगी और सिंचाई के लिए पानी नहीं मिलेगा, क्योंकि खाद का जुगाड़ कर लेने वाले बुआई पूरी कर चुके होंगे और पूरा पानी निकाल लेंगे.'' गेहूं की फसल को प्रति एकड़ 50-60 किलो डीएपी की जरूरत होती है, जबकि चने सरीखी फसलों के लिए कम डीएपी चाहिए. डीएपी को बीज के साथ मिलाते हैं और थोड़े-से यूरिया के साथ बुआई की जाती है.

पहले उर्वरकों की कमी आए दिन की घटना हुआ करती थी. पिछले पांच साल में सरकार ने इस समस्या को बड़ी हद तक कामयाबी से हल कर लिया था. कैसे किया था? कृषि विभाग के सूत्र बताते हैं कि पीएसीएस को रोलिंग स्टॉक रखने के लिए प्रोत्साहित किया गया, जिससे खरीफ सीजन के माल का इस्तेमाल किसान रबी सीजन में भी कर पाएं.

फिर इस साल हालात क्यों बदल गए? अधिकारी इसके लिए केंद्र सरकार की तरफ से सब्सिडी के फैसले में देरी को दोषी ठहराते हैं. उर्वरक मुहैया करवाने का चक्र पूरे साल चलता रहता है. राज्य केंद्रीय कृषि मंत्रालय को अपनी जरूरत बताते हैं, जिसे जोड़कर रसायन और उर्वरक मंत्रालय को कुल मांग बता दी जाती है. उर्वरक या उन्हें बनाने में लगने वाले कच्चे माल की मांग का बड़ा हिस्सा आयात से पूरा किया जाता है. केंद्र नाइट्रोजन (एन), फॉस्फोरस (पी) और पोटेशियम (के) पर अलग-अलग मात्रा में पोषण-आधारित सब्सिडी देता है. इस साल उर्वरक और उनके कच्चे माल के दामों में शुरू से ही तेजी देखी गई. मुख्य वजह थी डीजल की बढ़ती कीमतें. इसकी वजह से डीएपी के 50 किलो के बोरे की कीमत 1,200 रुपए से बढ़कर 1,900 रुपए पर पहुंच गई.

केंद्र सरकार को इसके राजनैतिक नतीजों को लेकर फिक्र हुई और उसने ऐलान किया कि इस कीमत वृद्धि से राहत देने के लिए वह सब्सिडी बढ़ाएगी. सब्सिडी तब 500 रुपए से बढ़ाकर 1,200 रुपए कर दी गई, जिससे कीमत 1,900 रुपए से घटकर 1,200 रुपए पर आ गई. खरीफ के सीजन में ऐसा कोई संकट नहीं था. तब रबी के सीजन की तुलना में मांग कम भी होती है. डीएपी की अंतरराष्ट्रीय कीमतें अलबत्ता खरीफ के सीजन से ही बढ़ने लगीं और करीब 580 डॉलर प्रति टन से बढ़कर 650 डॉलर से ऊपर चली गईं. इसी तरह यूरिया के अंतरराष्ट्रीय दाम भी खरीफ सीजन के एक महीने में ही 410 डॉलर प्रति टन से बढ़कर 440 डॉलर पर पहुंच गए.

रबी सीजन के लिए सब्सिडी बढ़ाने का फैसला सितंबर के अंत में जाकर लिया गया. लिहाजा ऑर्डर देने में देर हुई और अंतरराष्ट्रीय शिपिंग लाइनों में भीड़ बढ़ने और जाम लगने का असर आपूर्ति पर भी पड़ा. मध्य प्रदेश के एक बड़े अफसर कहते हैं, ''अगर ऑर्डर जुलाई या अगस्त में दे दिए जाते, तो इस देरी से बचा जा सकता था.'' केंद्र सरकार ने अब उत्पादन इकाइयों और बंदरगाहों से रेक पॉइंट और उनसे आगे राज्यों तक आपूर्ति पर नजर रखने के लिए एक टीम बनाई है.

केंद्र सरकार की तरफ से दी जा रही खाद सब्सिडी में बीते पांच साल के दौरान लगातार बढ़ोतरी हुई है. मौजूदा साल यह करीब 1.2 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गई. पिछले खरीफ के मौसम में ही बढ़ती कीमतों से राहत देने के लिए जून 2021 में उर्वरकों पर सब्सिडी में 14,775 करोड़ रुपए का इजाफा हुआ. मौजूदा रबी सीजन में और 25,000 करोड़ रुपए खर्च करने पड़ सकते हैं.

मध्य प्रदेश में किसानों को आसानी से मिलने वाली दूसरी खाद एनपीके मिश्रित खाद को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है. लेकिन एनपीके की कीमत थोड़ी ज्यादा पड़ती है, इसलिए किसान अपने पुराने भरोसेमंद डीएपी को ही चुनते हैं. मगर कोई चारा नहीं होने की वजह से किसान एनपीके को अपना रहे हैं.

भारत इस साल आयात में कटौती की योजना बना रहा था, क्योंकि देश के दक्षिणी और पूर्वी हिस्सों के उर्वरक कारखानों की क्षमता बढ़ाई जा रही है. पारादीप फॉस्फेट लिमिटेड तथा मंगलौर केमिकल और फर्टिलाइजर में 'मेक इन इंडिया' रणनीति के तहत उत्पादन क्षमता में 4 लाख टन की बढ़ोतरी होने की उम्मीद है. मगर क्षमता बढ़ाने में देरी, उर्वरकों की अंतरराष्ट्रीय कीमतों में तेजी और वैश्विक कमी की वजह से भारत के खेत संकट से दोचार हैं. और यह राजनैतिक मुद्दा भी बन सकता है.

—साथ में **अनिलेश एस. महाजन**

हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट बोर्ड परीक्षा वर्ष 2021
विकासखण्ड स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली मेधावी
स्मार्ट फोन वितरण कार्यक्रम”
मुख्य अतिथि
श्रीमती रेखा आर्या
मा० कैबिनेट मंत्री

उत्तराखंड

को सच्चे अर्थों में देवभूमि बनाने के संकल्प के साथ आगे बढ़ती सरकार, एक युवा विचार और सोच से लबरेज सरकार का एक पथ- प्रदर्शक मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस बार राज्य के इक्कीसवें स्थापना दिवस को एक हफ्ते तक पूरे राज्य में मनाने का कार्यक्रम तय करवाकर पूरे राज्य तक नये राज्य गठन के इक्कीस साल की खुशियों को राज्य की आम जनता तक पहुंचाने की ठान ली। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी को विशेष रूप से याद किया। उन्होंने ही प्रधानमंत्री रहते हुए राज्य निर्माण के साथ राज्य में विशेष औद्योगिक विकास की मजबूत नींव रखी थी।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि उत्तराखंड राज्य धरती का देवलोक है, इसकी महिमा का गुणगान ‘‘ऋग्वेद’’ ने भी किया जबकि, ‘‘स्कन्द पुराण’’ में बाकायदा इसका वर्णन है। अभिज्ञान शाकुन्तलम् की रचना यहीं की गयी। राज्य की इसी पृष्ठभूमि का ध्यान रखकर इससे सामंजस्य बैठाते हुए उत्तराखंड सरकार इस प्रदेश को विकास के रास्ते पर आगे बढ़ा रही है। राज्य में ऐसे बहुत से काम हुए हैं, जो पहले नामुमकिन लगते थे। पिछले पांच वर्षों में केन्द्र सरकार द्वारा करीब एक लाख करोड़ रूपये से अधिक की विभिन्न परियोजनाएं प्रदेश के लिये स्वीकृत करते ही यह संभव हुए है। इनमें से बहुत सी योजनाएं पूर्ण हो चुकी है और अन्य पर द्रुत गति से कार्य चल रहा है।उत्तराखंड प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के प्रयासों से हमारी अर्थव्यवस्था में क्रांतिकारी परिवर्तन आने वाला है ।

उत्तराखण्ड राज्य निर्माण के सभी अमर शहीदों व आंदोलनकारियों को श्रद्धापूर्वक नमन करते हुए मुख्यमंत्री ने भारत माता के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर जवानों को भी राज्य के 21वें स्थापना दिवस पर नमन किया। प्रदेश में अक्टूबर माह में आई आपदा में जिन लोगों की जानें गई, उनके प्रति मुख्यमंत्री अपनी अपनी संवेदना प्रकट करना नहीं भूले। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रदेश सरकार आपदा प्रभावितों की सहायता के लिए हर पल तत्पर है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा हर पीड़ित के आंसू पोंछने और एक बार फिर सामान्य जीवन शुरू करने के लिए सरकार ने आपदा प्रभावितों को दी जाने वाली सहायता राशि को बढ़ाया है।

सरकार की मजबूत इच्छाशक्ति, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उत्तराखंड के प्रति विशेष लगाव और केंद्र सरकार के सहयोग से उत्तराखंड तेजी से विकास की ओर अग्रसर है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और केंद्र सरकार के सहयोग से गतिमान इन निर्माणाधीन परियोजनाओं में 16,216 करोड़ रूपए की लागत वाली 125 किमी लम्बी ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल परियोजना को 2024-25 तक पूरा करने की तैयारी है। इसके अलावा टनकपुर बागेश्वर और डोइवाला से गंगोत्री - यमुनोत्री रेललाइन के सर्वे की सहमति देते हुए इसके लिए बजट भी स्वीकृत हुआ है। हरिद्वार- देहरादून रेल-लाइन के दोहरीकरण का कार्य पूरा होने जा रहा है।

इस सबके अलावा केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री की सड़क कनेक्टिविटी

में सुधार के लिए 889 किलोमीटर की चारधाम सड़क परियोजना का काम भी तेजी से प्रगति पर है।

राज्य में हवाई सेवाओं को विस्तार देने के लिए जौलीग्रांट एयरपोर्ट को अंतरराष्ट्रीय स्तर का बनाने का काम जारी है। कुमाऊं मंडल के उधमसिंह नगर में ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट निर्माणाधीन है। उत्तराखण्ड उड़ान योजना में हेली सर्विस शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया है। पिछले कुछ वर्षों में एयर कनेक्टिविटी को बहुत मजबूती मिली है।

आगामी दिनों में शीघ्र ही सिखों के प्रमुख तीर्थ और उत्तराखंड के पांचवे धाम के रूप में प्रख्यात हेमकुंड साहिब को रोपवे से जोड़ने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रस्तावित योजना साकार रूप लेने वाली है। केदारनाथ तक भी केबल कार चलाकर पर्यटन के क्षेत्र में सरकार युगांतकारी परिवर्तन की शुरुआत करने का खाका तैयार कर चुकी है। सरकार के भगीरथ प्रयासों से उत्तराखण्ड में अनेक उच्च स्तरीय संस्थाएं भी लाई गई हैं। इनमें देश का ड्रोन एप्लीकेशन सेंटर, सीपेट कोस्ट गार्ड भर्ती सेंटर, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी , सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑफ नेचुरल फाइबर जैसी संस्थाओं को शुमार किया जा सकता है। देहरादून में स्मार्ट सिटी परियोजना, उत्तराखण्ड वाटर मैनेजमेंट प्रोजेक्ट और जमरानी बहुउद्देशीय परियोजना, भारत नेट फेज-2 परियोजना सहित अन्य बहुत सी परियोजनाएं डबल इंजन की सरकार के चलते ही यहां प्रगति पर है।

उत्तराखंड के इस सरकार का युवाओं के लिए समर्पण प्रदेश में गतिमान 24 हजार सरकारी पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू किये जाने से भी झलकता है। इन भर्ती परीक्षाओं में आवेदन शुल्क माफ कर दिया गया है। यही नहीं समूह ‘‘ख’’ व ‘‘ग’’ के पदों पर चयन में अभ्यर्थियों को आयु सीमा में एक वर्ष की छूट भी दे दी गई है। संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षों, ‘‘एन.डी.ए’’., ‘‘सी.डी.एस’’. जैसी रक्षा सेवाओं और उनके ही समकक्ष अन्य सेवाओं की लिखित परीक्षा पास करने पर परिवार की आर्थिक स्थिति के आधार पर अभ्यर्थी को साक्षात्कार की तैयारी के लिये 50 हजार रुपए की वित्तीय सहायता दी जा रही है। प्रदेश के विभिन्न विभागों को स्वरोजगार के टाइम बाउंड लक्ष्य दिये गये हैं। आवेदकों की सुविधा के लिए विभिन्न स्थानों पर ऋण उपलब्ध कराने के लिए कैम्प लगाकर एक ही स्थान पर सारी औपचारिकताएं पूरी की जा रही हैं। ऑनलाइन पढ़ाई को और सुगम बनाने के लिए राज्य के सरकारी स्कूलों के कक्षा 10वीं और 12वीं के छात्र छात्राओं और गवर्नमेंट डिग्री कॉलेजों के छात्रों को टैबलेट उपलब्ध कराने की तैयारी है।

उत्तराखंड के सरकारी विद्यालयों में क्वालिटी एजुकेशन के लिए सभी सरकारी विद्यालयों में एन.सी.ई.आर.टी. की पाठ्य पुस्तकें अनिवार्य रूप से लागू करवा दी गयी हैं। कॉलेजों को स्मार्ट कैम्पस बनाने और बच्चों को पर्यावरण के प्रति जागरूक करने के लिए माध्यमिक विद्यालयों में स्मार्ट ईको क्लब की स्थापना हो रही है। प्रधानमंत्री की प्रेरणा से दुनिया का सबसे बड़ा कोविड वैक्सीनेशन अभियान ‘‘सबको वैक्सीन मुफ्त वैक्सीन’’ के लक्ष की तरफ प्रदेश द्रुत गति से आगे बढ़ रहा है। हाल ही में देश में 100 करोड़ डोज का महत्वपूर्ण लक्ष्य हासिल करने में भी राज्य ने अपना योगदान किया है। प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन से ही उत्तराखण्ड पूर्ण रूप से कोविड-19 वैक्सीन की प्रथम डोज लगाये जाने वाला राज्य बन चूका है। शत-प्रतिशत दूसरो डोज का लक्ष्य भी जल्द से जल्द पूरा हो इसका पूरा प्रयास सरकार कर रही है। कोविड- 19 की पहली और दूसरी लहर में कोविड-वारियर्स द्वारा किये गये सराहनीय कार्य के लिए उनको प्रोत्साहन व सम्मान राशि प्रदान कर सरकार ने उनके मनोबल को बढ़ाने का काम किया है। विपरीत परिस्थितियों के बावजूद कोविड से प्रभावित लोगों को राहत पहुंचाने की पूरी कोशिश सरकार ने की है।

> **“ उत्तराखंड राज्य को सबका साथ, सबका विकास एवं सबका विश्वास की भावना के अनुरूप देश के अग्रणीय राज्यों के रूप में पहचान दिलाने का संकल्प व्यक्त करते हुए हमारी सरकार युवावस्था में प्रवेश कर चुके उत्तराखंड की सभी युवा आकांक्षाओं को पूर्ण करने की प्रतिबद्धता व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के विजन के अनुरूप राज्य स्थापना की रजत जयंती वर्ष 2025 तक उत्तराखंड को भारत का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने की ओर अग्रसर है।**
>
> *— पुष्कर सिंह धामी,*
> *मुख्यमंत्री उत्तराखंड*

प्रदेश में कोविड-19 से प्रभावित पर्यटन, परिवहन व संस्कृति क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए लगभग 200 करोड़, चिकित्सा क्षेत्र के लिए 205 करोड़ जबकि महिला स्वयं सहायता समूहों और राज्य सरकार की स्वरोजगार योजनाओं से जुड़े लाभार्थियों को 118 करोड़ रुपए का कोविड राहत पैकेज की राशि लाभार्थियों के खातों में डीबीटी द्वारा पहुंचनी शुरू हो गई है। कोविड से प्रभावित परिवारों के निराश्रित बच्चों को वात्सल्य योजना का सहारा दिया जा रहा है। ऐसे बच्चों को 21 वर्ष की आयु तक 3000 रुपये प्रति माह दिये जायेंगे। राज्य सरकार इन बच्चों का एक अभिभावक की तरह पूरा संरक्षण कर रही है। पिछले वर्षों में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में कई गुना बढ़ोतरी की गई है। प्रत्येक जिले में ऑक्सीजन प्लांट शुरू हुए हैं। राज्य में

निशुल्क जांच योजना के तहत मरीजों को 207 प्रकार की पैथोलॉजिकल जांच की निःशुल्क सुविधा प्रदान की गयी है।

आयुष्मान उत्तराखंड योजना में 44 लाख लोगों के आयुष्मान कार्ड बनाए जा चुके हैं। इसके अंतर्गत अब तक 3 लाख 40 हजार से अधिक मरीज मुफ्त में उपचार करा चुके है। योजना के अंतर्गत लाभार्थियों के उपचार पर अब तक 461 करोड़ अधिक का कार्मिक व्यय किया जा चुका है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘‘बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ’’ अभियान को आगे बढ़ाते हुए मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना की शुरुआत प्रदेश में भी की गयी है। इसके तहत प्रथम दो बालिकाओं के जन्म पर माता और नवजात कन्या शिशु को मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट उपलब्ध कराई जा रही है।

आंगनबाड़ी बहनों के मानदेय में बढ़ोतरी करने के अलावा प्रदेश के लोक कलाकारों का मानदेय दोगुना किया है। वृद्धावस्था, विधवा और दिव्यांगजन पेंशन की राशि को एक हजार रूपए प्रतिमाह से बढ़ाकर बारह सौ रुपए प्रतिमाह किया गया है। ग्राम प्रहरियों का मानदेय रूपए 2 हजार प्रतिमाह किया गया है। अन्त्योदय की भावना के अनुरूप विकास का लाभ, अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए सरकार प्रयासरत रही है। लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ आसानी से मिल सके और उनकी समस्याओं का समाधान हो, इसके लिए सरलीकरण, समाधान, निस्तारण व संतुष्टि पर खास तौर पर फोकस किया गया है। ई-कैबिनेट, ई-ऑफिस, सीएम डैशबोर्ड उत्कर्ष, सीएम हेल्पलाइन 1905, सेवा का अधिकार और ट्रांसफर एक्ट की पारदर्शी व्यवस्था के चलते सरकार कार्य संस्कृति में गुणात्मक सुधार दिखाई देने लगा है।

सरकार मजबूत इच्छाशक्ति शहीद राज्य आंदोलनकारियों के सपनों को पूरा करने के लिए लिए गये हर जरूरी निर्णय और दृढ़ता से इसे लागू करने से साफ दिखती है। राज्य निर्माण आन्दोलन के शुरुआती दौर से ही गैरसैंण को राजधानी बनाये जाने की जो संकल्पना हर आंदोलनकारी के मन में रही। उसी का सम्मान करते हुए जनभावनाओं को सर्वोच्च सम्मान देते हुए सरकार ने गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया। इसी के तहत गैरसैण में राजधानी के अनुरूप आवश्यक सुविधाओं के विकास की कार्ययोजना पर काम किया जा रहा है।

सरकार का पूरा कार्यकाल दूरस्थ और पिछड़े क्षेत्रों के विकास को समर्पित रहा है। यह पहली सरकार है जिसने पलायन को गंभीरता से लिया और रिवर्स पलायन को साकार करने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए।

पर्वतीय क्षेत्रों में निवेश के लिए पर्यटन, आयुष व वेलनेस आईटी, सौर ऊर्जा सहित सर्विस सेक्टर पर विशेष फोकस किया गया है।

सरकार द्वारा एम.एस.एम.ई. के केंद्र में पर्वतीय क्षेत्रों को भी शामिल रखा गया है। सीमांत तहसीलों के लिए मुख्यमंत्री सीमांत क्षेत्र विकास योजना शुरू की गयी है। प्रदेश के सभी न्याय पंचायतों में क्लस्टर आधारित एप्रोच पर ग्रोथ सेंटर बनाए जा रहे हैं। वोकल फॉर लोकल पर आधारित ‘‘एक जनपद दो उत्पाद’’ योजना से स्थानीय लोगों के लिए स्वरोजगार के अवसर पैदा हो सके , और स्थानीय उत्पादों को विश्वस्तरीय पहचान मिल सके इसके भी प्रयास किये गये हैं।

राज्य में होम स्टे योजना से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मिल रही मजबूती का उल्लेख प्रधानमंत्री भी अपने उद्बोधन में कर चुके हैं। राज्य भर में 16 ईको टूरिज्म डेस्टिनेशन विकसित किए जा रहे हैं। ट्रैकिंग मार्गों पर भी होम स्टे को विशेष प्रोत्साहन दिया जा रहा हैं। साहसिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इसकी अलग से विंग गठित की गई है। सौर ऊर्जा और पिरूल ऊर्जा नीति, ग्रामीण युवाओं की आजीविका को बढावा देने में सहायक साबित हो रही है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सरकार का मूलमंत्र बनकर उभरा है।

सरकार के इसी प्रयास का प्रतिफल है कि आजादी के बाद से अभी तक अंधेरे में रह रहे 94 गांवों में बिजली पहुंचाई गई। सौभाग्य योजना में 2 लाख 50 हजार से अधिक घरों को रोशन किया गया। प्रधानमंत्री जल शक्ति अभियान के तहत केंद्र के सहयोग से हर घर नल से जल के लक्ष्य को हासिल करने के लिए सरकार संकल्पबद्ध हैं। हर घर को नल से जल योजना में ग्रामीण क्षेत्रों में केवल 1 रुपए पर पानी का कनेक्शन दिया जा रहा है।

राज्य में नदियों व जलस्त्रोतों को पुनर्जीवित करने की पहल बड़े स्तर पर की जा रही है। हर जिले में एक वाटरशेड विकसित करने के लक्ष्य को लेकर काम किया जा रहा है। आम लोगों की भी इसमें बढ़-चढ़कर हिस्सेदारी इसकी प्रामाणिकता को दर्शाती है। पहली बार प्रदेश में सरकार ने जल नीति को मंजूरी दी है। प्रत्येक जिले में वर्षा जल संचयन के लिए झीलें विकसित की जा रही हैं। इससे पेयजल की उपलब्धता के साथ वाटर स्पोर्ट्स की गतिविधियां भी बढ़ेंगी।

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से प्रदेश के लगभग 9 लाख किसान लाभान्वित हो चुके हैं। सरकार किसानों को तीन लाख रुपए और महिला स्वयं सहायता समूहों को पांच लाख रुपए तक का ऋण बिना ब्याज के उपलब्ध करा रही है। प्रदेश में जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए 3900 जैविक क्लस्टरों में काम शुरू किया गया है। किसानों को कृषि उपकरण उपलब्ध कराने को ‘‘फार्म

मशीनरी बैंक'' योजना शुरू की गयी है। इसके लिए 80 फीसदी तक सब्सिडी उपलब्ध कराई जा रही है।

उत्तराखंड देवभूमि ही नहीं, वीरभूमि भी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड को सैन्य धाम की संज्ञा दी है।

सरकार शहीद सैनिकों परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी में समायोजित कर रही है। विशिष्ट सेवा पदक से अलंकृत सैनिकों को अनुमन्य राशि में कई गुना बढ़ोतरी की गई है। पिछले लगभग साढ़े चार वर्षों में उत्तराखंड ने विभिन्न क्षेत्रों में बेहतरीन प्रदर्शन कई तरह से साबित हुआ है। राष्ट्रीय फलक पर उत्तराखण्ड अपनी पहचान बनाने में कामयाब रहा है। सतत विकास लक्ष्य सूचकांक में वर्ष 2018 में राज्य 10वें स्थान पर था जबकि और आज तीसरा स्थान राज्य को प्राप्त हो गया है। ऊर्जा और कानून व्यवस्था संबंधी इंडेक्स में राज्य प्रथम स्थान पर है। मातृत्व मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर बाल मृत्यु दर आदि स्वास्थ्य सूचकों में भी काफी सुधार हुआ है। तमाम सामाजिक-आर्थिक सूचकांक में प्रदेश देश के अग्रणी राज्यों में शामिल है। प्रधानमंत्री की अपेक्षा के अनुसार वर्ष 2025 तक जब उत्तराखंड अपनी स्थापना का रजत जयंती वर्ष मनाए, तब प्रदेश देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बने इसके लिए सरकार संकल्पबद्ध है, और इसके लिए ''विकल्प रहित संकल्प के मंत्र को ध्यान में रखकर दिन-रात कार्य कर रही हैं। जिसके द्वारा हम अन्त्योदय के अपने अंतिम लक्ष्य को प्राप्त कर सकें और उत्तराखंड को सच्चे अर्थों में देवभूमि बना सकें।

राज्य स्थापना दिवस पर मुख्यमंत्री ने भराडीसैंण में भी राज्य के उत्थान के लिए अठारह घोषणाएं की। मुख्यमंत्री के अनुसार उत्तराखण्ड राज्य आंदोलनकारियों, जिनको रु. 3100.00 पेंशन प्राप्त हो रही है, को बढ़ाकर रु. 4500.00 तथा जिनको रु. 5000.00 पेंशन प्राप्त हो रही है, को बढ़ाकर रु. 6000.00 किया जायेगा। राज्य के प्रत्येक जनपद मुख्यालय पर अध्ययनरत छात्राओं के शिक्षा को सुगम एवं सुविधा युक्त एक-एक महिला छात्रावास का निर्माण करने की भी घोषणा की गयी। मुख्यमंत्री के अनुसार राज्य में कामकाजी महिलाओं की आवश्यकतानुसार जनपद मुख्यालयों पर कामकाजी महिला छात्रावास का निर्माण किया जायेगा।

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से प्रदेश के लगभग 9 लाख किसान लाभान्वित हो चुके हैं। सरकार किसानों को तीन लाख रुपए और महिला स्वयं सहायता समूहों को पांच लाख रुपए तक का ऋण बिना ब्याज के उपलब्ध करा रही है। प्रदेश में जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए 3900 जैविक क्लस्टरों में काम शुरू किया गया है। किसानों को कृषि उपकरण उपलब्ध कराने को ''फार्म मशीनरी बैंक'' योजना शुरू की गयी है। इसके लिए 80 फीसदी तक सब्सिडी उपलब्ध कराई जा रही है।

मुख्यमंत्री ने यह भी घोषणा की कि सरकारी अस्पतालों में जच्चा-बच्चा के सुरक्षित स्वास्थ्य हेतु अस्पतालों में 48 घण्टे रुकने वाली प्रसूता महिला को रु. 2000.00 उपहार धनराशि भेंट की जायेगी। जी रैया चेली-जागी रैया नौनी योजना शुरू करने के तहत 11 से 18 आयु वर्ग की किशोरियों को टीएचआर सुविधा प्रदान की जायेगी।

मुख्यमंत्री के अनुसार 11 से 18 आयु वर्ग की किशोरियों को सेनेटरी नैपकीन उपलब्ध कराने हेतु आंगनबाड़ी केन्द्रों में सेनेटरी नैपकीन वेण्डिंग मशीन की स्थापना की जायेगी। 11 से 18 आयु वर्ग की किशोरियों के बेहतर स्वास्थ्य परीक्षण तथा हीमोग्लोबिन इत्यादि की जांच निशुल्क की जाएगी तथा हेल्प लाईन नं 104 के माध्यम से निःशुल्क चिकित्सीय परामर्श भी उपलब्ध कराया जायेगा। आरोग्य उत्तराखण्ड क्रॉनिक डिजीज (दीर्घकालिक एवं पुरानी बीमारियों) के उपचार में ली जाने वाली दवाइयों को निःशुल्क उपलब्ध कराया जायेगा। देहरादून एवं हल्द्वानी में नशा मुक्ति केंद्र की स्थापना की जायेगी। राज्य में स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन डेवलपमेंट की स्थापना की जायेगी। कोविड-19 में सराहनीय कार्य के दृष्टिगत एनएचएम के कर्मियों को रु. 10,000- को एकमुश्त प्रोत्साहन धनराशि प्रदान की जाएगी। राज्य के युवाओं को देश से बाहर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाने हेतु राज्य में विदेश रोजगार प्रकोष्ठ का गठन किया जाएगा। ई-डिस्ट्रिक्ट के माध्यम से संचालित 32 सेवाओं को इसमें शामिल करते हुए कुल 75 सेवाओं को ''अपणि सरकार पोर्टल'' के माध्यम से आम जनमानस को लाभ पहुंचाया जाएगा। सेवा का अधिकार अधिनियम में अधिसूचित अवशेष 190 सेवाओं को भी शीघ्र ही ''अपणि सरकार पोर्टल'' के माध्यम से संचालित कर आम जनमानस को लाभ पहुंचाया जाएगा। प्रदेश में खेल को प्रोत्साहित करने तथा युवाओं को खेल की विभिन्न विधाओं से जोड़ने के लिए ''खेल नीति-2021'' तुरन्त लागू की जाएगी। उत्तराखंड में स्वास्थ्य, पर्यटन से राज्य की आर्थिकी को बढ़ाने हेतु राज्य को आयुष वेलनैस का हब बनाया जाएगा। जिसके अन्तर्गत गढ़वाल मंडल विकास निगम एवं कुमाऊं मंडल विकास निगम के पर्यटक गृहों में आयुष वेलनैस सेन्टर खोले जाएंगे। भराड़ीसैंण विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत अंतरराष्ट्रीय प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान बनाया जाएगा। गैरसैण नगर पंचायत की विभिन्न समस्याओं के निदान के लिए 1.20 करो की स्वीकृति की घोषणा मुख्यमंत्री ने की। आदिबद्री और घाट क्षेत्र को नगर पंचायत बनाया जाएगा। नारायणबगड़ ब्लाक में एलोपैथिक अस्पताल का उच्चीकरण किया जाएगा।

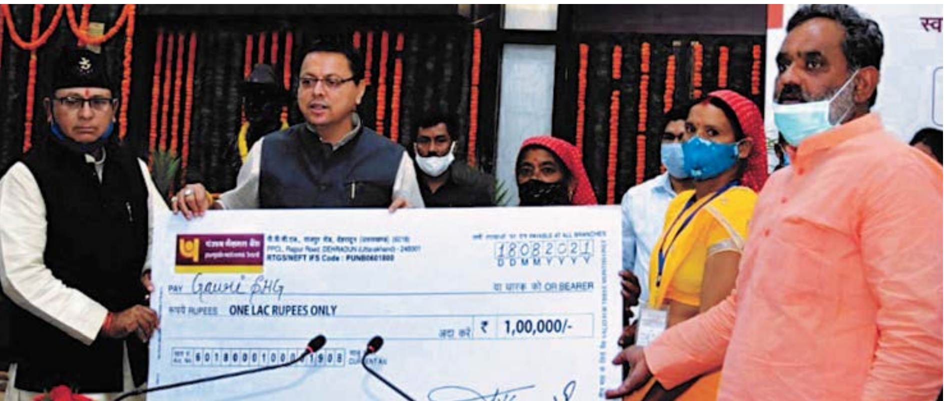

पश्चिम बंगाल

क्यों इतना अहम है देवचा पचमी कोल ब्लॉक?

रोमिता दत्ता

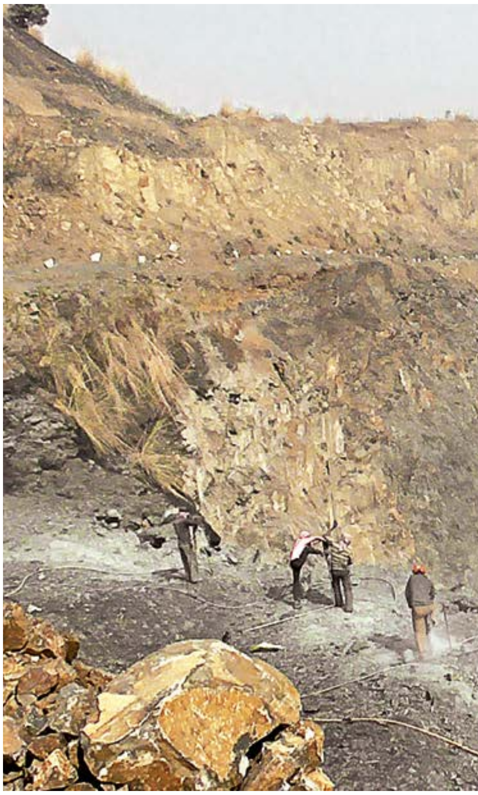
सुबीर हलदर

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के लिए देवचा पचमी कोयला खनन परियोजना अब तक की सबसे बड़ी चुनौती होगी. इस परियोजना में काफी वन इलाकों और 12 आदिवासी गांवों सहित हजारों एकड़ भूमि का अधिग्रहण शामिल है. बंगाल में कोई भी यह बात नहीं भूला है कि 14 साल पहले, ममता सिंगूर में वाम मोर्चा सरकार की भूमि अधिग्रहण नीति के खिलाफ आंदोलन की अगुवाई कर रही थीं, जिसके कारण टाटा समूह को अपनी कार परियोजना के लिए बंगाल छोड़ना पड़ा और राज्य पर उद्योगों के लिए 'गैर-दोस्ताना' सूबे का टैग चस्पां हो गया जो अभी तक जारी है. उस आंदोलन की वजह से ही माकपा सरकार 2011 में विधानसभा चुनाव हार गई और ममता के हाथ में सत्ता आई थी.

एक दशक के बाद, तृणमूल कांग्रेस की मुखिया खुद अब हॉट सीट पर हैं और वह इसके लिए कटबिद्ध हैं कि सिंगूर सरीखा प्रकरण इस बार न हो. किसी भी बड़े निवेश के लिए अधिक भूमि की जरूरत होती है और उसके साथ समस्याएं भी जुड़ी होती हैं. लेकिन वक्त को देखते हुए—परियोजना की घोषणा के दो साल बाद—मुख्यमंत्री ने आम सहमति बनाने तथा भूमि और आजीविका खोने वालों के लिए मुआवजा देने पर जोर दिया है. ऐसे में लग रहा है कि यह खनन परियोजना हकीकत बन सकती है. ममता ने यह भी सुनिश्चित किया है कि देवचा पचमी पर सरकारी अधिसूचना में कहीं भी 'अधिग्रहण' शब्द का उल्लेख नहीं हो. वे जोर देकर कहती हैं कि सरकार मालिकों से और उनकी सहमति से जमीन की सीधी खरीद के लिए जा रही है.

माना जा रहा है कि देवचा पचमी दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कोयला ब्लॉक है जिसमें 900 से 2,500 मीटर की गहराई तक करीब 2.1 अरब टन कोयला भंडार मौजूद है. इसको पहले संयुक्त रूप से पश्चिम बंगाल, पांच अन्य राज्यों और सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड को ऑफर किया गया था. भूगर्भीय चुनौतियों और लागत को देखते हुए बाकी हितधारकों ने इससे हाथ खींच लिए. राज्य की ऊर्जा एजेंसी, पश्चिम बंगाल पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (डब्ल्यूबीपीडीसीएल) को इसका एकाधिकार 2019 में मिल गया. विशेषज्ञों के एक सर्वे का अनुमान है कि खनन शुरू होने के बाद सीम (कोयले के स्तर) तक पहुंचने में कम से कम तीन साल लगेंगे. यहां तक कि खनन के लिए केंद्र के एकाधिकार वाली कंपनी कोल इंडिया लिमिटेड (सीआइएल), जिसके पास पहले यह ब्लॉक था, को भी इस खदान की क्षमता को लेकर संदेह है. सीआइएल के पूर्व चेयरमैन पार्थ एस. भट्टाचार्य ने 2019 में ध्यान दिलाया था कि भारत के पास अभी वह तकनीक नहीं है कि वह बैसाल्ट चट्टानों की मोटी परत के नीचे मौजूद भंडार का खनन कर सके और इस खनन के मलबे को हटाने की लागत बढ़ती जाएगी अगर इस परियोजना को टुकड़ो में लागू किया गया, जैसा कि सरकार ने अपने पास के 550 एकड़ की जमीन पर करने का प्रस्ताव रखा था. लेकिन ममता को भरोसा है कि देवचा पचमी राज्य की अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाई देगा, खासतौर पर तब जब इस संभावित भंडार का खनन अगली एक सदी तक किया जा सकता है और इससे 1,50,000 स्थानीय रोजगार सृजित किए जा सकेंगे.

11,000
एकड़
भूमि का अधिग्रहण किया जाना है, सरकार फिलहाल 3,500 एकड़ पर ध्यान दे रही है

21,000
लोग अपनी कृषि भूमि या मकान खो देंगे

10,000
करोड़ रु.
के मुआवजा पैकेज की योजना पश्चिम बंगाल सरकार ने बनाई है

जमीनी काम

हालांकि कोयला ब्लॉक बीरभूम जिले में 11,000 एकड़ में फैला हुआ है, पर सरकार 3,500 एकड़ पर ध्यान केंद्रित कर रही है, जिसमें पांच ग्राम पंचायतें और देवांगुनजे-हरिसिंघा, देवचा पचमी और चंदा मौजा ब्लॉक में 12 आदिवासी गांव शामिल हैं. यहां करीब 21,000 लोगों के पास कृषि भूमि और घर हैं. फिर पत्थर की खानें हैं जिन पर कई स्थानीय लोग आजीविका के लिए निर्भर हैं.

प्रभावित लोगों में अधिकतर आदिवासी हैं और उनके बीच विरोध न भड़के, सरकार इसको लेकर सतर्क रही है. उन्हें मनाने के लिए प्रशासनिक, राजनैतिक और सामाजिक-सांस्कृतिक स्तर पर कई रणनीतियां अपनाई

गहरी खुदाई
बीरभूम जिले में देवचा पचमी ब्लॉक में एक कोल पिट की फाइल फोटो

गई हैं. जिला मजिस्ट्रेट (डीएम) बिधान रे की अगुआई में स्थानीय मोहम्मद बाजार जिला प्रशासन ने परियोजना के बारे में लोगों की बात सुनने के लिए गांवों का दौरा किया. अधिकारियों का कहना है कि एसडीओ (अनुमंडल पदाधिकारी) और बीडीओ (प्रखंड विकास पदाधिकारी) ने भी लोगों की चिंताओं को दूर करने के लिए नियमित बातचीत की है.

परियोजना के केंद्र मोहम्मद बाजार के बीडीओ अर्घ्य गुहा कहते हैं, ''मुझे याद है कि कैसे स्थानीय लोग अपने भूखंड के आकार जैसी बुनियादी चीजों के बारे में जानकारी साझा करने से डरते थे, चाहे वे मालिक हों या बटाईदार, वे सामाजिक प्रभाव आकलन पर सर्वेक्षण के लिए मुर्गी या बकरी आदि रखते थे. आखिरकार, हम उनके डर को दूर करने के लिए घर-घर गए. लोगों को यह समझाने के लिए सर्वेक्षण प्रारूप को सरल बनाया गया था कि यह उनके अपने भले के लिए था.'' सर्वेक्षण को आखिरकार 2020 के अंत में तीन महीने में पूरा किया गया.

मुआवजे के योग्य लोगों के लिए 10,000 करोड़ रुपए का मुआवजा पैकेज है जिसमें पुलिस में उनकी कॉन्स्टेबल की नौकरी, एक कॉलोनी में 600 वर्ग फुट का भूखंड, मकान शिफ्ट करने की लागत और इस दौरान बेरोजगार हुए लोगों को नई नौकरी मिलने तक भत्ता देने का भी प्रावधान है. इसके अलावा, उनको जमीन के लिए बाजार मूल्य से दोगुनी कीमत दी जाएगी (एक बीघे, जो एक एकड़ से थोड़ा कम होता है, के लिए 10 से 13 लाख रुपए). मुआवजे के पैकेज के बाबत अलचिकी (संथाली) लिपि में पर्चे भी बांटे जा रहे हैं. नाम न छापने की शर्त पर एक अधिकारी कहते हैं, ''हमने किसी राजनैतिक दल को इससे खेलने की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी है.''

ब्यौरों को सार्वजनिक करने से पहले, प्रशासन ने भूमि अभिलेखों को अपडेट करने के लिए शिविरों का आयोजन किया. गुहा कहते हैं, ''यह असली मालिकों की पहचान करने के लिए था; कई मामलों में मृतक के नाम अभी भी फाइल में थे. मुआवजे की राशि और पैकेज की योजना दीर्घकालिक प्रभाव के लिए बनाई गई है.''

आसान नहीं राह

सरकार ने किसी भी भ्रम को दूर करने के लिए व्यक्तियों तक पहुंचने से पहले, आदिवासी अधिकारों के लिए लड़ने वाले मंच बीरभूम आदिवासी गांओंता (बीएजी) के आदिवासी नेताओं से संपर्क किया. इसके लिए दो प्रमुख स्थानीय नेताओं और पूर्व नक्सलियों, सुनील और रबिन सोरेन को शामिल किया गया था. रबिन अब टीएमसी समर्थक है और उसने कथित तौर पर इस सौदे से पैसा भी कमाया है, जबकि सुनील एक आपराधिक मामले में गिरफ्तार होने के बाद कम दिखने लगा है.

इस बीच, आदिवासी अपनी चिंताओं को जाहिर करने के लिए एक नेता की तलाश में हैं. कोयला ब्लॉक के एक हिस्से हरिसिंघा के स्थानीय निवासी सुनील मुर्मू कहते हैं, ''आदिवासी युवाओं को लुभाने के लिए भारी रकम खर्च की जा रही है, इसलिए सौदे से नाखुश होने पर भी लोगों के विरोध की संभावना नहीं है.'' वहीं, सुनील सोरेन कहते हैं कि आदिवासी ''खनन के खिलाफ नहीं हैं. यह स्थानीय लोगों को रोजगार देगा और उनकी आजीविका सुनिश्चित करेगा, पर प्रशासन को लोगों की प्रतिक्रिया जानने के लिए उनके साथ बैठने की जरूरत है.'' राज्य ने पैकेज पर किसी भी मतभेद को दूर करने के लिए स्थानीय आदिवासियों, मशहूर हस्तियों, गैर-सरकारी संगठनों के सदस्यों और जनप्रतिनिधियों को मिलाकर नौ सदस्यीय समिति गठित की है.

ममता सरकार की सबसे बड़ी चिंता कुछ स्थानीय मुद्दों के उठ खड़े होने की है, और भाजपा या वामपंथी इस परियोजना के विरोध की सवारी करने की कोशिशों में जुटे हैं. हरिसिंघा के करीब 2,000 लोग जिनमें 80 फीसद जनजातीय समुदाय के हैं, पहले ही इस इलाके में विकास की कमी को लेकर शिकायतें कर रहे हैं. एक स्थानीय कालिंदी हांसदा कहती हैं, ''यहां से आठ किमी तक कोई स्कूल या 3-4 किमी तक गाड़ी चलने लायक सड़कें नहीं हैं. पास में कोई स्वास्थ्य केंद्र भी नहीं है. अब जबकि हमारे गांवों में कोयला भंडार है, प्रशासन हमारे दरवाजे पर आ रहा है. कुछ काम कराने के लिए यह हमारा आखिरी मौका है.''

राज्य की नौ सदस्यीय समिति के सदस्य सुनील मुर्मू का कहना है कि पुनर्वास पैकेज के बारे में विवरण अभी भी अस्पष्ट है. आदिवासी अधिकार मंच के सुशील धांगरे पूछते हैं, ''सरकारी पैकेज में जमीन खोने वाले किसी परिवार के एक सदस्य के लिए नौकरी का वादा है. लेकिन परिवार में अगर तीन बेटे हों तो क्या होगा?'' सरकार ने स्टोन क्रशिंग इकाइयों में 3,000 मजदूरों को एक साल के लिए 10,000 रुपए और 160 खेत मजदूरों को 50,000 रुपए का एकमुश्त अनुदान देने का वादा किया है. यह ऐसे लोग हैं जिनका रोजगार चला जाएगा (स्थानीय लोगों का कहना है कि इस इलाके में लगभग 2,00,000 असंगठित कामगार हैं.) यहां भी भेदभाव साफ है: स्टोन क्रशिंग इकाइयों के मालिकों को एकमुश्त 50,000 रुपए का अनुदान, पास के औद्योगिक पार्क में जगह और छह महीने के लिए कच्चे माल की मुफ्त आपूर्ति मिलेगी. परियोजना स्थल के भीतर 300 से अधिक एकड़ में फैले जंगलों से उपज पर निर्भर 1,000 लोगों के भविष्य के बारे में भी कोई स्पष्टता नहीं है. ■

दिल्ली सरकार का नया टूरिज्म ऐप

दिल्ली आपकी उंगलियों पर

Delhi Tourism

देखो मेरी दिल्ली | Dekho Meri Dilli

पूरी दिल्ली को एक जगह समेटना बहुत मुश्किल है. चांदनी चौक की चहल-पहल भरी गलियों से लेकर लुटियंस दिल्ली के खूबसूरत छायादार रास्तों तक, यह शहर अलग-अलग विभिन्न संस्कृतियों का शानदार मेल नजर आता है. कुछ मामलों में दिल्ली में सफर करना इतिहास का दर्शन करने जैसा है. यह शहर सदियों के दौरान विकसित होकर अपने मौजूदा स्वरूप में पहुंचा है, दर्शकों को इसके गौरवपूर्ण इतिहास की झलकियां देखने को मिलती हैं. भले आप पहली बार देख रहे हैं, बार-बार उन इलाकों से गुजरते हैं, या स्थानीय दिल्लीवाले हैं, इस शहर में बहुत कुछ देखने लायक है.

> दिल्ली शहर की नई-नई चीजों से यात्रियों और पर्यटकों को रू-ब-रू होने में मदद करने के लिए दिल्ली सरकार ने हाल ही में दिल्ली पर्यटन का आधिकारिक मोबाइल एप्लिकेशन 'देखो मेरी दिल्ली' लॉन्च किया है. दिल्ली को अपने अद्भुत खानपान, मौज-मस्ती के लिए शानदार मनोरंजन और सबसे प्रतिष्ठित स्मारकों पर गर्व है. हालांकि, ऐसी कोई जगह नहीं थी जहां शहर की सभी जरूरी जानकारियां एक साथ मिल सकें. यह ऐप जानकारियों की उस कमी को पूरा करता है- दिल्ली के पर्यटन के बारे में सभी जानकारियां अब व्यवस्थित, उपयोगकर्ता के अनुकूल और प्रभावी तरीके से यहां उपलब्ध हैं.
>
> **-- अरविंद केजरीवाल**
> मुख्यमंत्री, दिल्ली सरकार

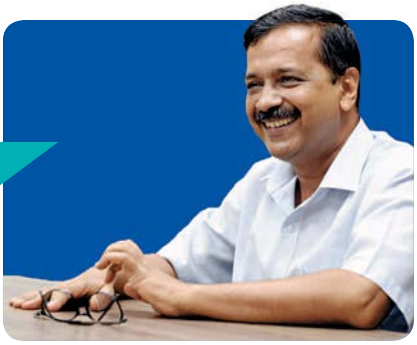

आपका भरोसेमंद हमसफर

एक ही जगह दिल्ली की सारी जानकारी: स्मारकों और विरासत स्थलों से लेकर रेस्तरां और पार्क तथा बाजार और मॉल तक, दिल्ली की सभी चीजों की खोज एक ही मंच पर करें. चाहे आप इतिहास को जानना चाहते हैं, अपने दोस्तों या परिवार के साथ किसी शाम का आनंद लेना चाहते हैं, अपने प्रियजनों के लिए उपहार खरीदना चाहते हैं या फिर दिल्ली के लजीज और जायकेदार पकवानों को आजमाना चाहते हैं- इस एप्लिकेशन में आपके लिए सारे सुझाव हैं.

बेफिक्र होकर सैर करेंः आपके ठहरने की अवधि के आधार पर यह एप्लिकेशन आपकी छुट्टी की योजना बनाने में आपकी मदद करता है. अगर आप दिल्ली में हैं तो यह ऐप आपको वहां ले जाएगा जहां आप जाना चाहते हैं. यह आपको परिवहन के विभिन्न साधनों और विभिन्न स्थानों पर पहुंचने के रास्तों के बारे में आपको बता देगा. इसके अलावा इसमें शहर की सभी सार्वजनिक सुविधाओं का नक्शा उपलब्ध है, इसलिए आप कहीं भी हों, आपको कोई मुश्किल नहीं आएगी.

झंझट मुक्त बुकिंग: टिकटों के लिए लंबी कतारों को अब कहें अलविदा! इस टूरिज्म एप्लिकेशन से उपयोगकर्ता सबसे लोकप्रिय गंतव्यों के लिए ऑनलाइन टिकट बुक कर सकते हैं.

अपरिचित परिवेश को समझनाः इस ऐप में गूगल लेंस इंटीग्रेटेड है जिसकी वजह से उपयोगकर्ता शहर में कभी नहीं खोएंगे. चाहे क्षेत्रीय भाषा में साइनबोर्ड हो, या फिर कोई अनजान लैंडमार्क- दिल्ली टूरिज्म ऐप में आप सब कुछ देख सकते हैं. जैसा कि दिल्ली के मुख्य सचिव विजय कुमार देव कहते हैं, "यह एप्लिकेशन इसलिए बनाया गया है कि दिल्ली में कोई सैलानी न खोए, यह आपकी जेब में समा जाने वाला ऐसा गाइड है जो शहर की आपकी यात्रा और अनुभव में आपका साथ देता है."

उपयोगकर्ता के अनुकूल इंटरफेस: इसके साथ-साथ, यह उपयोगकर्ता के अनुकूल इंटरफेस के भीतर इकट्ठा किए गए अनुभागों के बीच सहज नेविगेशन को आसान बनाता है. आप जब भी राजधानी में हों, 'देखो मेरी दिल्ली' आपका आदर्श साथी है.

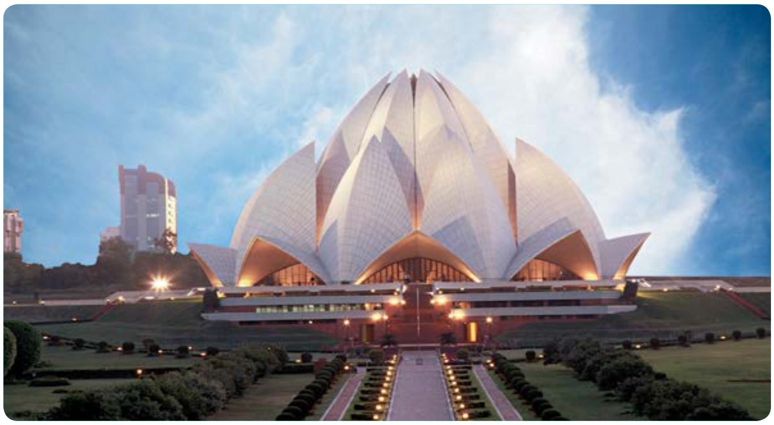

> पर्यटन का अनुभव खुशियों से जुड़ा है- चाहे नई जगहों की खोज करना हो, पुरानी पसंदीदा चीजों को फिर से देखना, या फिर अपने प्रियजनों के साथ बिताए पलों को यादगार बनाना. इस ऐप को बनाते समय ऐसा लग रहा था मानो हम दिल्ली के लोगों से लेकर पूरे देश और दुनिया के लोगों के लिए निमंत्रण कार्ड बना रहे हों. दिल्ली टूरिज्म ऐप आपको शहर की संपूर्ण यात्रा पर ले जाने के लिए बना है. आइए, देखिए!
>
> **-- मनीष सिसोदिया**
> उपमुख्यमंत्री एवं पर्यटन मंत्री, दिल्ली सरकार

अपनी यात्रा का प्रबंधन खुद करें

अपनी यात्रा के अनुभव का नियंत्रण और प्रबंधन खुद करें- चाहे आप पहली बार आए हों या अनुभवी यात्री हों, सभी लोगों के लिए गौरवशाली दिल्ली शहर की खोज करने के नए तरीके हैं! जैसा कि पर्यटन सचिव स्वाति शर्मा बताती हैं, “दिल्ली टूरिज्म एप्लिकेशन एक ऐसा सर्व-समावेशी मंच है जिसके माध्यम से हम दिल्ली, देश और पूरी दुनिया के लोगों को दिल्ली में अपनी यात्रा का स्वयं प्रबंध करने में सशक्त बनाना चाहते है.”

दिल्ली में घूमने की इच्छा रखने वाले अलग-अलग लोगों को ध्यान में रखते हुए इस ऐप को विकसित किया गया है. काम के लिए आने वाले लोग दिल्ली की जगहों के बारे में जान सकते हैं, जो छुट्टी पर हैं उन्हें कई तरह के अनुभवों के लिए विकल्प मिल सकते हैं, और दिल्ली के स्थानीय लोग ‘देखो मेरी दिल्ली’ पर बाहर घूमने-फिरने के सुझावों के लिए ब्राउज़ कर सकते हैं.

दिल्ली टूरिज्म ऐप के ज़रिये दिल्ली दर्शन

मेरे आसपास क्या-क्या है

क्या आपने कभी ऐसी स्थिति का सामना किया है जब आखिरी पल में आपको मेहमानों या सहयोगियों को घूमाना-फिराना पड़ा हो? दिल्ली टूरिज्म ऐप से आप अपनी लोकेशन के 10 किलोमीटर की रेडियस के भीतर घूमने-फिरने वाली जगहों का पता लगा सकते हैं.

दिली ख्वाहिश की खातिर सबसे बेहतरीन

आप शहर में कुछ दिनों के लिए हैं और यहां की सर्वश्रेष्ठ चीजों का अनुभव लेना चाहते हैं? इस एप्लिकेशन में शहर की टॉप 10 खानपान के अनुभवों, ऐतिहासिक स्मारकों, पार्क और उद्यानों, बाजारों और आध्यात्मिक स्थानों की सूची है. अपनी तमन्नाओं को पूरी करने के लिए तैयार रहें!

सदियों की दिल्ली

सदियों के इतिहास के साथ, दिल्ली इतिहास प्रेमियों के लिए शानदार शहर है. शहर में देखने के लिए स्मारकों और विरासतों की यात्रा की जानकारियां ऐप पर हासिल करें.

दिल्ली के अनदेखे रत्न

अगर आप गौरवान्वित दिल्लीवाले हैं, या शहर में बार-बार आने वाले यात्री हैं और मानते हैं कि आपने दिल्ली पूरी तरह देख लिया है तो जरा ठहरें- दिल्ली में अब भी बहुत कुछ देखने को बचा है. चाहें तो मिर्जा गालिब की हवेली का मेहमान बनें, या फिर तुगलकाबाद किले में अपने दोस्तों के साथ सैर करें- दिल्ली के अनदेखे रत्नों के पास आपको सुनाने के लिए बहुत सारी कहानियां हैं.

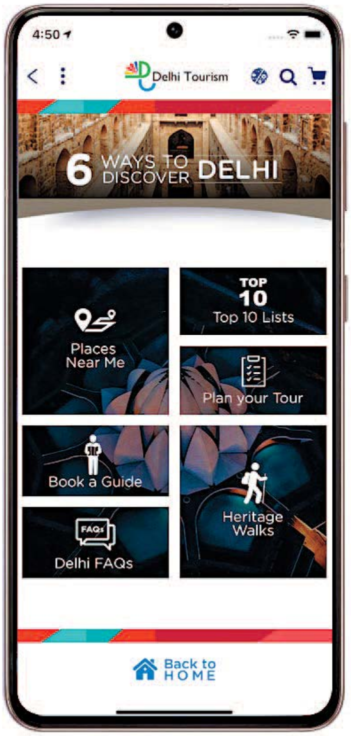

खानपान के शौकीनों का स्वर्ग

दिल्ली के व्यंजनों की शृंखला इसकी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का प्रतिबिंब है. चाहे आप दिल्ली के गली-मुहल्लों में कम पैसे में तरह-तरह के खाने का आनंद लेना चाहते हों, या आलीशान, नफीस और महंगे रेस्तरां में भोजन करना चाहते हों, अपने स्वाद और जरूरतों के आधार पर ‘देखो मेरी दिल्ली’ पर सुझाव हासिल करें.

पूरे परिवार के लिए

अगर आप अपने परिवार के साथ दिल्ली घूम रहे हैं तो शहर के भीतर परिवार और बच्चों के अनुकूल गतिविधियों की जानकारियां हासिल करें. ऐप यह सुनिश्चित करेगा कि अपनी यात्रा के दौरान आप और आपका परिवार एक पल के लिए भी उबाऊ महसूस न करें.

सहयोग एवं मार्गदर्शन

अगर दिल्ली आपके लिए नया शहर है तो इस एप्लिकेशन के जरिए मौसम से जुड़ी जानकारियां, सांस्कृतिक मानदंडों, परंपराओं और रिवाजों के बारे में सलाह, तथा सामान्य यात्रा टिप्स हासिल करें. आप शहर को देखने-समझने के लिए गाइड भी बुक कर सकते है जो आपकी पसंद और सुविधा की भाषा में बात करेंगे.

दिल खोलकर देखें दिल्ली !

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Android

iOS

कोविड-19 बच्चों का टीका

चलना है जरा संभल-संभल के

सोनाली आचार्जी

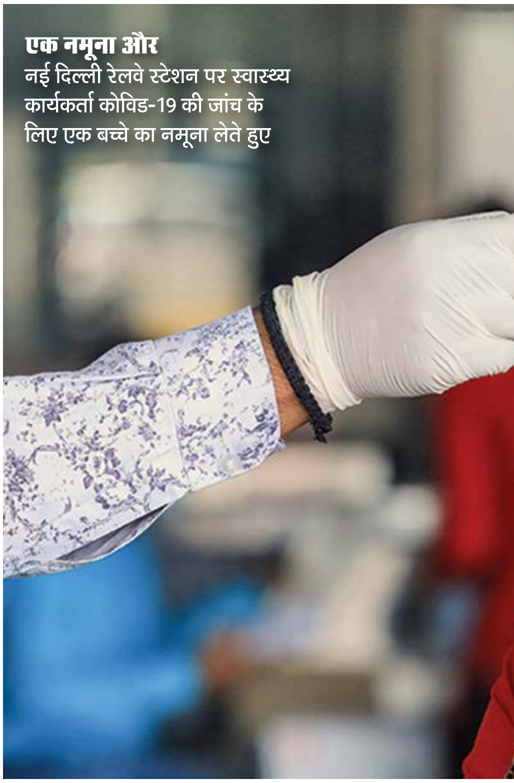
एक नमूना और
नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर स्वास्थ्य कार्यकर्ता कोविड-19 की जांच के लिए एक बच्चे का नमूना लेते हुए

गुरुग्राम की श्रेया नांगिया दो बच्चों की मां हैं. उन्होंने मार्च 2020 में कोविड महामारी की शुरुआत के बाद से ही बच्चों को अपने चार बेडरूम के घर से बाहर नहीं निकलने दिया. उनकी 12 और 14 साल की दोनों बेटियों को करीब 20 महीने से घर में बंद होने की हताशा और आक्रोश से उबरने के लिए ऑनलाइन काउंसलिंग की शरण लेनी पड़ी. पर 48 वर्षीया नांगिया कहती हैं कि वे उनके सामाजिक मेलजोल का जोखिम नहीं उठा सकतीं क्योंकि परिवार में उनके 86 वर्षीय पिता भी रहते हैं जो डायबिटिक और दिल के मरीज हैं. वे कहती हैं, ''मेरे पति घर से ही अपना कारोबार चलाते हैं और मैं गृहिणी हूं. हमने अपने बच्चों को टीके लगने तक घर पर ही पढ़ने देने की विशेष अनुमति ली है. अपने बच्चों को तकलीफ उठाते देखना बहुत कष्टदायक है, पर जिंदगी का जोखिम इस कष्ट से कहीं ज्यादा है.''

जब 20 अगस्त, 2021 को 12 से 18 साल के बच्चों को टीके लगाने का ऐलान हुआ और भारतीय कंपनी जायडस कैडिला की सूई-मुक्त डीएनए वैक्सीन जायकोव-डी को आपातकालीन इस्तेमाल की मंजूरी मिली, तो नांगिया परिवार खुशी से चहक उठा. मगर दो महीने बाद भी जब टीके लगने के बारे में कुछ पता नहीं चला, तो उत्साह ठंडा पड़ गया. नांगिया कहती हैं कि दो महीने पहले उनकी बेटियां वैक्सीन लगवाने वालों की कतार में शायद सबसे आगे होतीं, पर अब वे दावे से ऐसा नहीं कह सकतीं. वे सवाल करती हैं, ''क्या यह सुरक्षित है? हम ऑनलाइन खबरें पढ़ते रहते हैं कि बच्चों की इस वैक्सीन के लिए और परीक्षणों की जरूरत है जिसमें वक्त लगेगा. और साइड इफेक्ट? उसका भी पता नहीं.''

नांगिया अकेली नहीं हैं. चंडीगढ़ की पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन ऐंड रिसर्च और पुदुच्चेरी की जवाहरलाल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्टग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन ऐंड रिसर्च के शोधकर्ताओं ने 770 मरीजों पर ऑनलाइन सर्वे किया. इसके अनुसार, करीब 77 फीसद मरीजों ने कहा कि वे अपने बच्चों को टीके नहीं लगवाना चाहते. क्यों भला? इसके कारण हैं—सुरक्षा और प्रभाव के बारे में चिंता (86.4 फीसद), साइड इफेक्ट (78.2 फीसद) और यह विचार कि बच्चों को हल्की-फुल्की बीमारी होते रहने के रुझान के कारण उन्हें टीके लगवाने की जरूरत नहीं (52.8 फीसद).

> **''महामारी के चलते कई बच्चे घरों में बंद हैं. यह उनकी सेहत या भविष्य के लिए अच्छा नहीं. जिंदगी को फिर सामान्य बनाने के लिए टीके लगवाना जरूरी है''**
>
> **डॉ. अनिल सचदेवा**
> बाल रोग विशेषज्ञ, सर गंगाराम हॉस्पिटल, दिल्ली

डॉक्टर बार-बार प्रामाणिक जानकारी देकर टीके लगाने की झिझक को दूर कर रहे हैं. बेंगलूरू के बनेरघट्टा रोड स्थित फोर्टिस अस्पताल की पीडियाट्रिक इनटेंसिव केयर यूनिट के प्रमुख डॉ. योगेश कुमार गुप्ता कहते हैं, ''डीएनए वैक्सीन को परीक्षण के बाद ही मंजूरी दी गई है. यह सुरक्षित है. कुछ साइड इफेक्ट तो हर वैक्सीन में होते हैं. ज्यादातर लोग ऑनलाइन झूठी खबरों से चक्कर में पड़ जाते हैं. माता-पिता को डॉक्टर से मिलकर स्पष्ट पता करना चाहिए.'' अहमदाबाद स्थित जायडस ने जुलाई में तीसरे चरण के परीक्षण के नतीजों का ऐलान किया. परीक्षण 28,000 से ज्यादा वॉलंटियर पर किए गए. जायडस की तीन खुराक 28-28 दिनों के फासले से दी जानी हैं. इसे लक्षणों वाले संक्रमण के खिलाफ 67 फीसद असरदार पाया गया है. परीक्षण के लिए वैक्सीन लेने वाले मरीजों में दूसरी खुराक के बाद गंभीर मामला या कोविड से जुड़ी मौत सामने नहीं आई और तीसरी खुराक के बाद हल्के संक्रमण का मामला भी सामने नहीं आया. कंपनी ने बताया कि तीसरे चरण के परीक्षण के लिए नामांकित वयस्कों और करीब 1,000 किशोरों, दोनों में वैक्सीन के प्रति सहन क्षमता एक समान थी. यही नहीं, जायकोव-डी के लिए जिस डीएनए प्लाज्मिड प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया गया है, वह कोविड के नए रूपांतरणों के हिसाब से खुद को आसानी से ढाल लेता है. दिल्ली के

नवीन शर्मा/गेट्टी इमेजेज

सर गंगाराम अस्पताल के बाल रोग विशेषज्ञ डॉ. अनिल सचदेवा कहते हैं, ''महामारी के चलते कई बच्चे घरों में बंद हैं. यह उनकी सेहत या भविष्य के लिए अच्छा नहीं. जिंदगी को सामान्य बनाने के लिए टीके लगवाना जरूरी है.''

गुरुग्राम के मणिपाल अस्पताल की पीडियाट्रिशियन डॉ. बरखा पांडेय कहती हैं कि उनके मरीज अपने बच्चों को टीके लगवाने को लेकर उत्सुक हैं, पर मन में कहीं डर भी है. वे कहती हैं, ''बच्चे कमजोर आयु समूह में हैं. बच्चों की वैक्सीन के लिए लंबे वक्त की सुरक्षा और असर का डेटा होना जरूरी है. इसीलिए हमें कोविड वैक्सीनों के बारे में पढ़ते रहना होता है क्योंकि कुछ साइड इफेक्ट ज्यादा लंबे वक्त के दौरान भी हो सकते हैं.''

बच्चों को टीके लगवाने को लेकर सबसे ज्यादा उत्सुक वही माता-पिता हैं जिनके बच्चों को डायबिटीज, लीवर या किडनी की परेशानियां, अस्थमा या दूसरी सांस की बीमारियों जैसी सह-रुग्णताएं हैं. डॉ. पांडेय कहती हैं, ''पिछली दो देशव्यापी लहरों में हमने जो देखा, उसके मुताबिक बच्चों में कोविड उतना खतरनाक नहीं है. मगर जिन बच्चों को दूसरी बीमारियां हैं, उनमें जोखिम ज्यादा है. इन बच्चों में कोविड के बाद भीतरी सूजन और जटिलताएं होने का जोखिम भी ज्यादा है. इसलिए वयस्कों के साथ उन्हें भी टीके लगवा लेने में ही समझदारी है.''

नेशनल एक्सपर्ट ग्रुप ऑन वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन के सदस्यों के मुताबिक, बच्चों के लिए टीका अभियान 2022 की शुरुआत में चरणबद्ध तरीके से शुरू होगा. कोविड के तेज लक्षणों के सबसे ज्यादा अंदेशे वाले बच्चों को प्राथमिकता दी जाएगी.

सरकार ने जायकोव-डी की अंतिम कीमत का ऐलान किया है और 265 रुपए प्रति खुराक (नीडल-फ्री एप्लिकेटर के लिए 93 रुपए और) के हिसाब से 1 करोड़ खुराक का ऑर्डर भी दे दिया है. सरकार ने कहा है कि वह बच्चों के टीकाकरण में सतर्कता बरतेगी. स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने पिछले हफ्ते कहा, ''विशेषज्ञों की राय के आधार पर हम फैसला करेंगे.''

भारत की करीब 40 फीसद आबादी 18 से कम उम्र की है. विशेषज्ञों का कहना है कि इस आयु समूह को टीके नहीं लगाने का मतलब है कोविड वायरस को बार-बार पैदा होने, रूप बदलने और संक्रमण फैलाने देना. डॉ. सचदेवा कहते हैं, ''कोविड के खिलाफ बच्चों की रोग प्रतिरोधक प्रतिक्रिया अमूमन मजबूत पाई गई है, पर कइयों को भले-चंगे होने के बाद बहुत-से अंगों में सूजन आई.'' इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स (आइएपी) के इन्टेंसिव केयर चैप्टर के आंकड़े बताते हैं कि देश भर में बच्चों में मल्टीसिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम (एमआइएस-सी) के 2,000 से ज्यादा मामले आए. हालांकि कुल मिलाकर ये बिरले मामले ही हैं. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के आंकड़े बताते हैं कि 22 अगस्त, 2021 तक कोविड से हुई कुल मौतों में 20 साल से कम के भारतीय महज 1.2 फीसद हैं. डॉ. गुप्ता कहते हैं, ''ढेरों दूसरी बीमारियां हैं जिनसे बच्चों को कोविड से कहीं ज्यादा खतरा है. माता-पिता को इन बीमारियों से बच्चों की रक्षा करने से कोई समझौता नहीं करना चाहिए, महज इस डर से कि क्लिनिक में कोविड हो जाएगा. बच्चों को पहले से मंजूर टीके लगवाने के लिए कोविड वैक्सीन का इंतजार मत कीजिए.''

हालांकि डॉक्टर मानते हैं कि फिलहाल वयस्क टीकाकरण अव्वल प्राथमिकता होनी चाहिए और उसके बाद सह-रुग्णता से ग्रस्त बच्चों को टीके लगाएं. खासकर इसलिए कि अभी तक 18 साल से ऊपर के कुल करीब 94 करोड़ भारतीय में से केवल 37 करोड़ का ही पूर्ण टीकाकरण हुआ है. ऐसी योजना से हरेक के लिए जिंदगी सामान्य होने में लंबा वक्त लगेगा पर इससे मौत का जोखिम और कोविड के बाद की जटिलताएं तो कम हो ही जाएंगी.■

टीके जो आने हैं

बच्चों के लिए कई कोविड वैक्सीन विकसित की जा रही हैं

भारत बायोटेक की कोवैक्सिन

- 2-18 वर्ष के बच्चों के लिए इस्तेमाल की मंजूरी मिली; 5 से कम उम्र के बच्चों के लिए मंजूर दुनिया की पहली वैक्सीनों में
- अंतिम मंजूरी देने से पहले भारत के दवा नियंत्रक (डीसीजीआइ) और केंद्रीय दवा मानक नियंत्रण संगठन (सीडीएससीओ) फिलहाल इस वैक्सीन की समीक्षा कर रहे हैं
- तीन आयु समूहों (12-18 साल, 6-12 साल और 2-6 साल) के 525 स्वयंसेवकों पर दूसरे, तीसरे चरण के परीक्षण हो चुके
- वयस्कों में कोविड के डेल्टा रूप से पैदा लक्षणों वाली बीमारी के खिलाफ कोवैक्सिन 65.2 फीसद असरदार है

नोवोवैक्स की कोवोवैक्स (सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का उत्पाद)

- फिलहाल 2 से 17 साल के बच्चों में दूसरे और तीसरे चरण के परीक्षण चल रहे हैं; इस साल के अंत तक परीक्षण पूरे करने और आपातकालीन उपयोग मंजूरी पाने की योजना है
- कोविड-19 की नोकदार प्रोटीन निशाने पर, वायरस इसी से कोशिका में घुसता है
- वैश्विक परीक्षणों में साबित हुआ कि बीमारी को लक्षणविहीन बनाने में यह 60 फीसद असरदार; डेल्टा स्ट्रेन की चपेट में आने पर अस्पताल में भर्ती न होने के लिए 93 फीसद असरदार

बायोलॉजिकल ई की कोर्बेवैक्स

- फिलहाल 5 से 17 साल के बच्चों में दूसरे और तीसरे चरण के परीक्षण जारी
- यह आरबीडी प्रोटीन सब-यूनिट वैक्सीन है. सब-यूनिट वैक्सीन रोग प्रतिरोधक प्रतिक्रिया उत्पन्न करने के लिए पूरा वायरस इंजेक्ट नहीं करतीं, बल्कि इनमें वायरस के शुद्ध किए गए टुकड़े होते हैं, जो रोग प्रतिरोधक कोशिका उद्दीप्त करने की अपनी क्षमता के कारण चुने जाते हैं

क्रिप्टोकरेंसी का जुनून

क्रिप्टो के उन्माद को हवा दे रहा है डिजिटल मुद्रा में युवा भारतीयों का 6 अरब डॉलर का निवेश. क्या यह बुलबुला है जो फूटने का इंतजार कर रहा है?

एम.जी. अरुण

इलस्ट्रेशन : नीलांजन दास

एक दोस्त ने 2019 में मुंबई के विज्ञापन जगत के पेशेवर 42 वर्षीय शौविक सेन का तआरुफ क्रिप्टोकरेंसी की दुनिया से करवाया. कौतूहल से भरे सेन ने एक क्रिप्टो एक्सचेंज में रजिस्टर कर लिया. केवाइसी (नो योर कस्टमर) नियमों की अनिवार्यताएं पूरी करने के बाद उन्होंने अपना बैंक खाता एक्सचेंज के ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म से लिंक कर दिया. फिर उन्होंने म्यूचुअल फंड की बचत का एक हिस्सा कुछ क्रिप्टोकरेंसियों में निवेश कर दिया. करीबी दोस्तों ने डिजिटल जगत में इस तरह 'जुआ खेलने' के खिलाफ उन्हें आगाह किया लेकिन सेन इतने उत्सुक और उत्साहित थे कि उन्होंने किसी की एक न सुनी. उन्होंने सबसे बड़ा दांव एथेरियम पर लगाया, जो मूल्य के लिहाज से बिटकॉइन के बाद दुनिया की सबसे बड़ी क्रिप्टोकरेंसी है. उन्होंने कुछ एथेरियम खरीदे, जिनमें से हरेक 15,000 रुपए का था, और इस साल की शुरुआत में जब उनमें हरेक का मूल्य 2.7 लाख रुपए पर पहुंच गया तो बेच दिए. वे कहते हैं, ''अगर ज्यादा इंतजार करता तो मैं और ज्यादा पैसा बना सकता था, क्योंकि एथेरियम की कीमत फिलहाल 3.5 लाख रुपए है. मगर क्रिप्टो की दुनिया में कुछ भी पक्के तौर पर नहीं कहा जा सकता.''

सेन उन लाखों भारतीयों में हैं जो इन दिनों क्रिप्टो उन्माद की गिरफ्त में हैं. क्रिप्टोकरेंसी केंद्रीय बैंकिंग व्यवस्था के दायरे से बाहर काम करती है और अल साल्वाडोर तथा अब क्यूबा को छोड़कर यह कहीं भी वैध मुद्रा नहीं है. ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर इसकी ट्रेडिंग के हिसाब से इसका मूल्य तय होता है और इसीलिए कई लोग इसे महज क्रिप्टो कहना पसंद करते हैं. असल में, पहली क्रिप्टोकरेंसी बिटकॉइन ऑनलाइन गेमिंग में प्रोत्साहन लाभ देने वाले टोकन के तौर पर शुरू हुई थी. जब ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें लेन-देन करने लगे तो इसकी कीमत बढ़ने लगी. 15 नवंबर को ऑनलाइन व्यापार में एक बिटकॉइन की कीमत 65,734 डॉलर या लगभग 48.7 लाख रुपए थी.

यह ज्यादा जोखिम ज्यादा इनाम की इसकी खासियत ही है जिसने युवा भारतीयों को अपनी तरफ लुभाया है. कॉइनस्विच कुबेर क्रिप्टो एक्सचेंज के संस्थापक और सीईओ आशीष सिंघल के मुताबिक, डेढ़-दो करोड़ भारतीयों ने क्रिप्टोकरेंसियों में करीब 6 अरब डॉलर (44,400 करोड़ रु.) निवेश किए हैं. कुबेर में 80 क्रिप्टोकरेंसी खरीदी और बेची जा सकती हैं.

मगर क्रिप्टो का अपना स्वभाव, जो नियम-कायदों से परे और विकेंद्रीकृत है, अब उसी के खिलाफ काम करने का खतरा पैदा कर रहा है. क्रिप्टो लॉन्च करने के लिए आपको केंद्रीय बैंक या कंपनी की जरूरत नहीं है. इसकी बुनियादी टेक्नोलॉजी की जानकारी रखने वाला कोई भी शख्स इसे शुरू कर सकता है. मिल्कियत एक ऑनलाइन खाते में दर्ज कर ली जाती है, जिसे दूसरे क्रिप्टो मालिकों का एक नेटवर्क संभालता है. यह नेटवर्क जानकारी हासिल करने और संवाद के लिए मजबूत क्रिप्टोग्राफी का इस्तेमाल करता है और इसलिए इस व्यवस्था से बाहर के लोगों के लिए कुछ पता लगा पाना मुश्किल होता है. यह भौतिक रूप में मौजूद नहीं है और इसलिए इसे जब्त भी नहीं किया जा सकता. शेयरों की कीमत तो कंपनी की बुनियाद, उसके कार्य प्रदर्शन और कारोबारी नजरिये से तय होती है, लेकिन क्रिप्टो के पीछे ऐसा कोई आधार या समर्थन नहीं है. इसके बजाए इसकी कीमत खालिस मांग और पूर्ति से तय होती है. बिटकॉइन सरीखी कुछ क्रिप्टोकरेंसी की सप्लाइ सीमित है, जबकि एथेरियम सरीखी दूसरी क्रिप्टोकरेंसी असीमित मात्रा में सप्लाइ हो रही हैं. कभी-कभी क्रिप्टो की सप्लाइ पूरी तरह प्रोजेक्ट की प्रभारी टीम के फैसले से तय होती है. वे ज्यादा टोकन जारी करने का विकल्प चुन सकते हैं या आपूर्ति संभालने के लिए टोकन ''बर्न'' कर सकते हैं. क्रिप्टो का मूल्य इस पर भी निर्भर करता है कि उसका

इलस्ट्रेशनः नीलांजन दास

10 सबसे मूल्यवान क्रिप्टो

सबसे ज्यादा बाजार पूंजीकरण वाली डिजिटल करेंसी जिनकी लोग ट्रेडिंग करते हैं

क्रम	नाम	मूल्य (डॉलर में)	बाजार पूंजी (अरब डॉलर में)
1	**बिटकॉइन**	65,886.42	**1,242.2**
2	**एथेरियम**	4,735.97	**559.85**
3	**बाइनेंस कॉइन**	645.78	**107.59**
4	**सोलाना**	245.69	**74.2**
5	**टेथर**	1.00	**73.92**
6	**कार्डानो**	2.07	**68.9**
7	**एक्सआरपी**	1.21	**56.8**
8	**पोलकाडॉट**	47.23	**46.39**
9	**डॉजकॉइन**	0.2626	**34.69**
10	**यूएसडी कॉइन**	1.00	**34.41**

स्रोतः कॉइनमार्केटकैप.कॉम

बढ़ती हिस्सेदारी

हाल के महीनों में क्रिप्टो में आई एकाएक तेजी के कारण निवेशकों का विस्फोट जैसा नजर आया

भारतीय क्रिप्टो मार्केट का बढ़ता आकार

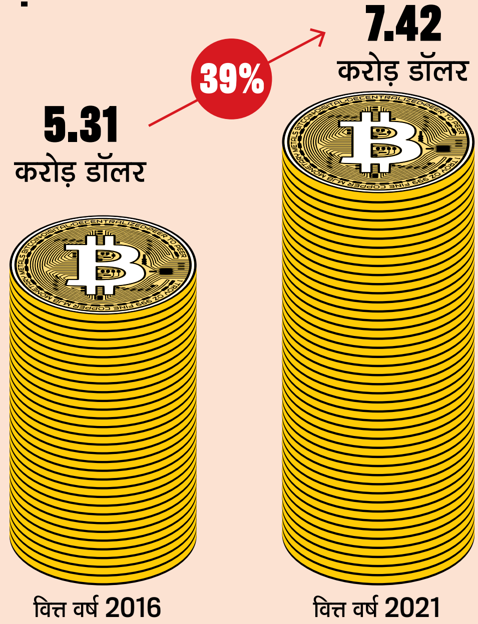

स्रोतः नैसकॉम

1.5-2 करोड़

भारतीयों ने क्रिप्टोकरेंसी में पैसे लगा रखे हैं

6 अरब डॉलर

या 44,400 करोड़ रुपए. कुल इतना भारतीय निवेश है क्रिप्टोकरेंसी में

40 एक्सचेंज

इतने क्रिप्टो प्लेटफॉर्म हैं भारत में. उद्योग का ऐसा अनुमान है

2.9 खरब डॉलर

या 212 लाख करोड़ रुपए. 15 नवंबर तक जिन 7,393 क्रिप्टो की पब्लिक ट्रेडिंग हो रही थी, उनकी बाजार पूंजी इतनी थी

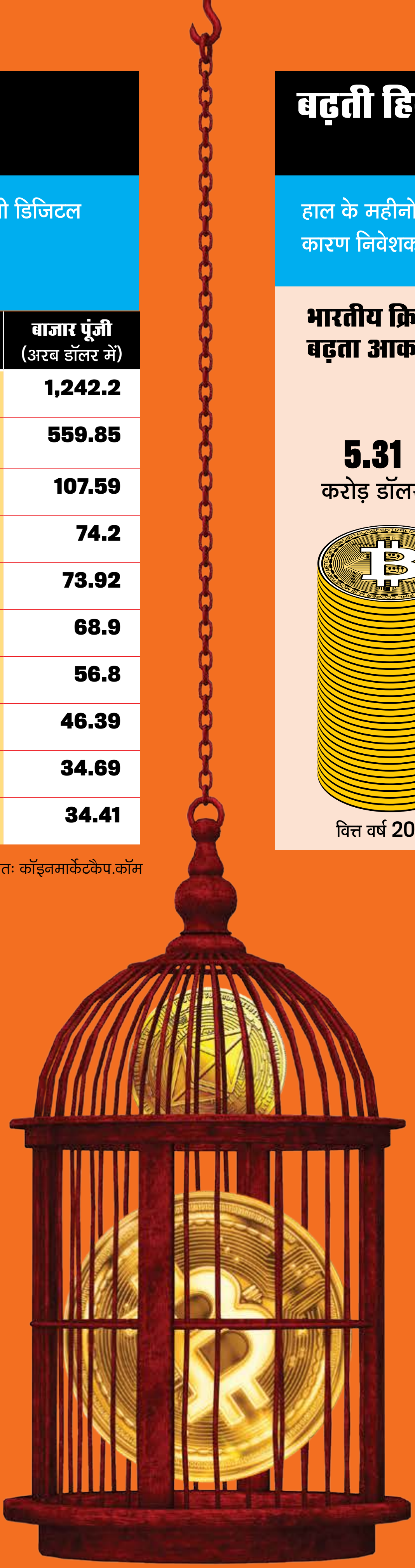

और फिर अगला कदम

अच्छे ढंग से मान्यता मिली और नियमित-नियंत्रित किया गया तो क्रिप्टो अपने में असीम संभावनाएं समेटे हुए है

क्रिप्टो मार्केट में समाई संभावना

(करोड़ डॉलर में)

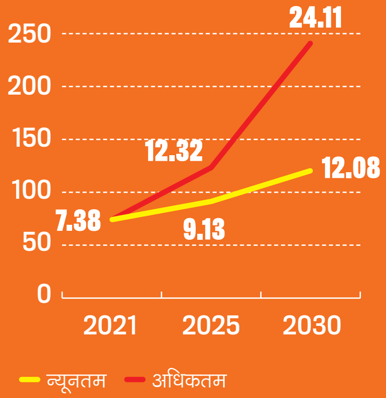

स्रोतः नैसकॉम

कोड कैसे लिखा जाता है, डिजिटल क्षेत्र में किसी समस्या को सुलझाने के लिए उसका कितनी अच्छी तरह इस्तेमाल किया जा सकता है, वगैरह.

क्रिप्टोकरेंसी के नए टोकन जिस प्रक्रिया से बनाए जाते हैं, उसे 'माइनिंग' कहते हैं. इसमें कंप्यूटर से लेन-देन की तस्दीक की जाती है. बदले में प्रोटोकॉल क्रिप्टो टोकन के रूप में इनाम देता है. इसके अलावा लेन-देन करने वाले पक्ष 'माइनर' को फीस चुकाते हैं.

क्रिप्टो का वैश्विक बाजार पूंजीकरण (यह क्रिप्टो एक्सचेंजों में निवेशकों के क्रिप्टो की कीमत में कुल प्रचलित क्रिप्टो की संख्या का गुणा करके निकाला जाता है) 15 नवंबर को 2.88 ट्रिलियन डॉलर या करीब 212 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गया. फिलहाल 7,393 से ज्यादा क्रिप्टोकरेंसी सार्वजनिक लेन-देन में हैं. हालांकि विशेषज्ञ मानते हैं कि क्रिप्टो जगत में इनकी संख्या इससे दोगुनी हो सकती है.

क्रिप्टो का बुखार जैसे-जैसे सरकारों के नियंत्रण से बाहर जोर पकड़ता जा रहा है, दुनिया भर की सरकारों में इसे नियमों के दायरे में लाने पर चर्चा छिड़ गई है. भारत भी क्रिप्टोकरेंसी के नियमन के लिए कानून बनाने पर विचार कर रहा है. इसके लिए संसद के शीतकालीन सत्र में विधेयक लाया जा सकता है. आरबीआइ के गवर्नर शक्तिकांत दास लगातार सतर्कता बरतने की बात कर रहे हैं. उन्होंने कहा है कि क्रिप्टोकरेंसी देश की "वृहत अर्थव्यवस्था और वित्तीय स्थिरता" के लिए खतरा पैदा कर रही हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 नवंबर को नई दिल्ली में एक उच्चस्तरीय बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें सरकारी सूत्रों के अनुसार, अन्य मुद्दों के अलावा इस बात पर विचार किया गया कि क्यों "नियम-कायदों से मुक्त क्रिप्टो बाजारों को धन शोधन और आतंकी वित्तपोषण का जरिया बनने की इजाजत नहीं दी जा सकती" और साथ ही क्रिप्टोकरेंसी के "गुमराह करने वाले, बड़े-बड़े वादे करने वाले और अपारदर्शी" विज्ञापनों की तरफ ध्यान आकृष्ट किया गया. भाजपा नेता और सांसद जयंत सिन्हा की अध्यक्षता में वित्त मामलों की संसदीय समिति ने भी क्रिप्टो को लेकर चिंता जाहिर की. मगर क्रिप्टोकरेंसी के लिए दरवाजे पूरी तरह बंद करने के बजाए उन्हें भारतीय प्रतिभूति और विनिमय

> "क्रिप्टो की असली फितरत और संभावनाओं की (भरोसेमंद) जानकारी के अभाव में खतरा यह है कि यह फूला हुआ बुलबुला साबित हो सकता है"
>
> **सुभाष चंद्र गर्ग**
> *पूर्व वित्त सचिव*

क्रिप्टोकरेंसी की बुनियादी जानकारी

खासे उतार-चढ़ाव, लगातार दायरा बढ़ाती जा रही डिजिटल दुनिया के बारे में वे तथ्य जो आप जानना चाहते हैं मगर पूछने से घबराते हैं

क्रिप्टोकरेंसी क्या है?

यह डिजिटल टोकन है, जिससे आप सामान और सेवाएं खरीद सकते हैं या फिर मुनाफे के लिए लेन-देन कर सकते हैं. इसके लिए सुरक्षित ऑनलाइन लेन-देन के वास्ते सख्त क्रिप्टोग्राफी से जुड़े साझा ऑनलाइन लेजर (खाता-बही) का इस्तेमाल किया जाता है

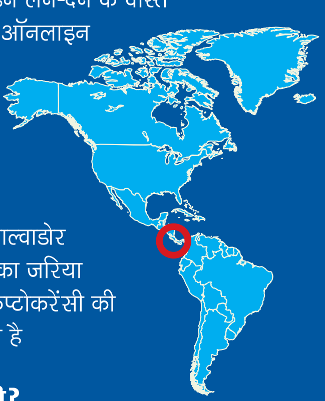

क्या इससे सामान खरीदा जा सकता है?

क्रिप्टो अभी बस दो देशों अल साल्वाडोर और क्यूबा में कानूनी लेन-देन का जरिया है. भारत सहित बाकी दुनिया क्रिप्टोकरेंसी की खरीद-बिक्री की ही इजाजत देती है

क्या है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी?

क्रिप्टो का आधार है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी. इसमें पीयर टु पीयर नेटवर्क के बीच, ऊपर से नीचे तक सारे लेन-देन का विकेंद्रित और बंटा हुआ लेजर है

आखिर कितना सुरक्षित है ब्लॉकचेन?

ब्लॉकचेन में हर 'ब्लॉक' खास लेन-देन और पहले के

आखिर इसकी उत्पत्ति कैसे हुई?

हाल के दौर में दिवलिया होने की सबसे बड़ी घटना 2008 में सामने आई. अमेरिका में लीमन ब्रदर्स की वजह से उपजे संकट ने वित्तीय व्यवस्था की किसी और ढंग से कल्पना करने को प्रेरित किया. इस तरह एक विकेंद्रित मुद्रा व्यवस्था सामने आई, जहां लोग एक-दूसरे से लेनदेन इंटरनेट के जरिए कर पाएं और उन्हें केंद्रीय बैंक और केंद्रीय नियम-कायदों जैसे केंद्रीय संस्थाओं पर निर्भर न रहना पड़े, जहां मुट्ठी भर अधिकारी फैसले करते हैं

लीमन ब्रदर्स

किसने शुरू की क्रिप्टो करेंसी?

2008 में सातोषी नाकामोटो के छद्म नाम से कोई एक शख्स या कुछ लोगों के समूह ने श्वेत-पत्र निकाला और उसे विकेंद्रित भुगतान व्यवस्था का नाम दिया. उन लोगों ने उसे ग्लोबल वर्चुअल करेंसी बिटकॉइन कहा और बिटकॉइन डॉट ओरआरजी नाम से डोमेन पंजीकृत कराया. मकसद सीमाओं के आरपार दो व्यक्तियों के बीच लेन-देन को बिना किसी ''भरोसेमंद मध्यस्थ'' को बीच में लाए संभव बनाना था

कैसे विकसित हुई यह टेक्नोलॉजी?

विकेंद्रित समुदाय ने ब्लॉकचेन नामक प्रोटोकॉल का इस्तेमाल किया. पहले पहल इसका प्रस्ताव 1991 के एक रिसर्च पेपर में आया. नाकामोटो और दूसरों ने उसमें 2009 में क्राउडसोर्सिंग के जरिए और सुधार किया, जिसे उन्होंने एक अच्छा सामाजिक काम बताया

लेन-देन का डेटा होता है. अगर कोई भी ब्लॉकचेन तोड़ने की या लेन-देन में हेराफेरी की कोशिश करता है, तो अगले सभी लेन-देन बेमानी हो जाएंगे. क्रिप्टो लॉबी अपने इस दावे के पक्ष में मिसाल देती है कि क्रिप्टो स्पेस में घुसपैठ डिजिटल बैंकिंग के मुकाबले काफी मुश्किल है

ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का और किस मद में इस्तेमाल हो सकता है?

ब्लॉकचेन के एप्लिकेशंस में मेडिकल डेटा को सुरक्षित तरीके से साझा करना, संगीत की रॉयल्टी की निगरानी, सीमाओं के आर-पार भुगतान, आइओटी (इंटरनेट ऑफ थिंग्स) ऑपरेटिंग सिस्टम की रियलटाइम उपलब्धता, मनी लॉन्ड्रिंग विरोधी निगरानी व्यवस्था, आपूर्ति श्रृंखला और सामान ढुलाई की निगरानी वगैरह शामिल हैं

क्रिप्टो के बारे में दुनिया का नजरिया क्या?

अल साल्वाडोर और क्यूबा ही ऐसे देश हैं, जहां बिटकॉइन को लेन-देन का कानूनी जरिया बनाने के लिए कानून पास किए गए हैं. अमेरिका, कनाडा और ब्रिटेन बिटकॉइन लेन-देन की मंजूरी देते हैं लेकिन रूस और चीन नहीं देते. दरअसल, चीन ने इस साल के शुरू में सभी क्रिप्टो लेन-देन पर एकतरफा प्रतिबंध लगा दिया

भारत में क्रिप्टोकरेंसी को नियंत्रित करने के लिए क्या हो रहा है?

➘ भारतीय रिजर्व बैंक ने 2018 में क्रिप्टोकरेंसी में लेन-देन पर प्रतिबंध लगा दिया था, जिसे सुप्रीम कोर्ट की तीन जजों की पीठ ने मार्च 2020 में खारिज कर दिया

➘ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 नवंबर को एक उच्चस्तरीय बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें क्रिप्टोकरेंसी के विज्ञापनों में ''भ्रामक'', ''बड़बोले दावों'' और ''गैर-पारदर्शिता'' पर नाराजगी जाहिर की गई और बताया गया कि क्यों ''बेलगाम क्रिप्टो मार्केट को मनीलॉन्ड्रिंग और आतंक के लिए वित्तीय मदद का जरिया नहीं बनने दिया जा सकता.''

➘ रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास कहते हैं कि क्रिप्टोकरेंसी देश की ''व्यापक अर्थव्यवस्था और वित्तीय स्थिरता'' के लिए खतरा हैं

➘ सरकार संसद के आगामी सत्र में इसे लेकर कोई विधेयक पेश कर सकती है. क्रिप्टो को शायद लेन-देन के कानूनी जरिए की इजाजत न मिले, लेकिन उसे धन-संपत्ति जैसा मान लिया जाए और शायद सेबी से नियंत्रित किया जाए

क्रिप्टो में कैसे करें कारोबार?

क्रिप्टो करीब 40 क्रिप्टो एक्सचेंज में खरीदा-बेचा जा सकता है. इनमें कॉइनबेस, बिनांस, कॉइनडीसीएक्स, वजीरएक्स और कॉइनस्विच कुबेर प्रमुख हैं. जानकार शुरू में ऐसी रकम का निवेश करने को कहते हैं, जो डूब जाए तो गम नहीं. अनाड़ियों को जानकारों से सलाह लेने को भी कहा जाता है.

क्रिप्टो निवेश के पांच कदम

1. क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज की पहचान करें

2. डिजिटल वॉलेट में पैसे डालने के लिए डेबिट कार्ड या वायर ट्रांसफर को जरिया बनाएं

3. एक्सचेज में सूचीबद्ध क्रिप्टो का चयन करें

4. ट्रेडिंग रणनीति में से चुनें: स्काल्पिंग (बिक्री के पहले थोड़े समय के लिए कॉइन को अपने पास रखें), डे ट्रेडिंग (एक दिन तक संपत्ति को हाथ में रखना), स्विंग ट्रेडिंग (कुछ दिनों या हफ्तों तक अपनी स्थिति बरकरार रखना), पोजिशन ट्रेडिंग (लंबे समय के मूल्य बदलाव का इंतजार) वगैरह. मुनाफा क्रिप्टो अकाउंट से जुड़े बैंक खाते में जाता है. उसी खाते से क्रिप्टो खरीद का पैसा आता है

5. अपनी क्रिप्टो को हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर वॉलेट में सुरक्षित रखें

(स्रोतः ब्लॉकचैन-काउंसिल.ओआरजी)

इलस्ट्रेशनः नीलांजन दास

बोर्ड (सेबी) के नियामकीय देखरेख के अधीन परिसंपत्ति वर्ग के रूप में इजाजत देने की कोशिशें चल रही हैं.

तो इस तरह क्रिप्टोकरेंसी फिलहाल किस मुकाम पर आ गई है? क्या इसका भविष्य की मुद्रा होना तय है, या यह सिर पर मंडराती मुसीबत है जिसे हमें लीलने से पहले जड़ से उखाड़ फेंकना जरूरी है? ऐसे और अन्य सवालों के जवाब पाने के लिए आइए शुरुआत की तरफ लौटें.

क्रिप्टो की शुरुआत

क्रिप्टोकरेंसी 2008 के लीमन ब्रदर्स संकट की राख से उत्पन्न हुई. उस साल नवंबर में एक व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह ने सतोषी नाकामोटो के छद्मनाम से एक श्वेत पत्र प्रकाशित किया और उसमें एक ग्लोबल वर्चुअल करेंसी बनाने की मांग की. दुनिया की वित्तीय प्रणालियों की अनिश्चितताओं और अनियमितताओं के चलते उन्होंने एक ऐसी करेंसी के रूप में इसकी कल्पना की, जो केंद्रीय बैंकों और नियामकों सरीखी केंद्रीयकृत संस्थाओं से (जहां मुट्ठी भर लोग तमाम फैसले लेते हैं और उस संकट ने उदाहरण सहित दिखाया कि वे सही फैसले नहीं लेते हैं) बचकर निकल सके. विचार यह था कि दुनिया भर में पारंपरिक "भरोसेमंद मध्यस्थों" के बगैर व्यक्ति से व्यक्ति से बीच लेन-देन की सुविधा विकसित की जाए, ताकि ऐसे लेन-देन ज्यादा तेजी से, ज्यादा सस्ते और ज्यादा पारदर्शी ढंग से किए जा सकें. क्रिप्टो के शुरुआती प्रस्तावकों ने इसे सीमाहीन नई "मुद्रा" बिटकॉइन कहा.

नई व्यवस्था में भरोसा पैदा करने के लिए जिन प्रोटोकॉल या नियम-कायदों का इस्तेमाल किया गया, उन्हें ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कहा गया. ब्लॉकचेन पूरे नेटवर्क में विभिन्न लेन-देन का विकेंद्रीकृत और वितरित खाता है. यह टेक्नोलॉजी पेशेवरों ने क्राउडसोर्सिंग के माध्यम से 2009 में विकसित की थी. बिटकॉइन पहली क्रिप्टोकरेंसी थी. मगर समय के साथ टेक्नोलॉजी के उत्साही समर्थकों ने कई और क्रिप्टोकरेंसी लॉन्च की. आज वर्चुअल दुनिया में इसके हजारों रूप प्रचलित हैं.

क्रिप्टो की तेज कदमताल

भारत में क्रिप्टो उद्योग यहां पिछले दो साल में टेक इंडस्ट्री के मुकाबले चार गुना रफ्तार से बढ़ा है

भारत में क्रिप्टो के राजस्व में वृद्धि
(2019-2021)

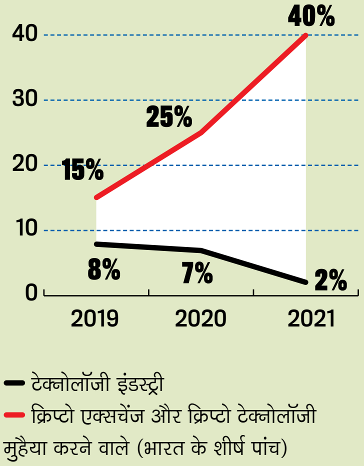

इलस्ट्रेशनः नीलांजन दास

> "नियमन का इस इंडस्ट्री में स्वागत है. हम नहीं चाहते कि इस ईको सिस्टम में कोई ऐसा खराब कुछ भी करे जिससे यूजर्स को नुक्सान हो."

आशीष सिंघल
संस्थापक और सीईओ
कॉइनस्विच कुबेर

भारत में क्रिप्टो

स्पेसएक्स और टेस्ला के सीईओ इलॉन मस्क के पास क्रिप्टो का ऐसा पोर्टफोलियो है जिससे कोई भी ईर्ष्या करेगा. लाखों दूसरे लोग भी क्रिप्टो को लेकर पागल हुए जा रहे हैं. भारत भी कोई अपवाद नहीं है. महामारी के दौरान जब अनगिनत लोग घर से काम करने को मजबूर हो गए तब काफी निवेशक क्रिप्टो के इर्दगिर्द जमा भीड़ में शामिल हो गए. हाल के दिनों में क्रिप्टो के मूल्य में जबरदस्त बढ़ोतरी ने भी इसे निवेश का लोकप्रिय विकल्प बना दिया. चूंकि दुनिया के ज्यादातर हिस्सों में क्रिप्टो को वैध मुद्रा के रूप में इजाजत नहीं दी गई, इसलिए इसने निवेश किए जा सकने वाले "परिसंपत्ति वर्ग" (शेयर, नकद और नकद समकक्ष, रियल एस्टेट से मिलती-जुलती खासियतों वाला निवेशों का समूह) के रूप में लगातार ज्यादा से ज्यादा कामयाबी हासिल कर ली.

अल साल्वाडोर में खरीदार डिजिटल वॉलेट में, जिन्हें "चीवो" (अंग्रेजी अनुवाद "कूल") कहा जाता है, बिटकॉइन लोड कर सकते हैं और एक मोबाइल ऐप के जरिए उन तक पहुंच सकते हैं. भुगतान या तो बिटकॉइन में या उनके बराबर डॉलर में किए जा सकते हैं. भारत में निवेशक क्रिप्टो जमा करने और रखने के लिए डिजिटल वॉलेट का इस्तेमाल करते हैं, जिनका फिर क्रिप्टो एक्सचेंज पर लेन-देन किया जाता है. बिटकॉइन और एथेरियम के अलावा ऊंचे मूल्य की दूसरी क्रिप्टोकरेंसी में बाइनेंस कॉइन, सोलाना, टेथर, कार्डानो, एक्सआरपी, पोलकाडोट, डॉजकॉइन और यूएसडी कॉइन शामिल हैं (देखें: 10 सबसे ज्यादा मूल्य वाली क्रिप्टोकरेंसी). एक प्रकार का डिजिटल टैग, नॉन-फंजिबल टोकन

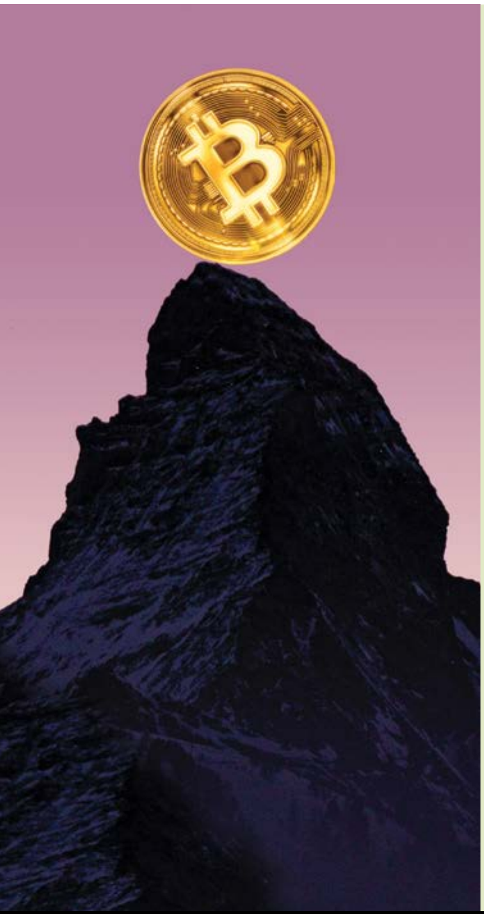

स्टार्ट-अप के मुरीद

क्रिप्टो के स्टार्ट-अप आज की तारीख में लोगों की भारी पसंद बने हुए हैं

भारत में चल रहे स्टार्ट-अप

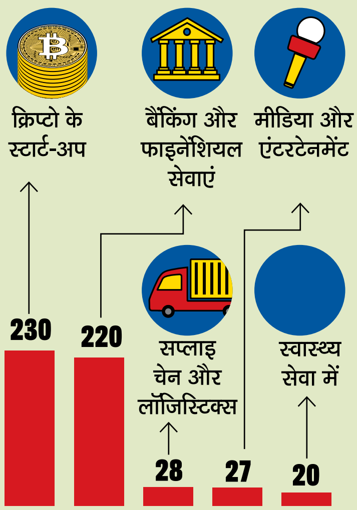

आगे और भी हैं संभावनाएं

दुनिया में क्रिप्टो उद्योग के 2026 तक 2.3 अरब डॉलर पहुंचने की संभावना है

विश्वव्यापी क्रिप्टो उद्योग
(अरब डॉलर में)

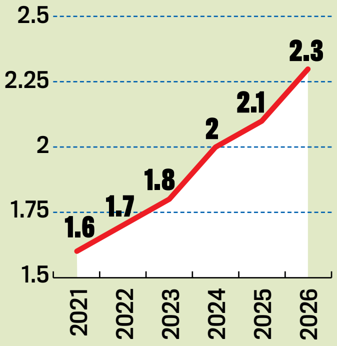

स्रोतः नैसकॉम

(एनएफटी) निवेशकों के बीच काफी लोकप्रिय हो गए हैं. इनका लेन-देन डिजिटल दुनिया में ज्यादातर कला की नीलामी में किया जाता है (देखें: एनएफटी को मिली सितारों की ताकत).

कुल मिलाकर छोटे और बड़े करीब 40 क्रिप्टो एक्सचेंज हैं, जो संभावित निवेशकों को लुभाने के लिए होड़ करते रहते हैं. कुछ एक्सचेंज ने ''जागरूकता पैदा करने'' के लिए प्रमोशन और विज्ञापन का अभियान छेड़ दिया है और मुख्यधारा के मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भारी रकम खर्च कर रहे हैं. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, उन्होंने हाल में हुए टी20 विश्व कप के दौरान करीब 50 करोड़ रुपए खर्च किए, जिससे सरकार का ध्यान इन पर गया और वह बिन मांगी जांच-पड़ताल के लिए तत्पर हुई. यूट्यूब और सोशल मीडिया साइटों पर सैकड़ों व्लॉगरों ने अंग्रेजी, हिंदी और कई क्षेत्रीय भाषाओं में इच्छुक निवेशकों को क्रिप्टो में निवेश के अवसरों के बारे में ''शिक्षित करने'' का बीड़ा उठा रखा है. क्रिप्टो एक्सचेंज कॉइनडीसीएक्स के संस्थापक सुमित गुप्ता के इंटरव्यू का, जिसका शीर्षक था ''मीट इंडियाज क्रिप्टो मिलियनेयर'' (मिलिए भारत के क्रिप्टो करोड़पति से), एक वीडियो मार्च में यूट्यूब पर अपलोड किया गया था और इसने दस लाख से ज्यादा व्यू जुटा लिए.

उद्योग की संस्था नैसकॉम की एक हालिया रिपोर्ट का अनुमान है कि यह क्रिप्टो बाजार में फिलहाल 50,000 लोग कार्यरत हैं, और यह 2030 तक 8,00,000 से ज्यादा नौकरियों का सृजन करने की क्षमता और संभावना से भरा है. रिपोर्ट यह भी कहती है कि भारत के 60 फीसद राज्य क्रिप्टो टेक्नोलॉजी को अपनाने वाले राज्यों के तौर पर उभर रहे हैं और 2030 तक इस उद्योग का 241 अरब डॉलर पर पहुंचना तय है. रिपोर्ट के मुताबिक, भारत का क्रिप्टो टेक उद्योग बीते पांच सालों में 39 फीसद बढ़कर 2020-21 में 7.42 करोड़ डॉलर पर पहुंच गया. इतना ही नहीं, बीते दो सालों में यह उद्योग टेक्नोलॉजी क्षेत्र की रफ्तार से चार गुना तेजी से बढ़ा है. इस अवधि में क्रिप्टो स्टार्ट-अप में सांस्थागत निवेश आठ गुना बढ़ा है. भारत में अभी 230 क्रिप्टो स्टार्ट-अप काम कर रहे हैं.

आलोचना और विरोध

अमेरिका, कनाडा और ब्रिटेन सरीखे देशों ने बिटकॉइन में व्यापार की इजाजत दी है जबकि चीन और रूस ने नहीं. चीन ने तो क्रिप्टो लेन-देन पर पूरी तरह पाबंदी लगा दी है. हालांकि उद्योग के कुछ पर्यवेक्षकों का कहना है कि यह क्रिप्टो की कीमतें गिराने और फिर कम कीमत पर उन्हें खरीदने की सोची-समझी रणनीति है. चीन नियम-कायदों से अत्यधिक बंधे और केंद्रीयकृत डिजिटल युआन या ई-सीएनवाइ के सामने आने वाली किसी प्रतिस्पर्धा को जड़ से उखाड़ फेंकना चाहता है. ई-सीएनवाइ का इस्तेमाल मुख्यतः खुदरा लेनदेन में किया जाता है.

क्रिप्टो व्यापार की खामियों की ऐसे करें भरपाई

क्रिप्टो मुद्राओं को लेकर कई तरह की चिंताएं जताई जा रही हैं, इसीलिए इन पर सख्त नियम-कायदों की मांग हो रही है. कुछ समाधान तो ये रहे

फिक्रः क्रिप्टो मार्केट में निवेशकों को खासा नुक्सान हो सकता है क्योंकि इनमें अक्सर भारी उतार-चढ़ाव आते हैं
हलः एक्सचेंजों को रक्षा के ऐसे उपाय तैयार करने चाहिए जिनसे भोले-भाले निवेशकों को अपनी रकम न गंवानी पड़े. पूरे साल के लिए क्रिप्टो की कीमतें प्रदर्शित करने से उतार-चढ़ाव को समझने और विवेक के साथ फैसले लेने में मदद मिलेगी

फिक्रः क्रिप्टो के प्रचार-प्रसार और विज्ञापनों में आए उछाल में निवेश पर रिटर्न को बढ़ा-चढ़ाकर बताया जा रहा है
हलः सरकार एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया से कह सकती है कि वह ऐसे विज्ञापनों पर कड़ी निगाह रखे और जरूरत पड़ने पर उनके बारे में लोगों को आगाह करे

फिक्रः भारतीय क्रिप्टो एक्सचेंज समय-समय पर हैकर्स के शिकार हुए हैं, जो उनके डिजिटल वॉलेट में सेंध लगा लेते हैं और क्रिप्टोकरेंसी ले उड़ते हैं
हलः निवेशकों को क्रिप्टो के बारे में खुद को अच्छी तरह से शिक्षित करना होगा, जैसा कि उन्होंने इक्विटी बाजारों में निवेश आरंभ करते समय किया था

फिक्रः आतंकवादी, धनशोधक और दूसरे असामाजिक तत्व क्रिप्टो के ईकोसिस्टम का दुरुपयोग कर सकते हैं
हलः सरकार को उपयुक्त सुरक्षा तंत्र बनाना चाहिए और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए पर्याप्त कानूनी और सांस्थानिक व्यवस्थाएं तथा रक्षा उपाय कायम करने चाहिए

इलस्ट्रेशनः नीलांजन दास

दूसरी तरफ भारत बहुत फूंक-फूंक कदम रख रहा है. 2018 में आरबीआइ (भारतीय रिजर्व बैंक) ने क्रिप्टो में व्यापार पर पाबंदी लगा दी थी. मार्च 2020 में सुप्रीम कोर्ट की तीन जजों की पीठ ने इसे रद्द कर दिया. इससे क्रिप्टो व्यापार में फिर नया उछाल आ गया. दुनिया भर की सरकारें विचार कर रही हैं कि ऐसी चीज को नियंत्रण में कैसे लाया जाए जो पूरी तरह नियंत्रण रोकने के लिए ही डिजाइन की गई है. ऐसे में भारत में भी इस चर्चा की शुरुआत होती दिख रही है.

पूर्व वित्त सचिव सुभाष चंद्र गर्ग के अनुसार, क्रिप्टो को लेकर जन नीति से जुड़े कई प्रमुख सरोकार हैं. इनमें सबसे अव्वल क्रिप्टो की असली फितरत को समझना है, क्योंकि ब्लॉकचेन और क्रिप्टोग्राफी टेक्नोलॉजी अपने आप में वैकल्पिक डिजिटल दुनिया है, जो बहुत तेजी से बढ़ रही है और क्रिप्टो प्लेटफॉर्म पर दी जा सकने वाली डिजिटल सेवाओं का लगातार ज्यादा से ज्यादा विस्तार कर रही है. औद्योगिक जमाने की कागजी मुद्रा के मुकाबले डिजिटल मुद्रा के अनगिनत फायदे हैं. मुद्रा जारी करना हालांकि संप्रभु कार्य और जिम्मेदारी है और इन्हें चंद लोगों के हाथों में नहीं दिया जा सकता. जिस तरह किसी भी नई टेक्नोलॉजी से लोग जबरदस्त रोमांचित हो उठते हैं, उसी तरह क्रिप्टो केअसली फितरत और क्षमता की ठोस जानकारी के अभाव में इसके जरूरत से ज्यादा फूला हुआ बुलबुला बन जाने का खतरा है. पूरी संभावना है कि कई निवेशक अपनी असली रकम क्रिप्टो में फूंक देंगे. यही वजह है कि सरकार को निवेशकों और ग्राहकों को सुरक्षा देनी चाहिए. यही नहीं, क्रिप्टो की दुनिया में ज्यादातर आमदनी और पूंजीगत फायदे ''रडार की छत्रछाया'' में कमाए जा रहे हैं. ऐसे में, सरकार को क्रिप्टो और उससे जुड़े कारोबारों के लिए वाजिब कराधान तय करने की जरूरत है. क्रिप्टो के कारोबार में मूल्य संवर्धन, लेन-देन, विकेंद्रीकृत वित्त और दूसरे कारोबारों से हासिल आमदनी और क्रिप्टो मुद्राओं में निवेश से मिले पूंजीगत लाभों पर कर लगाने के बारे में अभी तक कोई स्पष्टता नहीं है.

आखिर में, पूरी संभावना है कि आतंकवादी, धनशोधक और दूसरे असामाजिक तत्व क्रिप्टो पारितंत्र का दुरुपयोग कर सकते हैं. लिहाजा, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए पर्याप्त रक्षाकवच का निर्माण करना अहम और जरूरी है.

क्रिप्टो के अवास्तविक ढंग से ऊंचे मूल्य निर्धारणों ने भी बुलबुले की आशंकाएं पैदा कर दी है. फिनटेक कंपनी यूट्रेड सॉल्यूशंस के सह-संस्थापक और सीईओ कुणाल नंदवाणी

एनएफटी के पीछे आ खड़े हुए स्टार्स

नामी-गिरामी लोग और बॉलीवुड की शख्सियतें एनएफटी के काफिले में सवार हो रही हैं. उनमें से कई लोग तो अपनी संग्रहणीय डिजिटल वस्तुएं एनएफटी नीलामी के जरिए बेच रहे हैं

नॉन-फंजिबल टोकन यानी एनएफटी ने निवेशकों में दीवानगी पैदा कर दी है. यह ज्यादातर डिजिटल माध्यम पर पेंटिंग्स की नीलामी में दिखाई दे रही है. एनएफटी डिजिटल संपत्तियां हैं जो कला, संगीत, इन-गेम आइटमों और वीडियो सरीखी 'अनोखी' चीजों का प्रतिनिधित्व करती हैं. इन्हें क्रिप्टोकरेंसी के जरिए संग्रहणीय वस्तुओं की शक्ल में खरीदा जा सकता है. फरवरी में चर्चित न्यान कैट मीम 300 एथेरियम (करीब 10.4 करोड़ रुपए) में बिकी. न्यान कैट यूट्यूब वीडियो है, जो सबसे पहले अप्रैल 2011 में अपलोड किया गया था और वायरल मीम बन गया.

अक्तूबर में फैशन डिजाइनर मनीष मल्होत्रा ने वजीरएक्स एनएफटी मार्केटप्लेस से हाथ मिलाया और उनकी पांच एनएफटी रचनाएं लॉन्च होने के चंद सेकंड में बिक गईं. इनमें दो स्केच और जीआइएफ थे. कमल हासन और सनी लियोन भी एनएफटी के जरिए डिजिटल मेमोरेबलिया लॉन्च कर आभासी दुनिया में प्रवेश कर गए हैं. हासन ने एक प्रेस बयान में कहा, ''मैं डिजिटल और भौतिक दुनिया के उभरते उस चौराहे की खोजबीन करके उत्साहित हूं जो मेटावर्स के रूप में लोकप्रिय हो रहा है.''

नवंबर में अभिनेता अमिताभ बच्चन ने अपने एनएफटी संग्रह *मधुशाला* की नीलामी की. यह उनके पिता हरिवंश राय बच्चन की लिखी और अभिनेता बेटे की आवाज में रिकॉर्ड कविताओं का संग्रह है. बच्चन के एनएफटी लॉन्च को संभालने वाली आरऐंडडी टेक्नोलॉजी फर्म गार्जियन लिंक के मुताबिक, नीलामी में कुल 9,66,000 डॉलर (करीब 7.18 करोड़ रुपए) आए. बच्चन कहते हैं, ''डिजिटाइजेशन की इस दुनिया में एनएफटी ने अपने प्रशंसकों के साथ पहले से भी ज्यादा जुड़ने के अवसरों का एक नया संसार खोला है.''

हाल में गायक सोनू निगम ने डिजिटल मनोरंजन और टेक्नोलॉजी कंपनी जेटसिंथेसिस के साथ मिलकर एक एनएफटी सीरीज शुरू की, जिसमें उनकी डायरी में खुद उनके हाथों से लिखे उनके लोकप्रिय गानों की गीत रचनाओं के साथ उनका बिल्कुल पहला अंग्रेजी गाना भी शामिल है.

ज्यादा से ज्यादा सितारे क्रिप्टो प्लेटफॉर्म पर समर्थन की मोहर लगाते जा रहे हैं. इनमें सलमान खान (शॉर्ट वीडियो ऐप चिंगारी का क्रिप्टो टोकन ग़ारी), आयुष्मान खुराना (कॉइनजीसीएक्स) और रणवीर सिंह (कॉइनस्विच कुबेर) भी हैं. खान ने 10 नवंबर को ऐलान किया कि वे जल्दी ही अपना एनएफटी लॉन्च करेंगे. **—सुहानी सिंह**

क्रिप्टो के इर्दगिर्द रचे गए प्रचार के खिलाफ आगाह करते हैं. यह प्रचार इसके पीछे किसी बुनियादी मजबूती की बजाए बीते साल इसके मूल्य में आए उछाल पर टिका है. वे कहते हैं, ''इसे क्रिप्टोकरेंसी के तौर पर ईजाद किया गया, जिसका मतलब है कि आप सरकार की ओर से अधिकृत केंद्रीय विनियमित व्यवस्था के समानांतर किसी को धन भेज सकते हैं. मगर ऐसा कतई नहीं हो रहा है. इसकी बजाए हर कोई कॉइन की जमाखोरी कर रहा है ताकि उन्हें बाद में ऊंची कीमत पर बेच सके.'' नंदवाणी इस समूची व्यववस्था के उस स्वरूप पर भी सवाल खड़े करते हैं, जिसे इसके समर्थक ''विकेंद्रीकृत'' बताते हैं. वे कहते हैं, ''ज्यादातर क्रिप्टो के बीचोबीच एक सीईओ है और वे खुद अपना बेहतर मुनाफा बनाने पर काम कर रहे हैं. लिहाजा, इस तथाकथित विकेंद्रीकरण में बहुत ज्यादा केंद्रीकरण है.''

क्रिप्टो की गुत्थी सुलझाना

कई देश क्रिप्टो को वैध मुद्रा का दर्जा देने में आनाकानी कर रहे हैं तो उसके मूल में उनकी यह आशंका है कि यह कहीं उनकी संप्रभु मुद्राओं को लेन-देन के साधन के रूप में बेदखल न कर दे. मगर सरकार समर्थित डिजिटल मुद्रा के काफी समर्थक हैं. भारत में डिजिटल भुगतान का बहुत विशाल पारितंत्र पहले से ही है, जिसमें मूल्य के हिसाब से 95 फीसद से ज्यादा भुगतान डिजिटल हैं जो यूपीआइ (यूनाइफाइड पेमेंट इंटरफेस) और आइएमपीएस (तत्काल भुगतान सेवा) से किए जाते हैं. हालांकि मूल्य के लिहाज से ज्यादातर भुगतान अब भी भौतिक रूप में ही किए जाते हैं. ठीक यहीं ज्यादा बहुमुखी और इस्तेमाल में ज्यादा आसान डिजिटल मुद्रा अपनी भूमिका अदा कर सकती है. लेन-देन के लिए डिजिटल वॉलेट का इस्तेमाल करते हुए (जो भारत में बैंक खाते से होने वाले डिजिटल भुगतान से अलग हैं) चीन ठीक यही प्रयोग कर रहा है.

दूसरे विशेषज्ञ क्रिप्टो के कई फायदे गिनाते हैं. क्रिप्टो एक्सचेंज जेबपे के सीईओ राहुल पगड़ीपति बताते हैं कि बिटकॉइन ने किस तरह विकेंद्रीकृत, तिहरी प्रविष्टि वाली लेखा पद्धति और मूल्य हस्तांतरण व्यवस्था की शुरुआत की है, जो मुनाफे की खातिर जन नीति के साथ छेड़छाड़ को कम करती है, भ्रष्टाचार से लड़ती है और मुद्रास्फीति का मुकाबला करती है. इसकी सभी अंतर्निहित टेक्नोलॉजी और अनेक क्षेत्रों में उनके प्रयोग की जबरदस्त संभावनाएं भी हैं. कंसल्टिंग फर्म प्राइसवॉटरहाउसकूपर्स के मुताबिक, क्रिप्टोकरेंसी दरअसल टेक्नोलॉजी से संचालित बाजारों के एक नए दौर की शुरुआत दर्शाती है. इन बाजारों में पारंपरिक बाजार रणनीतियों, लंबे समय से चली आ रही कारोबारी प्रथाओं और स्थापित नियामकीय नजरिये का

कायापलट करने की क्षमता है, जिससे उपभोक्ता और व्यापक रूप से अर्थव्यवस्था को फायदा होगा. फर्म यह भी कहती है कि क्रिप्टो मुद्राओं में उपभोक्ताओं को किसी भी जगह, किसी भी समय वैश्विक भुगतान प्रणालियों तक पहुंचने देने की क्षमता है. इसमें भागीदारी को कर्ज का इतिहास और बैंक खाता होने सरीखे कारकों की बजाए केवल एक चीज—टेक्नोलॉजी तक पहुंच—ही रोकती है. वित्तीय सेवाओं में इसका मतलब होगा बैंक से बैंक को कहीं सस्ता धन हस्तांतरण और खुदरा बाजार में ज्यादा आसान खरीद और क्रेडिट कार्ड के जरिए लेन-देन के मुकाबले कम लागत. इसकी बदौलत कई लोगों ने डिजिटल टोकन आधारित धन उगाही के जरिए शुरुआती चरण के टेक्नोलॉजी स्टार्ट-अप में निवेश किया. यह कई पारंपरिक नियामकीय खतरों को दरकिनार कर देती है और इसके जरिए आप नकदी की जगह कपड़े, खिलौने या लैपटॉप और अन्य चीजें भेज पाते हैं.

गर्ग कहते हैं, ''क्रिप्टो टेक्नोलॉजी ईकोसिस्टम बहुत तेजी से विकसित हो रहा है. हर रोज संभावनाशील नए उत्पाद या सेवाएं आ रही हैं. संभावनाएं तो वाकई जबरदस्त हैं.'' दुनिया भर में केंद्रीकृत डेटाबेस की डिजिटल अर्थव्यवस्था का जीडीपी इस वक्त 5 ट्रिलियन डॉलर (370 लाख करोड़ रु.) से अधिक हो गया है, वहीं विकेंद्रीकृत या क्रिप्टो की डिजिटल अर्थव्यवस्था के जीडीपी का फिलहाल कोई अनुमान नहीं है. वे कहते हैं कि क्रिप्टो परिसंपत्तियों के पूंजी बाजार मूल्य निर्धारण को अर्थव्यवस्था/जीडीपी में उसका योगदान नहीं मान लेना चाहिए. मगर जीडीपी में विकेंद्रीकृत डिजिटल और क्रिप्टो टेक्नोलॉजी का योगदान तेजी से बढ़ने की संभावना है. वे यह भी कहते हैं, ''मैं नहीं मानता कि विकेंद्रीकृत क्रिप्टो व्यवस्था, केंद्रीकृत डेटाबेस डिजिटल अर्थव्यवस्था को बड़े पैमाने पर बेदखल कर देगी, पर इसका इस्तेमाल उन ज्यादातर क्षेत्रों में फैलने की संभावना जरूर है जिनमें फिलहाल कारोबार खड़े करने और चलाने के लिए केंद्रीकृत डेटाबेस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है.''

उनके अनुसार, भारत को सभी क्षेत्रों और खासकर सूचना प्रौद्योगिकी और वित्तीय क्षेत्रों में क्रिप्टो डेटाबेस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए उत्पादों, सेवाओं और परिसंपत्तियों का निर्माण करने के लिए समर्थ बनाने और ताकत देने वाले पारितंत्र के निर्माण पर ध्यान देना चाहिए.

सिंघल मानते हैं कि आने वाले कल के टेक्नोलॉजी दिग्गज ब्लॉकचेन के इस्तेमाल से आएंगे और भारत से आएंगे. वे कहते हैं, ''आज भारत टेक्नोलॉजी का आयातक है. कारोबार शुरू कर रहे किसी भी शख्स को ऐसी टेक्नोलॉजी के लिए भारी कीमत अदा करनी पड़ती है और धन देश से बाहर चला जाता है. मगर अब हमारे सामने मौका है जब हम अपने यहां ऐसी टेक्नोलॉजी का निर्माण कर सकते हैं और शुद्ध निर्यातक बन सकते हैं.''

आरबीआइ के गवर्नर शक्तिकांत दास यह दलील मानने को राजी नहीं हैं. उनके अनुसार, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कोई नई नहीं है. यह 10 सालों से है. उन्हें कोई संदेह नहीं कि यह बढ़ेगी और इसके लिए उसे क्रिप्टो की जरूरत नहीं है.

तो सरकार और क्रिप्टो समर्थक दोनों की ही यह राय बन रही है कि क्रिप्टो को व्यापार के लिए परिसंपत्ति के रूप में काम करने देना चाहिए. सिंघल कहते हैं, ''संप्रभु राष्ट्र के रूप में हम मुद्रा का नियंत्रण सरकार के हाथों से बाहर नहीं जाने दे सकते.'' मगर क्रिप्टो महज मुद्रा से कहीं ज्यादा हो गई है. वे कहते हैं, ''मुद्रा होने से यह परिसंपत्ति वर्ग होने की तरफ बढ़ गई है.'' सरकार भी सहमत दिखती है. हालांकि इसके साथ वह नियामकीय देखरेख भी चाहेगी.

पनवेल, नवी मुंबई के डिजिटल मार्केटिंग आंत्रप्रेन्योर, 43 वर्षीय आनंद महेश कहते हैं, ''नियम-कायदों और जो निर्दिष्ट खुलासे करने पड़ते हैं उनके बारे में स्पष्टता से मुझ जैसे निवेशकों को मदद मिलेगी.'' महेश ने सात महीने पहले क्रिप्टो में निवेश शुरू किया था और दो क्रिप्टो एक्सचेंज के मार्फत अब तक करीब 2.2 लाख रुपए लगाए हैं. वे कहते हैं, ''मैं अपना कोई भी निवेश लंबे समय तक कायम नहीं रखता. अगर मुझे 25-30 फीसद रिटर्न भी मिल जाता है तो बाहर निकल आता हूं.'' उनका क्रिप्टो पोर्टफोलियो बिटकॉइन और एथेरियम सरीखे लंबे वक्त के निवेशों, जो उनके मुताबिक ''स्थिर'' हैं, और सोलाना, डॉजकॉइन, रिपल, लाइटकॉइन और कार्डानो सरीखे छोटे वक्त के निवेशों का मिश्रण है.

“निवेशकों ने इक्विटी बाजारों में निवेश का अपना सफर शुरू करते वक्त जिस तरह खुद को शिक्षित किया था, ठीक उसी तरह उन्हें चाहिए कि इस परिसंपत्ति वर्ग के बारे में भी अपने को शिक्षित करें”

संजय मेहता

संस्थापक और पार्टनर, 100एक्स वीसी

शुरुआती स्टार्ट-अप में निवेश करने वाली वेंचर कैपिटल फर्म 100एक्स वीसी के संस्थापक और पार्टनर संजय मेहता मानते हैं कि एक्सचेंजों और वॉलेट कंपनियों के सुझाए सुरक्षा नियमों का पालन और एहतियात बरतने की जिम्मेदारी निवेशकों के कंधों पर है. वे कहते हैं, ''निवेशकों ने इक्विटी बाजारों में निवेश का अपना सफर शुरू करते वक्त जैसे खुद को शिक्षित किया था, ठीक उसी तरह उन्हें चाहिए कि इस परिसंपत्ति वर्ग के बारे में भी अपने को शिक्षित करें. बैंकों ने सुरक्षा के ढेर सारे उपाय किए हैं, इसके बावजूद हम ऑनलाइन बैंकिंग चोरियों और फिशिंग हमलों के बारे में आए दिन मीडिया में पढ़ते हैं.''

मसलन, कर्नाटक पुलिस ने भारतीय एक्सचेंजों को कथित तौर पर हैक करने और ''बग का फायदा उठाकर'' बिटकॉइन चुराने पर 26 साल के एक शख्स को हाल ही में हिरासत में लिया. खबरों की मानें तो बड़े क्रिप्टो एक्सचेंजों ने साइबर हमलों के कम से कम दो-तीन बड़े मामले देखे हैं, जिनमें वॉलेट हैक हो जाने के बाद निवेशक अपनी क्रिप्टो पूंजी गंवा बैठे.

इसमें शक नहीं कि क्रिप्टो मुद्राओं ने खासा रोमांच पैदा कर दिया है. मगर किसी भी दूसरे व्यसन की तरह संयम ही कुंजी है. लोगों की तरफ से, प्रमोटरों की तरफ से और सरकार की तरफ से नियमन ही मुद्रा के रूप में क्रिप्टो को बनाए रखने का एकमात्र तरीका है. ■

INDIA TODAY

BREAKING NEWS

JUST A TAP AWAY

9:41

INDIA TODAY

LIVE

TOP NEWS VIDEOS PROGRAMMES

TOP STORIES

LOK SABHA 2019

Narendra Modi Live: By Congress-mukt India we will fulfil Gandhi's dream

PM Narendra Modi was speaking in Lok Sabha

DOWNLOAD THE APP NOW

AVAILABLE ON

उग्रवाद की वापसी!

म्यांमार सीमा के पास एक सैन्य काफिले पर भीषण हमले ने राज्य में हालिया अतीत में कायम शांति को छिन्न-भिन्न कर दिया है और भारत में सबसे लंबे चलने वाले विद्रोहों में से एक को लेकर नए सवाल खड़े कर दिए हैं

संदीप उन्नीथन और कौशिक डेका

नवंबर की 13 तारीख की सुबह थी. 41 वर्षीय कर्नल विप्लव त्रिपाठी, अपनी 33 वर्षीया पत्नी अनुजा और आठ साल के बेटे अबीर के साथ काली महिंद्रा बोलेरो जीप में सवार होकर मणिपुर के चुराचांदपुर जिले के लिए रवाना हुए. परिवार 1,643 किमी लंबी म्यांमार सरहद से कुछ किलोमीटर दूर बेहियांग टी गांव में रात्रि प्रवास करके लौट रहा था. इस सरहद की रखवाली असम राइफल्स करती है. उसकी 46वीं बटालियन के कमांडिंग अफसर कर्नल त्रिपाठी और उनके परिवार के साथ तीन मारुति जिप्सियों में दर्जन भर हथियारबंद सिपाही थे. वे गांव में सामुदायिक मेल-मिलाप के कार्यक्रम से लौट रहे थे. ऐसी यात्रा में अफसर आम तौर पर अपने परिवार को साथ ले जाते हैं.

यह छोटा-सा काफिला अभी गांव से निकला ही था कि वह संकरी सड़क एक के बाद एक धमाकों से दहल गई. घने जंगलों में घात लगाकर इंतजार कर रहे उग्रवादियों ने ऑटोमैटिक बंदूकों और राइफल ग्रेनेड से वाहनों पर ताबड़तोड़ गोलियां दागीं. कुछ मिनट बाद जब गोलाबारी रुकी, कर्नल त्रिपाठी और उनका परिवार बेजान पड़ा था. चार अन्य सैनिक मारे गए और छह गंभीर रूप से घायल हुए.

दो उग्रवादी संगठनों, पीपल्स लिबरेशन आर्मी (पीएलए) और मणिपुर नगा पीपल्स फ्रंट (एमएनपीएफ), ने उसी दिन एक बयान जारी करके हमले की जिम्मेदारी ली. मणिपुर भारत के सबसे लंबे समय से चले आ रहे विद्रोहों में से एक का गवाह रहा है. यहां कम से कम 40 प्रतिबंधित भूमिगत संगठन सक्रिय हैं. फिर भी पिछले छह साल से उग्रवादी धड़ों ने इतना दुस्साहसी हमला नहीं किया था. इससे पहले बड़ा हमला 4 जून 2015 को हुआ था, जब यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ वेस्टर्न साउथईस्ट एशिया (यूएलएफडब्ल्यूएसए) के अलगाववादियों ने चंदेल जिले में भारतीय सेना के काफिले पर घात लगाकर हमला किया और 18 सैनिकों को मार डाला था.

जानलेवा सफर
कर्नल त्रिपाठी इसी जीप में अपने परिवार के साथ सवार थे

साल 2021 में मणिपुर में उग्रवाद में बढ़ोतरी देखी गई है. इस साल यहां अब तक 162 आतंकवादी घटनाएं और 24 लोगों की मौत हो चुकी हैं. वहीं, आतंकी घटनाएं साल 2014 में 700 से घटकर 2020 में 113 पर आ गई थीं

खतरनाक गठजोड़

मणिपुर के अलगाववादी संगठन अपनी विभिन्न जनजातीय पहचान के आधार पर बंटे हुए हैं- नगा, कुकी और मेइतेइ. 13 नवंबर के हमले की जिम्मेदारी इनमें से दो जनजातीय समुदाय के अलगाववादियों ने ली है

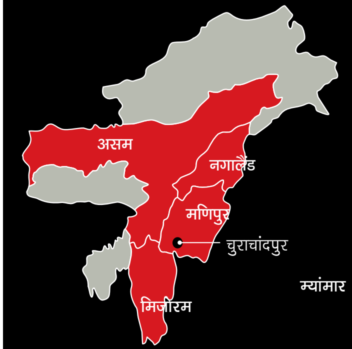

4 जून, 2015

चंदेल जिले में भारतीय सेना के एक काफिले पर हमला करके यूएलएफडब्ल्यूएसए ने 18 सैनिकों को मार डाला. सेना ने म्यांमार के भीतर तक घुसकर जवाबी हमला किया और एनएससीएन(के) के शिविरों को निशाना बनाया

13 नवंबर, 2021

चूराचांदपुर जिले में हमले में असम राइफल्स के कर्नल, उनकी पत्नी और बेटा तथा चार अन्य सैनिक मारे गए

13 नवंबर के हमले के लिए जिम्मेदार उग्रवादी समूह

मणिपुर नगा पीपल्स फ्रंट (एमएनपीएफ)

मणिपुर के दो भूमिगत संगठनों–मणिपुर नगा रिवॉल्यूशनरी फ्रंट (एमएनआरएफ) और यूनाइटेड नगा पीपल्स काउंसिल (यूएनपीसी) का साल 2013 में विलय करके इस संगठन को बनाया गया है. यह समूह नगा लोगों की संप्रभुता और उनके आत्मनिर्णय के अधिकार के लिए संघर्ष करने का दावा करता है

पीपल्स लिबरेशन आर्मी (पीएलए)

इस उग्रवादी समूह में मेइतेइ समुदाय के लोग शामिल हैं. इस उग्रवादी समूह की स्थापना 25 सितंबर, 1978 को एन. बिशेश्वर सिंह के नेतृत्व में हुआ था. यह समूह स्वतंत्र मणिपुर के लिए लड़ रहा है. यह माओवादी चीन से प्रेरित हैं और भारत सरकार की शांति वार्ता से अलग हट चुका है

राज्य के सिंघात सबडिविजन में 13 नवंबर की हत्याओं ने बीते कुछ साल से चली आ रही थोड़ी-बहुत शांति को छिन्न-भिन्न कर दिया है. यह घटना ऐसे दौर में हुई जब इलाका उथल-पुथल से गुजर रहा है. म्यांमार की सेना ने 1 फरवरी को सरकार का तख्तापलट करके लोकतांत्रिक ढंग से चुने गए नेताओं को हिरासत में ले लिया. सैन्य शासकों के अत्याचारों से त्रस्त होकर भाग रहे हजारों लोगों का मणिपुर सहित भारत के सरहदी राज्यों में तांता लग गया. इस अफरातफरी में म्यांमार के शिविरों में डेरा डाले पीएलए और एमएनपीएफ सरीखे धड़ों को खुलकर काम करने का मौका मिल गया.

खुली हुई लंबी सरहद

पाकिस्तान और बांग्लादेश से सटी सरहदों पर तो काफी जगह कांटेदार बाड़ लगी हैं और तेज रोशनी से जगमगाती पट्टियां भी हैं. मगर म्यांमार से सटी भारत की सीमा पर बाड़ नहीं है, सीमा दर्शाने वाले खंभे भर खड़े हैं. राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड (एनएसएबी) के सदस्य लेफ्टिनेंट जनरल एस.एल. नरसिंहन (सेवानिवृत्त) कहते हैं, ''म्यांमार की सरहद से एक दिन में आने-जाने की दूरी पर कोई भी जगह असुरक्षित है. वे (उग्रवादी) आ सकते हैं, घात लगाकर हमला कर सकते हैं और वापस जा सकते हैं.''

साल 2015 के हमले के बाद भारतीय सेना की विशेष इकाइयों ने बेहद फुर्ती से म्यांमार के भीतर घुसकर नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नगालैंड (खापलांग) या एनएससीएन(के) के शिविरों पर हमले किए थे. पिछले साल मई में पूर्वी लद्दाख की सरहद पर चीन के साथ तनाव की वजह से भारतीय सेना को इस इलाके से विशेष बलों को बुलाकर उत्तर में चीन के साथ लगी वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) पर हजारों किलोमीटर के क्षेत्र में तैनात करना पड़ा.

सेना के शीर्ष अफसर चूड़ाचांपुर के हमले में बाहरी मदद की संभावना से इनकार नहीं करते. चीन उत्तरपूर्व के विद्रोही धड़ों को खुला और छिपा समर्थन देता रहा है. पिछले अक्तूबर में गुवाहाटी के यूएपीए (गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम कानून) पंचाट में दाखिल एक बेलाग हलफनामे में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बताया था कि परेश बरुआ के यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम (इंडिपेंडेंट) या उल्फा (आइ) का अड्डा चीन के यूनान प्रांत के रुइली में था. 13 नवंबर

के हालिया हमले की जांच कर रही सुरक्षा एजेंसियों को अब तक केवल एक अहम सुराग मिला है. यह एक सैटेलाइट फोन है, जो कर्नल त्रिपाठी और उनके सिपाहियों पर हमले के आसपास के वक्त तक नजदीकी गांवों में सक्रिय था.

बागी धड़े फिर एकजुट हो रहे हैं?

विद्रोह से मुकाबले के लिए सशस्त्र बल दशकों से मणिपुर में तैनात हैं. इम्फाल नगर परिषद इलाके को छोड़कर पूरे राज्य में सशस्त्र बल (विशेषाधिकार) अधिनियम 1958 लागू है. हाल के हमले ने कई लोगों को हैरत में डाल दिया, क्योंकि सशस्त्र बल कर्मी के परिवार के सदस्यों को पहली बार निशाना बनाया गया है. बाद में जिम्मेदारी लेने वाले दोनों उग्रवादी धड़ों ने कहा कि उन्हें काफिले में परिवार के सदस्यों की मौजूदगी का पता नहीं था. हालांकि, घात बिछाने वाले उग्रवादी कर्नल त्रिपाठी की आसन्न यात्रा के बारे में साफ तौर पर जानते थे और उनके पास हमले की जगह तय करने, हथियारबंद काडर को लाने और आईईडी (इंप्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइसें) लगाने का वक्त था.

विद्रोहियों ने जो जगह चुनी, वह भी अजीबोगरीब है. पीएलए में इम्फाल घाटी के जातीय मेइतेइयों का दबदबा है और चुराचांदपुर में मजबूत मौजूदगी नहीं है. जिले में कुकी, पाइते और जोमी जनजातियों के उग्रवादी धड़े ज्यादा सक्रिय हैं. इम्फाल के दक्षिण में 65 किमी दूर और म्यांमार सीमा पर बसा चुराचांदपुर जिला 2003 में भारतीय सेना के ऑपरेशन ऑल क्लियर के बाद से ही विद्रोही हमलों से काफी मुक्त रहा है. इलाके के ज्यादातर आदिवासी उग्रवादी धड़े केंद्र सरकार के साथ शांति वार्ता कर रहे हैं, जो अलग-अलग चरणों में हैं, और उन्होंने अपनी कार्रवाइयां स्थगित कर दी हैं. विशेषज्ञ यह जानने को उत्सुक हैं कि क्या यह हमला विद्रोही धड़ों और इस मामले में पीएलए और एमएनपीएफ के बीच नए गठजोड़ के उभरने का संकेत है.

यह अभी साफ नहीं है कि क्या चुराचांदपुर में सक्रिय कूकी धड़े ने इस हमले को दबा-छिपा समर्थन दिया है या इस हमले से वे भी हैरान रह गए. वहीं, मणिपुर के मुख्यमंत्री एन. बीरेन सिंह ने कहा, ''उग्रवादी धड़ों की तरफ से यह हताशा और अस्तित्व की लड़ाई का संकेत है. राज्य में उग्रवाद के लिए जरा भी समर्थन नहीं है. ऐसे में अपना वजूद दिखाने के लिए ये धड़े साथ आ रहे हैं.''

> “यह संकेत है कि उग्रवादी समूह हताश हैं और अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रहे हैं. राज्य में उग्रवाद के लिए जरा भी समर्थन नहीं है. ऐसे में अपना वजूद दिखाने के लिए ये धड़े अब एक-साथ आ रहे हैं”
>
> **एन. बीरेन सिंह**
> मणिपुर के मुख्यमंत्री

इम्फाल घाटी के दूसरे मेइतेइ धड़ों की तरह पीएलए ने भी भारत सरकार के साथ न तो किसी तरह के युद्धविराम समझौते पर दस्तखत किए हैं और न ही ऐसी कोई मंशा जताई है. फिर भी मणिपुर को अलग करने के लिए संघर्षरत यह धड़ा पिछले पांच या छह साल से सुस्त पड़ा था.

म्यांमार कारक

पीएलए मुख्यतः म्यांमार से काम कर रहा है और इसे तीन नेता चलाते हैं. ये हैं प्रेसिडेंट और 'लेफ्टिनेंट जनरल' आइरेंगबन चाओरीन उर्फ भोरेत, वाइस-प्रेसिडेंट और 'आर्मी चीफ' एम.एम. नगोउबा उर्फ प्रबीन शर्मा, और जनरल सेक्रेटरी सनासम गुनेन उर्फ फाल्गुनी. माना जाता है कि ये तीनों उम्र के सत्तरवें पड़ाव में हैं. ये मंडाले में रहते हैं और ट्रांसपोर्ट तथा सुपारी का कारोबार करते हैं.

मणिपुर की सरहद पर म्यांमार के तामु इलाके में स्थित शिविरों में पीएलए के कुछ सौ कार्यकर्ता हैं. भारतीय और म्यांमार के बलों ने पहले सीमा-पार अभयारण्यों में रह रहे विद्रोहियों के खिलाफ संयुक्त कार्रवाइयां की हैं. रणनीतिक मामलों के विश्लेषक ब्रह्मा चेलानी कहते हैं, ''म्यांमार की सीमा पर बसे राज्य में असम राइफल्स के काफिले पर टूटकर अलग हुए गुरिल्ला धड़े का हमला याद दिलाता है कि खुली सीमाओं को देखते हुए भारत के लिए म्यांमार के साथ विद्रोह-विरोधी सहयोग कितना अहम है और नई दिल्ली म्यांमार के सैन्य शासकों के खिलाफ अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के संयुक्त प्रयासों में शामिल नहीं हो सकती.''

एमएनपीएफ 2013 में मणिपुर के दो नगा भूमिगत संगठनों—मणिपुर नगा रिवॉल्यूशनरी फ्रंट (एमएनआरएफ) और यूनाइटेड नगा पीपल्स काउंसिल (यूएनपीसी)—का विलय करके बनाया गया था. कहा गया था कि नया संगठन 'नगा क्रांतिकारियों की ढुलमुल हालत' की वजह से 'नगा लोगों की संप्रभुता और उनके आत्मनिर्णय के अधिकार की बहाली' के उद्देश्य से बनाया गया था.

मणिपुर के कई विद्रोही धड़ों ने सरकार के साथ अलग-अलग कार्रवाई-स्थगन समझौतों पर दस्तखत किए हैं. ऐसे में बीते छह साल में राज्य आतंकी घटनाओं में अच्छी-खासी कमी का गवाह रहा है. ये घटनाएं साल 2014 में 700 से घटकर साल 2020 में 113 पर आ गईं. उसके बाद फिर राज्य में विद्रोही गतिविधियां बढ़ती दिखाई दे रही हैं. इस साल अब तक 162 विभिन्न आतंकी घटनाओं में 24 लोगों की जान जा चुकी हैं. बीते दो साल में मृतकों की गिनती दहाई के आंकड़े तक भी नहीं पहुंची थी.

मणिपुर में अगले साल चुनाव होने हैं. पूरी संभावना है कि विपक्षी पार्टियां यह मुद्दा उठाएंगी. सत्तारूढ़ भाजपा का कहना है कि 13 नवंबर का हमला आतंकी धड़ों की हताशा का संकेत है. पार्टी के नेता दावा करते हैं कि इन हत्याओं का मकसद भाजपा की अगुआई वाली सरकार की छवि बिगाड़ना है, क्योंकि उसने विद्रोह के खिलाफ कड़ाई बरती है. भाजपा के एक बड़े नेता कहते हैं, ''मकसद यह जताना भी हो सकता है कि चीजें उतनी अच्छी नहीं हैं जितनी बताई जा रही हैं. विपक्षी पार्टियां यह कहकर इसका फायदा उठाने की कोशिश करेंगी कि भाजपा राज्य में शांति बनाए रखने में नाकाम हो गई है.''

राज्य सरकार हालांकि ज्यादा फिक्रमंद नहीं दिख रही. मुख्यमंत्री बीरेन सिंह दावा करते हैं कि उग्रवादी म्यांमार से दबे पांव घुसे. मुख्यमंत्री कहते हैं, ''सरहद पर हम और ज्यादा सतर्क रहेंगे और ऐसी कायराना कार्रवाई दोहराने नहीं देंगे.'' मगर हथियारबंद विद्रोही जब खुली सरहद के उस पार बैठे हों, तो केवल अनुमान ही लगाया जा सकता है कि ऐसा हो पाएगा या नहीं. ■

FROM CABIN CRITICS TO THOSE MAKING INDIA SHINE

We believe in just one thing. Your voice matters. Irrespective of who you are, where you come from, where you stand, what you do and, who you support. We are the India Today Group. Where every voice finds its right. And every right finds a voice.

WE'RE ALWAYS IN CONVERSATION WITH YOU.

INDIA TODAY GROUP

INDIA'S DEMOCRATIC NEWSROOM

शीर्ष पर हमला

भारत में माओवादी उग्रवाद के लिए नवंबर बहुत ही खराब महीना साबित हुआ. चार शीर्ष नेताओं का काम तमाम होने के बाद उनका नेतृत्व चरमरा गया

अमरनाथ के. मेनन, किरण डी. तारे और अमिताभ श्रीवास्तव

एक बड़ा झटका

भाकपा (माओवादी) की केंद्रीय कमेटी के छह सदस्य अब गिनती से बाहर हो गए हैं

मिलिंद तेलतुंबड़े उर्फ दीपक, 61 वर्ष
यह 12 नवंबर , 2021 को महाराष्ट्र पुलिस के साथ मुठभेड़ में मारा गया

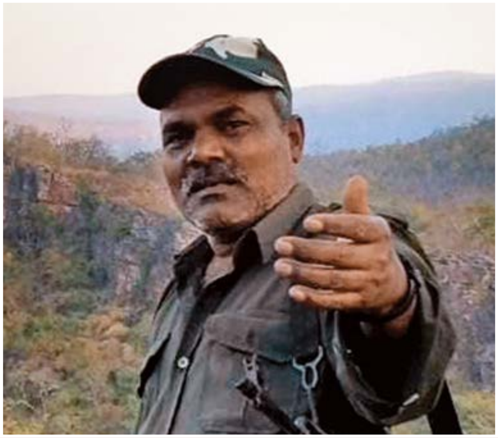

प्रशांत बोस उर्फ किशनदा, 82 वर्ष
11 नवंबर, 2021 को झारखंड में गिरफ्तार

शीला मरांडी उर्फ शोभा, 64 वर्ष
11 नवंबर, 2021 को झारखंड में गिरफ्तार

बी.जी. कृष्णमूर्ति उर्फ विजय, 51 वर्ष
9 नवंबर, 2021 को केरल में गिरफ्तार

अक्किराजू हरगोपाल उर्फ रामकृष्ण या आरके 63 वर्ष
किडनी फेल होने की वजह से 14 अक्तूबर, 2021 को छत्तीसगढ़ में मौत

हरिभूषण उर्फ यापा नाराया या लक्मु दादा, 52 वर्ष
कोविड-19 की वजह से 21 जून, 2021 को छत्तीसगढ़ में मौत

नवंबर की 13 तारीख को, जब गढ़चिरौली पुलिस को खुफिया जानकारी मिली कि महाराष्ट्र-छत्तीसगढ़ सीमा के पास ग्यारपट्टी के जंगलों में प्रतिबंधित माओवादी इकट्ठा हुए हैं, तो उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी कि एक इनामी माओवादी उनकी पकड़ में आएगा. लगभग 10 घंटे तक सी-60 फोर्स के जवानों ने माओवादियों को मुठभेड़ में उलझाए रखा. उनमें से 26 माओवादी मारे गए. मरने वालों में 61 वर्षीय मिलिंद तेलतुंबड़े भी था, जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) की केंद्रीय समिति का सदस्य था. केंद्रीय समिति एक कोर समूह है, जो पूरे भारत में अलग-अलग इलाकों में माओवादियों और उनके समर्थकों के अलग-अलग समूहों की गतिविधियों का समन्वय करता है. वह वही व्यक्ति था, जिसने कथित तौर पर महाराष्ट्र-मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ (एमएमसी) क्षेत्र में माओवादियों का नेतृत्व किया था. सुरक्षा अधिकारियों का मानना है कि तेलतुंबड़े के मारे जाने से इलाके में माओवादी काफी कमजोर हो गए हैं.

एक दिन पहले, 12 नवंबर को सुबह होने से पहले, झारखंड पुलिस और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) की एक संयुक्त टीम ने झारखंड के सरायकेला-खरसावां जिले के गिद्दीबेड़ा टोल गेट पर एक सफेद महिंद्रा स्कॉर्पियो को रोका; उसमें बैठे लोगों को दूसरी कार में बिठाकर रांची ले जाया गया. एक घंटे की लगातार पूछताछ के बाद, 82 वर्षीय वयोवृद्ध प्रशांत बोस ने खुद को देश के मोस्ट वांटेड माओवादियों में से एक किशनदा बताया. वह गिरिडीह के पारसनाथ पहाड़ियों में अपने ठिकाने से लौट रहा था और पश्चिम बीरभूम के सारंडा साल जंगल की ओर जा रहा था, जहां उसका कई वर्षों से अड्डा है. केंद्रीय समिति और भाकपा (माओवादी) पोलितब्यूरो का सदस्य बोस अपनी 64 वर्षीया पत्नी शीला मरांडी और चार अन्य माओवादियों के साथ यात्रा कर रहा था. शीला केंद्रीय समिति की पहली महिला सदस्य है. बोस की गिरफ्तारी (उस पर 1 करोड़ रु. का इनाम था) को 24 नवंबर, 2011 को पश्चिम बंगाल के पश्चिम मिदनापुर जिले के बरीशोल जंगल में पोलितब्यूरो के सदस्य माल्लोजुला कोटेश्वर राव उर्फ किशनजी की मुठभेड़ में मौत के बाद सुरक्षाबलों की सबसे बड़ी सफलता के रूप में देखा जा रहा है.

दरअसल, प्रतिबंधित भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादियों) के लिए नवंबर एक बुरा महीना रहा है. केरल पुलिस के आतंकवाद निरोधी दस्ते (एटीएस)

संगठन

भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी)

यह 2004 में पीपल्स वार ग्रुप और माओवादी कम्युनिस्ट सेंटर (एमसीसी) के विलय से बना

क्षमताः करीब 8,000- 10,000 हथियारबंद काडर

महासचिव

नामबाला केशव राव उर्फ बासवराज
2017 में नियुक्त

↓

केंद्रीय कमेटी

28 सदस्य

नवंबर में मिलिंद तेलतुंबड़े की मौत, तीन अन्य की गिरफ्तारी और इससे पहले इस साल दो अन्य के निधन से इसकी क्षमता घट गई है

सियासी

पोलितब्यूरो

सर्वोच्च निर्णायक समूह

- ● **नामबाला केशव राव** उर्फ बासवराज (65 वर्ष)
- ● **प्रशांत बोस** उर्फ किशनदा (82 वर्ष)
- ● **मुपल्ला लक्ष्मण राव** उर्फ गणपति (73 वर्ष)
- ● **कटकम सुदर्शन** उर्फ दूला दादा उर्फ आनंद मोहन (63 वर्ष)
- ● **मिसिर बेसरा** उर्फ सुनीरमल (83 वर्ष)

↓

क्षेत्रीय ब्यूरो

↓

राज्य कमेटी

↓

जिला कमेटी

सैन्य

केंद्रीय सैन्य कमिशन

भाकपा (माओवादी) की मुख्य हथियारबंद भाग

मुखियाः नामबाला केशव राव उर्फ बासवराज

↓

राज्य/विशेष जोन कमेटी

↓

क्षेत्रीय सैन्य कमान

↓

जिला कमान

ने 9 नवंबर को वकील से माओवादी बने और केंद्रीय समिति के सदस्य 51 वर्षीय बी.जी. कृष्णमूर्ति उर्फ विजय और एक अन्य माओवादी (दोनों निहत्थे) को पकड़ा, जब वे कर्नाटक से केरल तक सड़क मार्ग से यात्रा कर रहे थे. एटीएस ने उसे कई मामलों में मुकदमा चलाने के लिए राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआइए) को सौंप दिया. केवल पांच दिनों में केंद्रीय समिति के चार सदस्यों को पकड़ना या मारना सुरक्षा बलों के लिए बड़ी उपलब्धि है. पिछले कुछ महीनों में केंद्रीय समिति के दो अन्य सदस्यों की भी मृत्यु हो गई—21 जून को तेलंगाना के 52 वर्षीय हरिभूषण उर्फ यापा नारायण या लक्मू दादा और 14 अक्तूबर को आंध्र प्रदेश के 63 वर्षीय अक्कीराजू हरगोपाल उर्फ रामकृष्ण या आरके की छत्तीसगढ़ के जंगल में बीमार पड़ने के बाद मृत्यु हो गई.

माओवादियों का प्रभाव घट रहा है, वामपंथी-उग्रवादियों की हिंसा का भौगोलिक क्षेत्र 2020 में 53 जिलों तक सिमट गया है जो 2013 में 76 जिलों में फैला था

एएनआइ

मुठभेड़

ग्यारपट्टी जंगलों में 12 नवंबर को मुठभेड़ के बाद बरामद हथियार और सामान

विश्लेषकों का कहना है कि माओवादियों का शीर्ष नेतृत्व बिखरा हुआ है. 2019 में 25 सदस्यों के साथ अंतिम पुनर्गठन के बाद कृष्णमूर्ति सहित उनमें से तीन को इस वर्ष ही केंद्रीय समिति में शामिल किया गया था. एक दशक पहले केंद्रीय समिति में 32 सदस्य हुआ करते थे. इसी तरह, भाकपा (माओवादी) पोलितब्यूरो के सदस्यों की संख्या 12 से घटकर छह हो गई है.

गौरतलब कि हाल के वर्षों में हर जगह सुरक्षा बलों ने बढ़त हासिल की है, सिर्फ छत्तीसगढ़ को छोड़कर, जहां माओवादी कई मौकों पर सेना को मात देने में कामयाब रहे हैं. वामपंथी उग्रवादी हिंसा वर्ष 2013 के 76 जिलों के मुकाबले वर्ष 2020 में 53 जिलों में सिमटकर रह गई है. माओवादी हिंसा की घटनाओं में 70 फीसद की गिरावट आई है, वर्ष 2009 में सबसे ज्यादा 2,258 हिंसक घटनाएं हुई थीं, जो 2020 में घटकर 665 रह गईं. इसी तरह, नागरिकों और सुरक्षा बलों की मृत्यु 2010 के 1,005 के उच्च स्तर से 82 फीसद घटकर 2020 में 183 रह गई.

स्पष्ट रूप से सुरक्षाबलों के मिलकर ऑपरेशन चलाने, बेहतर खुफिया जानकारी और पिछले दशक की तुलना में राज्यों के बीच बेहतर तालमेल का लाभ मिल रहा है. केंद्रीय समिति के सदस्यों के अलावा, माओवादी लगातार आधार के साथ-साथ काडर भी खो रहे हैं, खासकर चार प्रमुख राज्यों—छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, झारखंड और ओडिशा के संकटग्रस्त क्षेत्रों में. काडर को प्रेरित रखने के लिए धन की कमी के कारण भर्ती में तेजी से गिरावट के साथ उनकी संख्या भी घट रही है. छत्तीसगढ़ (जहां ज्यादातर नेतृत्व छिपा हुआ है) से लेकर माओवादी उग्रवाद के उद्गम स्थल तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में नए काडर को भर्ती करने के प्रयास किए गए हैं. दस सदस्यों के साथ दो तेलुगु राज्यों के नेता अब भी केंद्रीय समिति पर हावी हैं, पर हाल में सार्वजनिक आत्मसमर्पण के कारण यहां बहुत लोग नहीं हैं. नई भर्तियां अब ज्यादातर छत्तीसगढ़ में ही हो रही हैं.

राज्यों ने माओवादियों से निपटने के लिए ज्यादातर अपनी-अपनी रणनीतियों पर भरोसा किया है. महाराष्ट्र पुलिस ने अप्रैल, 2018 में हुई पिछली मुठभेड़, जब दो अलग-अलग गोलाबारी में 42 माओवादी मारे गए थे, के बाद से 27 माओवादी नेताओं और उनसे सहानुभूति रखने वालों को गिरफ्तार किया या मार डाला है. पुलिस सूत्रों का कहना है कि पिछले पांच वर्षों में गिरफ्तार या आत्मसमर्पण करने वाले पैदल लड़ाकों की संख्या 300 को पार कर गई है. वे यह भी बताते हैं कि 1980 के दशक में महाराष्ट्र में माओवाद की शुरुआत के बाद से ये सबसे अच्छे नतीजे हैं. पुलिसबल के आधुनिकीकरण और स्थानीय लोगों के साथ संवाद बनाए रखने से पुलिस को माओवादियों की गतिविधियों के बारे में बेहतर खुफिया जानकारी जुटाने में मदद मिली है. महाराष्ट्र के पूर्व पुलिस महानिदेशक प्रवीण दीक्षित सफलता का श्रेय माओवादी नियंत्रित क्षेत्रों में विकास गतिविधियों के साथ-साथ स्थानीय लोगों का दिल जीतने के प्रयास को देते हैं. ''सी-60 फोर्स पूरी तरह से स्थानीय युवाओं से बना है. इस उपलब्धि में उनकी अहम भूमिका रही है.''

झारखंड के डीजीपी नीरज सिन्हा बोस को पकड़ने को अपनी सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक मानते हैं. फरवरी, 2021 में झारखंड के शीर्ष पुलिस अधिकारी के रूप में कार्यभार संभालने के बाद से, उन्होंने आत्मसमर्पण करने वाले कुछ माओवादियों के साथ काम करते हुए लोगों की खुफिया जानकारियों पर ध्यान केंद्रित किया है. बोस की गिरफ्तारी ने पुलिस को भारत में माओवादियों की दुनिया के बारे में नई जानकारी दी है. जब उन्होंने माओवादियों के बारे में दो टीबी (टेरा बाइट) डेटा बरामद किए, तो लगा कि उन्होंने सोने की

मंदार देवधर

जंग को तैयार

गढ़चिरौली के जंगलों में गश्त करते सी-60 कमांडो की फाइल फोटो

खान पा लिया है. झारखंड के एक शीर्ष पुलिस अधिकारी कहते हैं, ''1.51 लाख रु. नकद और चार मोबाइल फोन के अलावा, हमने 2 टीबी डेटा के साथ हार्ड-ड्राइव बरामद की. यह डेटा 'डॉन की डायरी' की तरह है, जैसे अमिताभ बच्चन की फिल्म में था.''

कथित तौर पर डेटा में माओवादियों के बारे में सूक्ष्म जानकारियां हैं. माओवादी अभियानों की जानकारियों से लेकर माओवादी हिंसा के निष्पक्ष विश्लेषण तक—वे कैसे सफल हुए और क्यों विफल हुए—साथ ही माओवादियों के पास विशिष्ट आग्नेयास्त्रों और उन्हें गोला-बारूद प्रदान करने वाले आपूर्तिकर्ताओं के नाम भी हैं. इसमें माओवादी काडर के नाम और तस्वीरें भी हैं, इसके अलावा जिनकी पहचान शहीद के रूप में की गई है और जिनके परिवारों की देखभाल विद्रोहियों की ओर से की जानी है. कथित तौर पर इस डेटा में सभी राज्यों के विवरण हैं और केंद्रीय एजेंसियों के अलावा, उन्हें सभी वामपंथी उग्रवाद प्रभावित राज्यों के पुलिस प्रमुखों के साथ साझा किया जा रहा है. हैरानी नहीं कि बोस की गिरफ्तारी के एक दिन बाद अपने नुक्सान को कम करने के लिए नक्सलियों ने बिहार के गया जिले में चार लोगों को पुलिस-मुखबिर बताकर मार डाला.

इस बीच, ओडिशा सरकार ने एक आकर्षक आत्मसमर्पण और पुनर्वास नीति के साथ अलग कदम उठाया है. हाल ही में, 20 से अधिक युवा माओवादियों ने ओडिशा पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया. आत्मसमर्पण करने वाले माओवादियों को मुआवजा पैकेज के अलावा, राज्य अपने विशेष अभियान समूह (एसओजी) में स्थानीय युवाओं की भी भर्ती करता है, जिन्हें माओवादियों से लड़ने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है. उनकी क्षमताओं में सुधार करते हुए, राज्य युवाओं को माओवादी गुटों में शामिल होने से रोकने पर भी विचार कर रहा है. अधिकारियों का कहना है कि एसओजी ने न केवल स्थानीय युवकों को राज्य के खिलाफ हथियार उठाने से रोका है, बल्कि एक बड़ी शिकायत, बेरोजगारी के निवारण में भी मदद की है. कभी राज्य के 30 में से 15 जिलों में माओवादी सक्रिय थे, जो अब बिखरे हुए हैं और पांच जिलों तक सीमित हैं. ओडिशा सरकार की बहुआयामी रणनीति—कंधमाल, कालाहांडी और कोरापुट क्षेत्रों में मुठभेड़ में हत्याएं (जिससे माओवादी विचारधारा के प्रति आकर्षण खत्म हुआ है) और साथ ही विकास कार्यक्रमों को शुरू करना, ने माओवादियों को बड़े पैमाने पर फिर से संगठित होने से रोका है. विकास, सामाजिक कल्याण और आजीविका संबंधी गतिविधियों ने राज्य को माओवादियों को अलग-थलग करने के साथ-साथ स्थानीय लोगों अपने पाले में लाने में मदद की है. यहां तक कि जनवरी, 2020 में मलकानगिरि में जनतुरै गांव के आदिवासियों ने सड़क-निर्माण का विरोध कर रहे एक माओवादी गंगा माडी को मार डाला. मुख्य सचिव सुरेश महापात्रा कहते हैं, ''हमने बड़े विकास कार्य, सिंचाई, पेयजल, स्वास्थ्य शिविर और बड़ी संख्या में सुरक्षा शिविरों की शुरुआत की है.''

छत्तीसगढ़ अकेला राज्य है, जहां माओवादियों का दबदबा है. पिछले कुछ वर्षों में यहां सुरक्षा अभियानों में खामोशी रही है, आखिरी बड़ा मामला अगस्त, 2018 में दंडकारण्य विशेष जोनल कमेटी के सदस्य पहाड़ सिंह के आत्मसमर्पण का है.

इस बीच, समय के साथ विद्रोही भी बदल रहे हैं, खासकर 'धन इकट्ठा करने' के मामले में. पहले, उन्होंने सड़कों और पुलों जैसे बुनियादी ढांचे के काम करने वाले ठेकेदारों को निशाना बनाया, लेकिन अब उन्होंने छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में तेंदूपत्ता के व्यापार पर ध्यान केंद्रित किया है. पुलिस सूत्रों का कहना है कि माओइस्ट कम्युनिस्ट सेंटर बनाने का एक कारण वैकल्पिक वित्तीय स्रोतों की तलाश करना भी था, क्योंकि तीन राज्यों के तिमुहाने क्षेत्र में प्रमुख बुनियादी ढांचे का काम चल रहा था. छत्तीसगढ़ में, पिछले कुछ वर्षों में बुनियादी ढांचे के कामों पर खर्च घटा है, जिससे उनका ध्यान तेंदूपत्ता के व्यापार पर केंद्रित हुआ है.

हाल के उलटफेरों के बावजूद, चार प्रभावित राज्यों के एक बड़े हिस्से में माओवादियों का बोलबाला है. उनकी विचारधारा को भी अपनाने वाले होंगे, क्योंकि असंतोष और उपेक्षा की गहरी भावना के चलते जंगल अब भी उनके लिए उर्वर क्षेत्र बना हुआ है. सुरक्षाबलों की सफलताओं को क्षेत्र विशेष में विकास की रूपरेखा से समर्थित करना होगा, अन्यथा राज्य जल्द ही मामले को फिर से हाथ से निकलता देखेगा.

—साथ में **राहुल नरोन्हा** और **रोमिता दत्ता**

किशनदा से बरामद 2 टीबी डेटा में माओवादियों की सूक्ष्म जानकारियां हैं. एक पुलिस अफसर बताते हैं, ''यह बिग बी की फिल्म के *डॉन* की डायरी की तरह है''

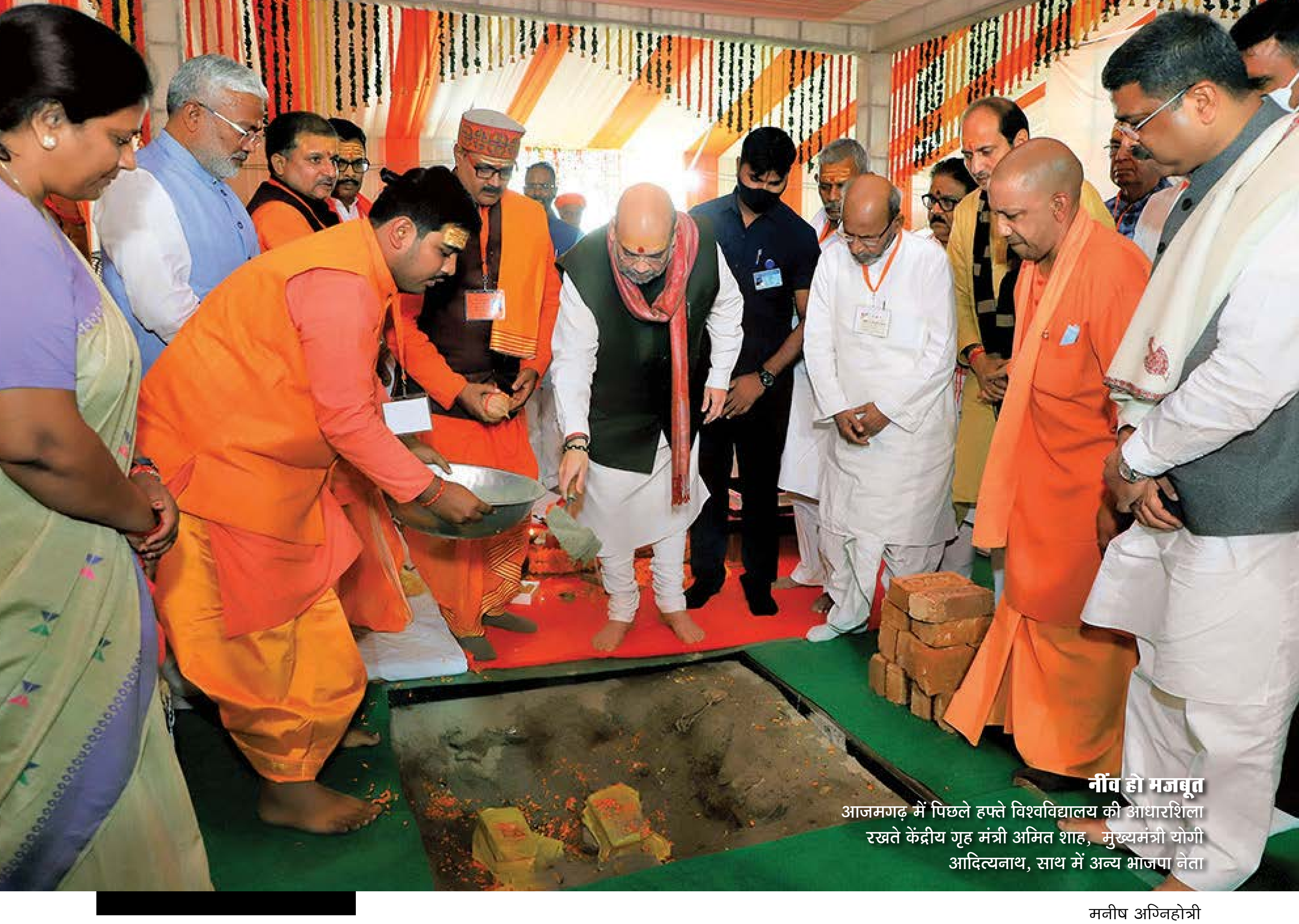

नींव हो मजबूत

आजमगढ़ में पिछले हफ्ते विश्वविद्यालय की आधारशिला रखते केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, साथ में अन्य भाजपा नेता

मनीष अग्निहोत्री

खास रपट | उत्तर प्रदेश

घरों में होने लगी घुसपैठ

अगले विधानसभा चुनावों के लिए पाले अब साफ-साफ खिंचने लगे. भाजपा ने सपा के मजबूत इलाकों में तो सपा ने भाजपाई गढ़ों में घुसपैठ के दांव चलने शुरू किए

आशीष मिश्र

पूर्वी उत्तर प्रदेश का राजनैतिक तापमान 13 नवंबर को आम दिनों की तुलना में कहीं ज्यादा था. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समाजवादी पार्टी (सपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के संसदीय क्षेत्र आजमगढ़ में बनने वाले राज्य विश्वविद्यालय का शिलान्यास करने के लिए उपस्थित थे. आजमगढ़ के यशपालपुर-आजमबांध गांव में 108 करोड़ रु. की लागत से 49.42 एकड़ में बनने वाले विश्वविद्यालय के शिलान्यास कार्यक्रम के दौरान जनसभा को संबोधित करते हुए शाह ने कहा, ''मैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से अपील करूंगा कि नए बनने वाले विश्वविद्यालय का नाम विदेशी आक्रांताओं से मुक्ति दिलाने वाले महाराजा सुहेलदेव के नाम पर रखा जाए. अब आजमगढ़ में भी परिवर्तन की शुरुआत होगी और सभी विधानसभा सीटों पर कमल खिलेगा.'' शाह के प्रस्ताव पर सहमति जताते हुए मुख्यमंत्री योगी ने फौरन मंच से विश्वविद्यालय का नाम ''सुहेलदेव राज्य विश्वविद्यालय'' करने का ऐलान कर दिया.

सपा के गढ़ आजमगढ़ में सुहेलदेव के नाम पर विश्वविद्यालय की स्थापना सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की रणनीति का हिस्सा है. 2017 का विधानसभा चुनाव भाजपा के साथ मिलकर लड़ने वाले, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (सुभासपा) के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर राजा सुहेलदेव को अपना आदर्श मानते हैं. भाजपा से प्लग निकालकर सुभासपा ने अबकी सपा से तार जोड़े हैं.

आमने-सामने

सपा के गढ़ में योगी

मुरादाबाद

6 2 4

मुरादाबाद लोकसभा सीट—सपा

4.5 साल में योगी का 11 बार मुरादाबाद दौरा. पिछले पखवाड़े प्रधानमंत्री आवास योजना के 1008 घरों की चाबी बांटी

रामपुर

5 2 3

रामपुर लोकसभा सीट—सपा

आजम खान के गृह जिले में चार बार आए. 63 करोड़ रु. की परियोजनाएं लोकार्पित

बदायूं

6 5 1

बदायूं लोकसभा सीट—भाजपा

अखिलेश यादव के चचेरे भाई धर्मेंद्र बदायूं से दो बार सांसद रहे हैं. योगी ने 9 नवंबर को 1,117 करोड़ रु. की 50 योजनाएं लोकार्पित कीं

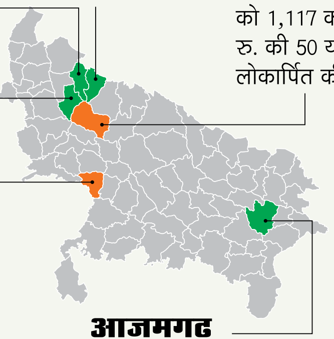

संभल

3 1 2

संभल लोकसभा सीट—सपा

सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव के क्षेत्र रहे संभल में योगी ने 275 करोड़ की 62 परियोजनाएं डलवाईं

इटावा

3 2 1

इटावा लोकसभा सीट—भाजपा

मुलायम सिंह का गृह जिला. 2021 में योगी दो बार इटावा का दौरा कर चुके. हाल ही 454 करोड़ रु. की योजनाओं का लोकार्पण/शिलान्यास

आजमगढ़

10 1 5 4

आजमगढ़ लोकसभा सीट—सपा

आजमगढ़ सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश का संसदीय क्षेत्र. छह महीने में योगी के दो दौरे. 13 नवंबर को सुहेलदेव के नाम पर विश्वविद्यालय का शिलान्यास

भाजपा के गढ़ में अखिलेश

मथुरा

5 4 1

मथुरा लोकसभा सीट—भाजपा

19 मार्च को अखिलेश ने राष्ट्रीय लोकदल की किसान महापंचायत में हिस्सा लिया. सपा ने नंदगांव में दलित संवाद रखा था

अयोध्या

5 5

फैजाबाद लोकसभा सीट—भाजपा

सपा और जनवादी पार्टी (सोशलिस्ट) ने अयोध्या से जनक्रांति यात्रा निकाली. जयशंकर पांडेय सपा के प्रदेश उपाध्यक्ष बने

गोरखपुर

9 8 1

गोरखपुर लोकसभा सीट—भाजपा

मुख्यमंत्री के गृह जिले से अखिलेश यादव ने 13 नवंबर को समाजवादी पार्टी की विजय यात्रा की शुरुआत की

वाराणसी

8 6 1 1

वाराणसी लोकसभा सीट—भाजपा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र में अखिलेश ने 25 फरवरी को संकटमोचन मंदिर में पूजा की. 28 अक्तूबर को सपा का जनसंवाद

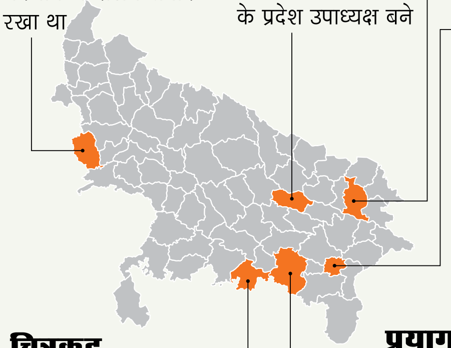

चित्रकूट

2 2

बांदा-चित्रकूट लोकसभा सीट—भाजपा

8 जनवरी को अखिलेश का चित्रकूट दौरा. 6 अक्तूबर को सपा ने पटेल यात्रा निकाली

प्रयागराज

12 8 1 2 1

इलाहाबाद लोकसभा सीट—भाजपा

अखिलेश की 22 फरवरी को प्रयागराज में निषाद समाज के लोगों से भेंट. अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरि की मृत्यु पर भी प्रयागराज आए

● कुल सीटें ● भाजपा ● सपा ● बसपा ● सुभासपा ● अपना दल (एस)

27 अक्तूबर को सपा और सुभासपा की एक बड़ी रैली मऊ में हो चुकी है. अखिलेश के संसदीय क्षेत्र आजमगढ़ में सुहेलदेव के नाम पर विश्वविद्यालय की स्थापना का ऐलान कर भाजपा ने एक तीर से दो निशाने साधने की कोशिश की है.

शाह और योगी 13 नवंबर को जिस समय आजमगढ़ में विश्वविद्यालय का शिलान्यास कर रहे थे उसी समय वहां से 100 किलोमीटर दूर गोरखपुर में अखिलेश सपा की ''विजय यात्रा'' का श्रीगणेश कर रहे थे. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गृह जिले में यात्रा की शुरुआत से पहले शंखनाद और मंत्रोच्चार से अखिलेश का स्वागत किया गया. गोरखपुर के कुसुंभी बाजार में आयोजित जनसभा में अखिलेश ने मुख्यमंत्री योगी पर तंज कसा. उन्होंने कहा ''योगीजी ने युवाओं को लैपटॉप इसलिए नहीं दिया क्योंकि उन्हें खुद लैपटॉप चलाना नहीं आता. यूपी को योगी सरकार नहीं, योग्य सरकार की जरूरत है. वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव में बाबा जी (योगी) के इलाके में भी बदलाव दिखाई पड़ेगा.''

योगी और अखिलेश ने एक दूसरे के गढ़ में रैलियां करके 2022 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले यह साफ करने की कोशिश की है कि सियासी मैदान पर आमने-सामने ताल ठोंकने वाले आखिर कौन हैं? आजमगढ़ के प्रतिष्ठित शिबली नेशनल कॉलेज में राजनीति शास्त्र के पूर्व विभागाध्यक्ष और पूर्व प्राचार्य ग्यास असद खान कहते हैं, ''यह स्पष्ट हो गया है कि 2022 के विधानसभा चुनाव में योगी आदित्यनाथ ही भाजपा का चेहरा होंगे. यही वजह है कि अखिलेश यादव सीधे उन्हीं पर हमला करके प्रदेश की भाजपा सरकार के खिलाफ जनमत तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं. गोरखपुर से पूर्वांचल में सपा की विजय यात्रा की शुरुआत इसी रणनीति का हिस्सा है. 2022 के चुनाव में भाजपा कुछ ऐसी सीटें हारेगी जिन पर 2017 में जीती थी. इन्हीं हारने वाली सीटों को बैलेंस करने के लिए योगी ने सपा के गढ़ में नई सीटें जीतने की योजना तैयार की है. सपा के गढ़ में योगी की सक्रियता से यही निष्कर्ष निकल रहा है.''

मार्च, 2017 में मुख्यमंत्री बनने के साल भर बाद ही योगी आदित्यनाथ ने सपा के गढ़ में भाजपा की पकड़ मजबूत करने के प्रयास शुरू कर दिए थे. इसी रणनीति के तहत 1 जून, 2018 में योगी ने पहली बार सपा के संरक्षक मुलायम सिंह यादव के गृह जिले का दौरा किया. इस दौरान मुख्यमंत्री ने 665 करोड़ रुपए की विकास योजनाओं का शिलान्यास किया. इसके बाद योगी चार बार इटावा का

मनीष अग्निहोत्री

गोरखपुर में
विजय यात्रा निकालते
अखिलेश यादव

दौरा कर चुके हैं. योगी अपने हर दौरे में न केवल विकास योजनाओं की शुरुआत करते हैं बल्कि सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश और परिवारवाद की आलोचना भी करते हैं. योगी ने 6 नवंबर को इटावा पहुंचकर यूपी में नवनिर्मित छठी सेंट्रल जेल का लोकार्पण किया. इस मौके पर आयोजित जनसभा में योगी ने कहा, ''यूपी में पहले एक परिवार का ही विकास हो रहा था, अब प्रदेश की 25 करोड़ जनता को विकास योजनाओं का लाभ मिल रहा है.'' सपा के गढ़ में योगी की सक्रियता को अखिलेश के चचेरे भाई और बदायूं से पूर्व सांसद धर्मेंद्र यादव बेनतीजा रहने वाली कवायद बता रहे हैं. वे कहते हैं, ''योगी आदित्यनाथ जनता का समर्थन खो चुके हैं, इसलिए सपा के गढ़ में रैलियां करके अपनी खीज मिटा रहे हैं. 2022 के विधानसभा चुनाव में इन इलाकों में भाजपा एक भी सीट नहीं जीत पाएगी.''

वर्ष 2022 के चुनाव से पहले मुख्यमंत्री योगी ने हारी हुई विधानसभा सीटों पर ध्यान केंद्रित किया है. 2017 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने 384 सीटों पर चुनाव लड़कर 312 सीटें जीती थीं. बीते साढ़े चार साल के दौरान हुए विधानसभा उपचुनाव में वे चार सीटें हार चुकी है. राजभर से गठबंधन टूटने के बाद भाजपा ने 2017 के विधानसभा चुनाव में सुभासपा को दी गई आठ सीटों को भी हारी हुई सीटों की संख्या में शामिल किया है. इस तरह योगी ने कुल 84 विधानसभा सीटों पर फोकस किया है. इसी रणनीति के तहत मुख्यमंत्री योगी ने बदायूं जिले में 1,358 करोड़ रु. की लागत से 350 विकास योजनाओं का लोकार्पण सहसवान विधानसभा क्षेत्र में किया. 2017 में भाजपा ने इस जिले की पांच में से चार विधानसभा सीटों पर जीत हासिल की थी लेकिन सहसवान सीट सपा के हाथ लगी थी. सहसवान इलाके में आयोजित जनसभा में योगी ने मंच से कहा, ''बदायूं में सहसवान सपा का आखिरी किला बचा है, 2022 के विधानसभा चुनाव में इसे भी ढहा देना.'' जवाब में मौजूद भीड़ ने हुंकार भरते हुए योगी की अपील का समर्थन किया.

पश्चिमी यूपी का मुरादाबाद मंडल मुख्यमंत्री योगी के लिए सिरदर्द बना हुआ है. मुरादाबाद मंडल में अमरोहा, बिजनौर, मुरादाबाद, संभल और रामपुर जिले आते हैं. 2019 के लोकसभा चुनाव में मुरादाबाद मंडल की सभी पांच लोकसभा सीटों पर भाजपा को सपा-बसपा गठबंधन से हार का सामना करना पड़ा था. अमरोहा और बिजनौर सीट बसपा ने जीती थी जबकि सपा ने संभल, रामपुर और मुरादाबाद सीट पर जीत हासिल की थी. 2017 के विधानसभा चुनाव में मुरादाबाद मंडल की सीटों पर भाजपा को सपा से सीधी चुनौती मिली थी. यहां की 27 सीटों में से भाजपा 14 पर जीती थी जबकि 13 सीटों पर सपा के उम्मीदवार विजयी रहे थे. 2022 के विधानसभा चुनाव में मुरादाबाद मंडल में सपा के गढ़ को भेदने के लिए योगी ने पूरी ताकत लगा दी है. मुख्यमंत्री का कार्यभार संभालने के दो महीने बाद 21 मई, 2017 को योगी ने मुरादाबाद जिले का पहला दौरा किया था. उसके बाद से अब तक योगी 11 बार मुरादाबाद आ चुके हैं जो पश्चिमी यूपी के किसी जिले में उनका सर्वाधिक दौरा है. इनमें आठ दौरे 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद किए गए हैं.

सपा के गढ़ में योगी की सक्रियता के प्रत्युत्तर में सपा ने भी भाजपा के गढ़ में ध्यान केंद्रित किया है. अखिलेश ने 8 जनवरी को चित्रकूट का दौरा कर पहली बार यहां पर कामदगिरि पर्वत की परिक्रमा भी की थी. इसके बाद अगले दो महीनों के दौरान अखिलेश ने वाराणसी, प्रयागराज, मथुरा जैसे भाजपा के गढ़ माने जाने वाले जिलों का दौरा कर सपा की रणनीति को अमलीजामा पहनाने की कोशिश शुरू कर दी थी. कोरोना की दूसरी लहर के दौरान अखिलेश ने दौरा स्थगित रखा. उसके बाद उन्होंने भाजपा के गढ़ में जनाधार मजबूत करने के लिए सपा के ''फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन'' को जिम्मेदारी सौंपी है.

बीते एक महीने के दौरान गोरखपुर, वाराणसी, प्रयागराज, समेत भाजपा की मजबूत पकड़ वाले सभी जिलों में सपा पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ, महिला सभा, व्यापार प्रकोष्ठ की बैठकें हो चुकी हैं. भाजपा के गढ़ वाले इलाकों में वरिष्ठ नेताओं को पार्टी में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी देकर अखिलेश ने भाजपा के ''हिंदुत्व एजेंडे'' को निष्प्रभावी करने की रणनीति बनाई है. अयोध्या के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक जयशंकर पांडेय को सपा का उपाध्यक्ष बनाया गया है. पांडेय अयोध्या, आंबेडकर नगर समेत आसपास के जिलों में लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं. पांडेय दावा करते हैं कि ''2017 के विधानसभा चुनाव में जिन जिलों की सभी सीटें भाजपा ने जीती थीं वहां पर विकास का कोई भी कार्य नहीं हुआ है. यह बात जनता को अच्छी तरह से समझ में आ चुकी है. इन जिलों में आयोजित हो रहे सपा के कार्यक्रमों में उमड़ने वाली भीड़ यह इशारा भी कर रही है.''

बहरहाल, इतना तय है कि एक-दूसरे के गढ़ में सेंध लगाने की होड़ में जो पार्टी आगे निकलेगी, वही 2022 के विधानसभा चुनाव में भी अगुआ रहेगी. ■

इंडिया टुडे

देश की भाषा में देश की धड़कन

INDIA TODAY GROUP

विशेषांक
इंडिया टुडे
ऊंचे और असरदार
रसूखदारों की सूची 2021
इंडिया टुडे
इंडिया टुडे कॉन्क्लेव 2021
बेहतरी की उम्मीद
महामारी के बाद उपजी आशंका और आशा के बारे में राजनीति, कारोबार, विज्ञान और खेलकूद की प्रमुख हस्तियों की राय

सबसे भरोसेमंद स्रोतों से, सबसे सटीक जानकारी

सब्सक्राइब करें और पाएं 21% तक की छूट

हां! मैं इंडिया टुडे को सब्सक्राइब करना चाहता/चाहती हूँ

अपनी पसंद के सब्सक्रिप्शन को टिक करें और फॉर्म को इस पते पर भेज दें– **वी केअर, लिविंग मीडिया इंडिया लि. सी-9, सेक्टर-10, नोएडा 201302 (भारत)**

टिक करें	अवधि	कुल अंक	कवर प्राइस (₹)	ऑफर प्राइस (₹)	डिस्काउंट
☐	2 वर्ष	104	~~5200~~	4099	21%
☐	1 वर्ष	52	~~2600~~	2199	15%

कृपया फॉर्म को ब्लॉक लेटर में भरें

मैं चेक/डीडी जमा कर रहा/रही हूँ जिसकी संख्या.......................है और इसे दिनांक................ को लिविंग मीडिया इंडिया लिमिटेड के पक्ष में .... (बैंक का नाम).......................रुपये की धनराशि (दिल्ली से बाहर के चेक के लिए ₹ 50 रुपये अतिरिक्त जोड़ें, समान मूल्य के चेक मान्य नहीं होंगे) के लिए बनवाया गया है.

नाम... पता...

.... शहर...................... राज्य...................... पिन......................

मोबाइल.. ईमेल..

सब्सक्राइब करने के लिए यहां स्कैन करें.

ऑफर के विषय में विशेष जानकारी के लिए निम्न माध्यमों से संपर्क भी कर सकते हैं

हमारे टॉल फ्री नंबर पर कॉल करें
18001800100 (0120) 2479900

ईमेल भेजें
wecare@intoday.com

लॉग ऑन करें
subscriptions.intoday.in/indiatoday-hindi

लिविंग मीडिया इंडिया लिमिटेड इस ऑफर या इसके अंश को कभी भी समाप्त करने या आगे बढ़ाने का अधिकार सुरक्षित रखता है. अन्य नियम व शर्तों की जानकारी के लिए कृपया देखें-www.indiatoday.in

मुख्य अतिथि : श्री मनोहर लाल, मुख्य
विशिष्ट अतिथि : श्री दुष्यंत चौटाला, उप मुख्य
परिवार पहचान-पत्र
परिवार ID: 8HWV7622
परिवार का मुखिया JASWANT
पिता / पति Raghubir
जिला PANCHKULA
शहर PANCHKULA MC
लिंग Male
उम्र 39 साल
पता 180 Madanpur 180 madanpur
नागरिक संसाधन सूचना विभाग

सहज शासन
एक लाभार्थी को परिवार पहचान पत्र सौंपते डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला और सीएम मनोहरलाल खट्टर (4 अगस्त, 2020)

[redacted]

राष्ट्र | **हरियाणा**

परिवारों को पहचान पत्र क्यों दे रही सरकार

हरियाणा की खट्टर सरकार की परिवार पहचान पत्र योजना का उद्देश्य सामाजिक कल्याण के लाभों की डिलिवरी में सुधार करने के लिए प्रमाणित नागरिकों का डेटा तैयार करना है

अनिलेश एस. महाजन

इस साल जनवरी में हरियाणा सरकार के 'परिवार पहचान पत्र (पीपीपी)' के लिए पंजीकरण कराते समय सोनीपत के नागरिक नवीन कुमार सरकारी रिकॉर्ड में खुद को मृतकों की सूची में देखकर स्तब्ध रह गए. पता चला कि उनके पिता टेक राम की जगह उन्हीं के नाम का मृत्यु प्रमाणपत्र जारी कर दिया गया था. टेक राम का देहांत 25 मई, 2018 को हो गया था. सरकारी आंकड़ों में नाम की गड़बड़ी और गलत पता समेत इस तरह की खामियों के मद्देनजर मुख्यमंत्री मनोहरलाल खट्टर को विश्वास है कि उनकी यूनिक फैमिली आइडी, पीपीपी योजना गेम चेंजर साबित होगी.

पीपीपी का उद्देश्य राज्य के सभी परिवारों का प्रमाणित डेटा तैयार करना है ताकि पहचान संबंधी गलतियों की वजह से नागरिकों को सामाजिक कल्याण के लाभों से वंचित न किया जाए. हरियाणा 1 नवंबर को यूनीक फैमिली आइडी योजना लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया. इससे जन्म, मृत्यु और संपत्ति का पंजीकरण, छात्रवृत्ति समेत 456 सेवाएं और विभिन्न कल्याणकारी कार्यक्रम जुड़े होंगे. राज्य का 2021-22 का कुल खर्च 1.55 लाख करोड़ रु. तय किया गया है और खट्टर को उम्मीद है कि सामाजिक क्षेत्र का खर्च इस पीपीपी के जरिए ज्यादा से ज्यादा लक्षित लाभार्थियों तक पहुंचेगा.

देश का नं. 1
हिंदी न्यूज़ ऐप

जुड़े रहिए हर खबर से,
कहीं भी, कभी भी

अभी डाउनलोड करें

aajtak.in/app

उपलब्ध है

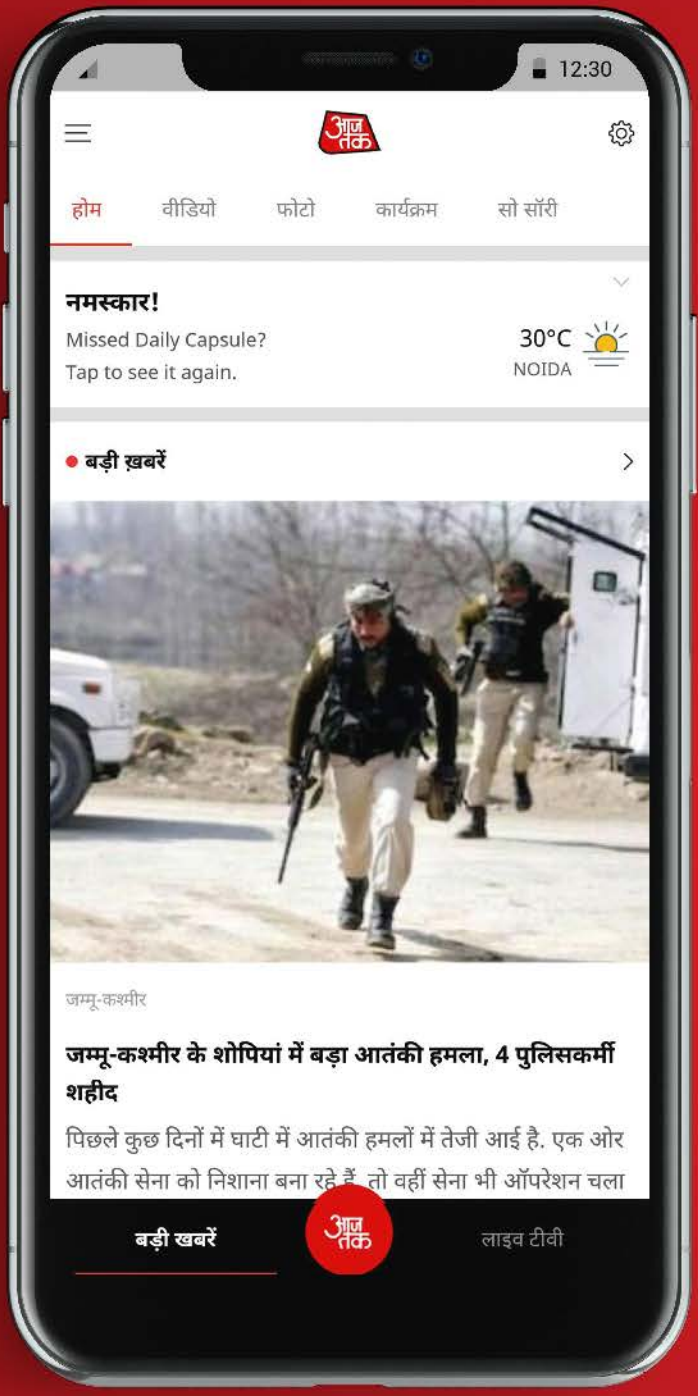
12:30
होम
वीडियो
फोटो
कार्यक्रम
सो सॉरी
30°C
NOIDA
बड़ी ख़बरें
बड़ी खबरें
लाइव टीवी

नमस्कार!
Missed Daily Capsule?
Tap to see it again.

जम्मू-कश्मीर

जम्मू-कश्मीर के शोपियां में बड़ा आतंकी हमला, 4 पुलिसकर्मी शहीद

पिछले कुछ दिनों में घाटी में आतंकी हमलों में तेजी आई है. एक ओर आतंकी सेना को निशाना बना रहे हैं, तो वहीं सेना भी ऑपरेशन चला

बातचीत »
मनोहरलाल खट्टर

'हम परिवारों की प्राइवेसी सुनिश्चित करेंगे'

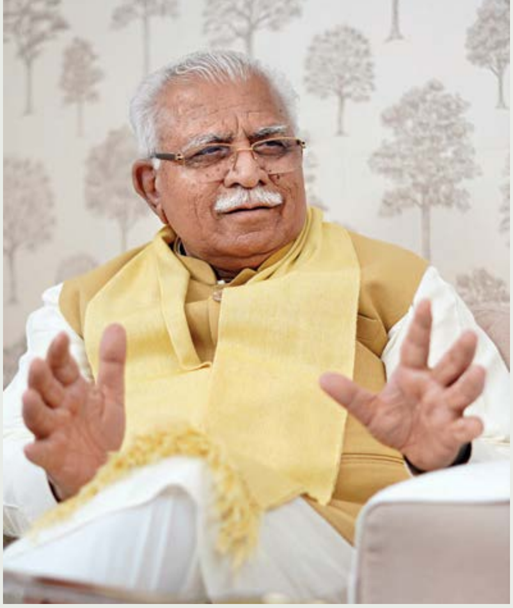
संदीप सहदेव

हर परिवार को एक पहचानपत्र देने की कोशिश का उद्देश्य नीति निर्माण और शासन की डिलिवरी में गेम-चेंजर बनना है. मुख्यमंत्री ***मनोहरलाल खट्टर*** *ने सीनियर एडिटर* **अनिलेश महाजन** *से विशेष बातचीत में बताया कि हरियाणा किस तरह इस पहल को सफलतापूर्वक लागू कर रहा है जबकि कर्नाटक और तमिलनाडु जैसे राज्यों में यह अभी तक शुरू नहीं हो पाया. मुख्य अंशः*

● नीति निर्माण में परिवार पहचान पत्र किस तरह गेम-चेंजर होगा?
भारतीय नागरिक की पहचान आधार कार्ड से होती है, एक यूनिक आइडी, जिससे लोगों को सीधे डिलिवर करने में मदद मिलती है. फिर भी हमारा समाज व्यक्ति केंद्रित नहीं है, यह परिवार केंद्रित है. लिहाजा, एक परिवार पहचान पत्र जरूरी है.

● क्या यह राज्य के कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों तक सीमित है या यह सबके लिए है?
यह सबके लिए है. हरियाणा में 69 लाख परिवार हैं, जिनके ब्यौरे विभिन्न विभागों के पास हैं, भले ही वह पीडीएस लाभार्थी के रूप में हों, संपत्ति के पंजीकरण या कुछ दूसरे लाभ के लिए हों. काम डेटा में सहयोग और सफलता लाने का है. हमने इसे संस्थागत बनाने के लिए एक अलग विभाग, सिटीजन रिसोर्स इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंट (सीआरआइडी) बना दिया.

● आप डेटा कैसे जुटाते हैं?
शुरू में परिवार का प्रमुख परिवार के आकार, नाम, उम्र, संपत्ति और आय जैसी बुनियादी जानकारी खुद देता है. फिर उसे पांच सदस्यीय टीम प्रमाणित करती है. इस तरह जुटाया गया डेटा अटल सेवा केंद्र पर फीड किया जाता है.

● क्या आपने इस फैमिली आइडी के साथ सरकारी योजनाओं को जोड़ना शुरू कर दिया है?
हां, हमने 456 योजनाओं को पीपीपी के साथ जोड़ दिया है. मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना, पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना, पीएम दुर्घटना सुरक्षा योजना, पीएम किसान सम्मान निधि, पीएम लघु व्यापार सम्मान निधि और पीएम श्रमजीवी सम्मान निधि, पीएम फसल बीमा योजना, सब इस आइडी से जोड़ दी गई हैं.

● यह आइडी लोगों के जीवन में किस तरह बदलाव लाएगा?
यह डेटाबेस हमें—आय के मामले में—राज्य के एक लाख सबसे ज्यादा गरीब लोगों की पहचान करने और हमारे संसाधनों को उन्हें ऊपर उठाने में मदद कर रहा है.

● क्या केंद्र प्रायोजित योजनाओं के लिए परिवार का आइडी सार्थक है?
नहीं. यह केवल राज्य की योजनाओं या उन योजनाओं के लिए है, जिनमें राज्य नागरिकों की ओर से योगदान करता है. हमने ऐसी 100 से ज्यादा योजनाओं की पहचान की है, चाहे वह विवाह के लिए लड़कियों की सहायता हो या स्कूली छात्रों को छात्रवृत्ति. यह डेटा बदलता रहेगा.

● आप परिवार की इकाई कैसे तय करते हैं?
परिभाषा के मुताबिक परिवार में पति–पत्नी, बच्चे व उन पर निर्भर माता–पिता होते हैं. फिलहाल, हम सालाना 1.8 लाख रु. से कम आय वाले बीपीएल परिवारों की पहचान कर रहे हैं; धीरे–धीरे हम उसमें परिवारों की प्रति व्यक्ति आय शामिल करेंगे. अगर किसी परिवार में तीन सदस्य हैं तो प्रति व्यक्ति आय 60,000 रु. होगी, पर अगर उसमें छह सदस्य हैं तो यह 30,000 रु. हो जाएगी.

● आप इस तरह के डेटा की निजता की रक्षा कैसे करेंगे?
यह डेटा एक जगह पर नहीं होगा. हमारे पास बुनियादी जानकारी होगी और बाकी डेटा अलग–अलग होगा. सो, अगर स्वास्थ्य विभाग इस जानकारी का इस्तेमाल करना चाहता है तो उसे सिर्फ स्वास्थ्य संबंधी जानकारी मिलेगी.

स्मार्ट डिलिवरी

इस योजना के लिए डेटा जुटाने का केंद्र चंडीगढ़ में मुख्यालय वाला सिटीजन रिसोर्स इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंट (सीआरआइडी) है. यह नोडल एजेंसी सीधे खट्टर को रिपोर्ट करती है. युवा पेशेवरों को मौके पर किए गए सर्वेक्षणों के जरिए जुटाए गए डेटा को प्रमाणित और उसे विभिन्न विभागों के लिए प्रॉसेस करने में मसरूफ देखा जा सकता है. नागरिकों का सभी प्रमाणित डेटा पीपीपी नंबर के जरिए अधिकारियों को उपलब्ध है. इससे किसी भी तरह की सरकारी सेवा हासिल करने के लिए सहायक दस्तावेज लगाने की जरूरत खत्म हो जाएगी. मिसाल के तौर पर, हरियाणा की नागरिक श्रुति मलिक और उनके पति को अपने बच्चे के जन्म का पंजीकरण कराने के लिए अपने आधार के ब्योरे जमा करने की जरूरत नहीं पड़ी. श्रुति के पीपीपी नंबर से न केवल सारी जानकारी मिल गई बल्कि स्तनपान करा रही माताओं से जुड़ी उन सारी योजनाओं का ब्यौरा मिल गया जिनकी वे हकदार हैं, साथ ही उनका आवासीय पता और बैंक अकाउंट नंबर भी मिल गया, जिसमें सरकार उन्हें मिलने वाले लाभ को हस्तांतरित कर सकती है.

पीपीपी नंबर के दो हिस्से हैं—एक सात–नंबर की फैमिली आइडी, और आठवां अंक परिवार विशेष के सदस्यों की सूचना से जुड़ा है. नागरिकों को दिए जा रहे पीपीपी स्मार्ट कार्ड में राज्य में उनकी संपत्ति का डेटा, आय, किसी तरह की पेंशन के साथ ही छात्रवृत्ति, स्वास्थ्य और उन्हें उपलब्ध दूसरे लाभ की जानकारी है. खट्टर का कहना है, ''हकदार लाभार्थियों की प्रायः कोई आवाज नहीं होती. इसका विचार

शासन को उनके द्वार तक ले जाना है.''

लेकिन इस परियोजना की वजह से कुछ हलकों में लोगों की 'संवेदनशील' जानकारी सरकार के कब्जे में होने को लेकर आशंका पैदा हो गई है. अक्तूबर में पंजाब और हरियाणा हाइकोर्ट में दाखिल याचिका में इस योजना पर रोक लगाने की मांग की गई. याचिका में दलील दी गई कि परिवारों की वित्तीय जानकारी के दुरुपयोग का जोखिम है. लेकिन खट्टर का कहना है कि परिवार पहचानपत्र में शामिल जानकारी पहले से ही लोगों की जानकारी में है. इसके अलावा, आधार से जुड़ी निजता की बहस के मद्देनजर हरियाणा सरकार का कहना है कि डेटा जुटाने और उसके प्रॉसेसिंग के लिए किसी निजी एजेंसी का प्रयोग नहीं किया गया है. हरियाणा के एक प्रमुख अधिकारी कहते हैं, ''राज्य सरकार की सेवाओं को पाने के लिए डेटा अपनी मर्जी से देना है. अगर वे कोई सेवा नहीं ले रहे हैं तो वे डेटा न देने के लिए स्वतंत्र हैं.''

खट्टर शासन के मामले में परिवार पहचान पत्र की अहमियत बताते हैं: ''आधार व्यक्ति विशेष का होता है और इससे डुप्लीकेसी तथा फंड की लीक को रोकने का उद्देश्य सधा है, और नागरिकों को सीधे लाभ पहुंचाया गया है. लेकिन हमारा समाज परिवार उन्मुखी है. हम पारिवारिक ढांचे पर आधारित नीतियां बनाते हैं. इसमें (आधार में) परिवार की जरूरतों को पूरी करने वाले डेटा की पहचान नहीं की गई है.''

खाका

अश्विनी वैष्णव के नेतृत्व वाला इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आइटी मंत्रालय भी यूनिवर्सल फैमिली रजिस्ट्री (यूएफआर) तैयार करने के लिए काम कर रहा है. इसका उद्देश्य केंद्र और राज्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन के लिए यूनीक फैमिली आइडी तैयार करना है. यूनीक फैमिली आइडी बनाने का काम 2017 में हरियाणा के साथ ही तमिलनाडु और कर्नाटक में शुरू किया गया था. छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश भी इस पर विचार कर रहे हैं.

पूर्ववर्ती यूपीए सरकार की 2011 में स्वीकृत सामाजिक आर्थिक और जाति जनगणना (एसईसीसी) के निष्कर्षों को 2015 में प्रकाशित किया गया. इन्हीं निष्कर्षों के आधार पर केंद्र और राज्य सामाजिक क्षेत्र के विभिन्न लाभों को वितरित करते हैं. खट्टर का कहना है, ''एक लाख से ज्यादा लोग या तो सरकारी नौकरी पा गए हैं या आयकर दाता बन गए हैं, पर उन्होंने एसईसीसी के आधार पर लाभ उठाना जारी रखा है. इस नई आइडी में उन्हें बाहर कर दिया जाएगा और सबसे हकदार लोगों को लाभ दिया जाएगा.''

पीपीपी काम कैसे करता है?

➘ पहला चरण: सिटीजन रिसोर्स इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंट (सीआरआइडी) परिवार के सदस्यों के प्रमुख डेटा जुटाता है–अन्य ब्यौरों के अलावा, नाम, उम्र, संबंध, परिवार की आय, पेशा और शिक्षा प्रोफाइल.

➘ दूसरा चरण: डेटा प्रमाणित करने के बाद हर परिवार को एक पीपीपी नंबर दे दिया जाता है. परिवार के हर सदस्य के प्रमाणित डेटा–जैसे छात्रवृत्ति, पेंशन, सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों के लाभ, सरकारी एजेंसियों से अदायगी–को जोड़ा जाता है.

➘ तीसरा चरण: राज्य के हर नागरिक को मिले पीपीपी नंबर से उसके खातों को जोड़ा जाता है.

➘ चौथा चरण: नागरिक उन सरकारी लाभों को हासिल करने के लिए पीपीपी नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिनके वे हकदार हैं.

हरियाणा के करीब 69 लाख परिवारों में से 64 लाख को पीपीपी के तहत सात-अंकों वाला आइडी जारी कर दिया गया है. हरियाणा के एक अधिकारी का कहना है, ''पीपीपी में व्यक्तियों की यूनिक आइडी को स्थापित करने के लिए आधार आधारित प्रमाणन का प्रयोग किया जाता है. आंकड़े को अपडेट करते समय कुछ क्षेत्रों के लिए ई-केवाइसी किया जाता है. प्रमाणन के लिए आधार का प्रयोग पीपीपी के डेटा की विश्वसनीयता स्थापित करने के लिए किया जाता है.''

सबसे पहले अटल सुविधा केंद्रों के जरिए सीआरआइडी डेटा जुटाता है. यह डेटा परिवार खुद मुहैया कराते हैं और पांच सदस्यों वाली 20 हजार स्थानीय समितियां इसे प्रमाणित करती हैं. प्रत्येक टीम 300 परिवारों को प्रमाणित करती है. परिवार के कम से कम तीन सदस्यों की आय के आंकड़े को स्वीकार किया जाता है. हरियाणा में कुल 1.8 लाख रु. वार्षिक आय वाले परिवार को गरीबी रेखा के नीचे (बीपीएल) माना जाता है, जबकि राष्ट्रीय मानक 1.2 लाख रु. है. खट्टर का कहना है, ''इस आइडी की बदौलत बीपीएल लाभार्थियों को किसी तरह का फॉर्म भरे बगैर सीधे उनके बैंक खाते में लाभ पहुंचाया जाएगा.''

अगला स्तर

इस साल अप्रैल में कोविड की दूसरी लहर के दौरान इस पहचान पत्र प्रणाली का इस्तेमाल प्रभावित बीपीएल परिवारों के चिकित्सा बिलों का खर्च उठाने की राज्य सरकार की योजना के लिए किया गया. हरियाणा के जिन नागरिकों ने निजी अस्पतालों में इलाज कराया उन्हें प्रति मरीज प्रति दिन एक हजार रु. और घर पर इलाज कराने वाले बीपीएल परिवारों को कुल पांच हजार रु. दिया गया. राज्य के वरिष्ठ अधिकारी का कहना है, ''लाभ का वितरण सौ फीसद था और पैसा कहीं लीक नहीं हुआ. अब हम इसे बढ़ाकर राज्य सरकार की सारी योजनाओं को इस आइडी से जोड़ रहे हैं.''

खट्टर सरकार ने मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना को पीपीपी से जोड़ दिया है, जिसमें परिवार विभिन्न सरकारी योजनाओं के लिए प्रीमियम के रूप में प्रति वर्ष 6,000 रु. पाने के हकदार हैं. सरकार ने राज्य के सबसे निर्धन एक लाख ऐसे परिवारों की पहचान कर ली है जिन्हें मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के तहत मदद दी जाएगी. इस योजना का उद्देश्य आय बढ़ाने के लिए कौशल विकास और स्वरोजगार को बढ़ावा देना है. खट्टर का कहना है, ''हमने सात सरकारी विभागों की पहचान करके उन्हें ऐसे परिवारों की वार्षिक आय कम से कम एक लाख रु. करने की रणनीति तैयार करने को कहा है.'' अधिकारियों के मुताबिक, इन परिवारों को साल में 250 दिन—400-500 रु. की—मजदूरी से आय के इन लक्ष्यों को हासिल करने में मदद मिल सकती है.

सीआरआइडी के प्रमुख वी. उमाशंकर का कहना है कि हरियाणा के 28 लाख लोग किसी न किसी रूप में सरकारी सेवाओं का इस्तेमाल करते हैं, उनके डेटा का मानकीकरण करके परिवार आइडी के तहत डालने से सरकार को हकदार लाभार्थियों तक पहुंचने में मदद मिलती है. वे चहकते हुए कहते हैं, ''आखिरकार, हमारे पास डेटा है और ये सब प्रमाणित है.'' ■

बातचीत / **भूपेंद्र यादव**

“दुनिया के मालदार मुल्क पैसे के मामले में दी गई जबान पूरी करने में नाकाम रहे”

ग्लासगो में हाल ही संपन्न जलवायु परिवर्तन सम्मेलन की पर्यावरण कार्यकर्ताओं ने इस बात के लिए खासी आलोचना की कि उसने दुनिया को बचाने के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठाए. लेकिन कुछ बड़ी पहलकदमियों के लिए इसकी तारीफ भी हुई. इस सम्मेलन में भारत की महत्वपूर्ण भूमिका रही. केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव वहां पर भारत के मुख्य वार्ताकार थे. ग्रुप एडिटोरियल डायरेक्टर राज चेंगप्पा के साथ एक खास बातचीत में उन्होंने सम्मेलन में हासिल उपलब्धियों पर विस्तार से चर्चा की और यह भी बताया कि क्या कुछ था जो हाथ आने से रह गया. पेश हैं बातचीत के चुनिंदा अंश:

चंद्रदीप कुमार

प्र. ग्लासगो जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में भारत का नजरिया क्या था? क्या भारत वह सब हासिल कर सका जो वह चाहता था?
हमारा नजरिया था कि हमारा ग्रह एक ही है, न कि कोई ‘ए’ या ‘बी’ ग्रह, और इसका बचाव करना हमारा कर्तव्य है. लेकिन हमारा कर्तव्य भी हमारी परिस्थितियों से बंधा है. यही कारण है कि भारत हमेशा ‘साझा लेकिन एक-दूसरे से अलहदा किस्म की जिम्मेदारियों (सीबीडीआर)’ वाले सिद्धांत का पक्षधर रहा है जो 2015 में पेरिस समझौते में मंजूर किया गया था. हमने कहा कि इस बार के समझौते के पाठ में भी ‘राष्ट्रीय परिस्थितियां और गरीबी उन्मूलन’ को होना चाहिए. हमने ग्लासगो में सभी को साफ कर दिया कि पर्यावरण सिर्फ संवाद का मुद्दा नहीं बना रह सकता, साफ नजरिए के साथ इस पर कार्रवाई होनी चाहिए. हमने अपने ‘राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान’ (एनडीसी) में जो भी लक्ष्य हासिल करने की प्रतिबद्धता जताई है, उन्हें हासिल करने की राह पर हैं. हमने दिखाया है कि हम और भी बहुत कुछ करने को तैयार हैं. ग्लासगो में उद्घाटन सत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन पांच नए लक्ष्यों की घोषणा की जिन्हें हमने अपने लिए ‘पंचामृत’ के रूप में निर्धारित किया है. भारत ने 2030 तक 500 गीगावाट अक्षय ऊर्जा के उत्पादन का लक्ष्य तय किया है. तब तक इसने कुल ऊर्जा जरूरतों का 50 प्रतिशत अक्षय ऊर्जा स्रोतों से पूरा करने की प्रतिबद्धता जताई है. साथ ही भारत ने इस दशक के अंत तक अपने ग्रीनहाउस गैस (जीएचजी) उत्सर्जन को एक अरब टन तक कम करने का आश्वासन दिया है. भारत ने कहा कि वह अर्थव्यवस्था की कार्बन इंटेंसिटी को घटाकर 45 प्रतिशत से कम के स्तर पर लाएगा. यह भी कि भारत 2070 तक नेट-जीरो उत्सर्जन स्तर तक पहुंच जाएगा. प्रधानमंत्री ने ‘जीवन’ के लिए एक नया मुहावरा गढ़ते हुए इसे ‘पर्यावरण-हितैषी जीवन शैली’ के रूप में व्यक्त किया और कहा कि यह ऐसी जरूरत है जिसे अब पूरी दुनिया को अपना लेना चाहिए. भारत ने भविष्य की ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए भी एक बड़ी पहल की है, जिसमें ग्लासगो में शुरू की गई ‘ग्रीन ग्रिड पहल—एक सूर्य, एक विश्व, एक ग्रिड’—शामिल है.

● ग्लासगो शिखर सम्मेलन में सबसे निराश करने वाली बातें क्या थीं?
देखिए, जलवायु परिवर्तन संबंधी जिम्मेदारियों को अगर आप न्यायसंगत बनाना चाहते हैं तो आपको विकासशील देशों को पैसा और टेक्नोलॉजी देनी होगी. इस समय वातावरण में मौजूद अधिकांश कार्बन उत्सर्जन के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार औद्योगीकृत राष्ट्र हैं. पेरिस समझौते के तहत यह ऐतिहासिक जिम्मेदारी स्वीकार करते हुए उन्हें 2020 से विकासशील देशों को जलवायु परिवर्तन से निबटने में मदद के लिए सालाना 100 अरब डॉलर देने थे. अब तक नहीं दिए उन्होंने.

● अमीर देश वादे के मुताबिक रकम

> हमने अपनी ऊर्जा की 50 प्रतिशत जरूरत अक्षय ऊर्जा स्रोतों से पूरी करने की प्रतिबद्धता जताई है, और जब भारत वह लक्ष्य हासिल कर लेगा तो स्वाभाविक तौर पर कोयले जैसे जीवाश्म ईंधन पर उसकी निर्भरता घट जाएगी

दें, क्या भारत यह दबाव बना पाने में कामयाब हुआ?

प्रधानमंत्री ने अपने उद्घाटन भाषण में इस मुद्दे पर विकासशील देशों की चिंताओं को उठाते हुए कहा कि सालाना जरूरत सौ अरब डॉलर की नहीं, एक खरब डॉलर की है. इसने पहली बार प्रेसिडेंसी ऑफ द कमेटी ऑफ पार्टीज (सीओपी) से 'गहरे अफसोस' के साथ टिप्पणी लिखवाने में सफलता पाई कि विकासशील देशों को जलवायु के वास्ते रकम देने का आश्वासन पूरा नहीं किया गया. अध्यक्षीय आसन को स्वीकारना पड़ा कि विकसित देशों को प्रतिबद्धता का सम्मान करना होगा. दूसरे, 'जलवायु वित्त' को परिभाषित करने का विषय निर्णय के लिए स्थायी समिति के पास भेजा गया. तीसरे, सम्मेलन ने 2025 के बाद की अवधि के लक्ष्यों को परिभाषित करने के लिए 'नवीन सामूहिक मात्रात्मक लक्ष्य' पर तदर्थ समिति की नियुक्त की. चौथे, विकसित देश चाहते थे कि उनकी दीर्घकालिक देनदारियां 2027 तक खत्म हो जाएं, लेकिन विकासशील देशों के दबाव में उन्हें इसकी निरंतरता को स्वीकार करना पड़ा. पांचवीं बात, छोटे देशों में क्षमता निर्माण और उन्हें वित्त मुहैया कराने की जरूरत को भी स्वीकारा गया. ग्लोबल एन्वायरनमेंट फैसिलिटी (जीईएफ) को भी एन्हांस्ड ट्रांसपेरेंसी फ्रेमवर्क (ईटीएफ) के तहत लाया गया.

● ऊर्जा के लिए कोयले के इस्तेमाल को 'चरणबद्ध तरीके से बंद करने' की बजाए उसे 'चरणबद्ध तरीके से कम करने' के रूप में स्वीकार किए जाने पर जोर देकर भारत के ग्लासगो संधि को कमजोर करने के विवाद पर आपका क्या कहना है?

पेरिस समझौते का मूल सीबीडीआर सिद्धांत में निहित है. निर्णय लिया गया था कि हर देश अपनी राष्ट्रीय परिस्थितियों के आधार पर अपने लक्ष्य तय करेगा. उसमें भी यह निर्णय लिया गया था कि सभी जीवाश्म ईंधनों का उपयोग उत्तरोत्तर बंद कर दिया जाना चाहिए, लेकिन इसमें किसी एक ऊर्जा स्रोत को लक्ष्य नहीं किया गया था. ग्लासगो में जताई गई प्रतिबद्धता के अनुरूप जब हम अपनी ऊर्जा जरूरतों का 50 प्रतिशत अक्षय स्रोतों से प्राप्त करने का लक्ष्य हासिल कर लेंगे तो स्वाभाविक रूप से जीवाश्म ईंधन स्रोतों पर भारत की निर्भरता कम होगी. अधिकांश विकासशील देशों की यही स्थिति है. हमने तर्क दिया कि कोयले के उपयोग जैसी प्रतिबद्धताओं को राष्ट्रीय परिस्थितियों के आधार पर तय किया जाना चाहिए, सो हमने चरणबद्ध तरीके से कमी लाने की बात की.

● ऐसी आलोचना भी हुई कि भारत को अवरोधक के रूप में देखा जा रहा है जबकि कोयले के सबसे बड़े उपभोक्ता चीन ने बिना किसी आलोचना के अपनी बात मनवाने को हमारा इस्तेमाल कर लिया.

नहीं. अगर आप बैठक स्थगित होने पर प्रस्ताव की भाषा देखेंगे तो पाएंगे कि भारत और चीन दोनों ने 'अध्यक्षीय सहमति के साथ' वाक्यांश का उपयोग किया था. इससे पता चलता है कि आम सहमति बन चुकी थी. उपस्थित सभी लोग इसका हिस्सा थे. चूंकि सीओपी प्रेसिडेंसी के कथन में परिवर्तन किया जाना था, इसलिए यह आम सहमति के आधार पर होना था. सिर्फ भारत और चीन ही नहीं, कई विकासशील देशों ने इस मुद्दे को उठाया.

● पर भारत शब्दावली में बदलाव लाने का प्रस्ताव चीन से करवा सकता था?

रॉयटर

पहले उन्होंने इसे प्रस्तावित किया और फिर हमने. दक्षिण अफ्रीका, ईरान, क्यूबा, नाइजीरिया और कई अन्य विकासशील देशों ने भी इस मुद्दे को उठाया.

● ग्लासगो संधि में 'कोयले के उपयोग में चरणबद्ध कमी' से संबंधित शब्दावली भारत के लिए इतनी महत्वपूर्ण क्यों है?

आप रातो-रात कोयले का इस्तेमाल बंद नहीं कर सकते. यह काम 2070 तक धीरे-धीरे किया जाएगा. आज भी अमेरिका और इंग्लैंड ने कोयला उत्पादन बंद नहीं किया है जबकि वे सबसे विकसित देशों में से हैं. अगर उन्हें अपना नेट-जीरो लक्ष्य 2050 तक प्राप्त करना है, तो उन्हें 2030 तक कोयले का उपयोग बंद करने का लक्ष्य प्राप्त करना चाहिए. लेकिन विकसित देश अभी भी इस लक्ष्य को प्राप्त करने में असमर्थ हैं. भूलिए मत कि हमें गांवों में बिजली पहुंचानी है. हम केवल एक स्रोत पर निर्भर नहीं, बल्कि नवीकरणीय ऊर्जा के लिए और अधिक प्रयास करेंगे. भारत पहले ही कुछ क्षेत्रों में ऐसा कर चुका है. रेलवे में कोयले का उपयोग बहुत पहले समाप्त हो चुका है. रेलवे ने विद्युतीकरण भी लगभग पूरा कर लिया है. हमने 36 करोड़ एलईडी बल्ब बांटने का लक्ष्य हासिल किया. भारत की अपनी उपलब्धियां और लक्ष्य हैं.

● विकासशील देशों को स्वच्छ प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के लिए विकसित देशों की प्रतिबद्धताओं के बारे में क्या कहेंगे?

जलवायु वित्त, अनुकूलन के लिए एक समिति का गठन, दीर्घकालिक वित्त और नवीन सामूहिक मात्रात्मक लक्ष्यों से संबंधित मुद्दों की पहचान की गई है, लेकिन मुझे लगता है कि इन्हें तत्काल स्वीकार किया जाना चाहिए क्योंकि ऐसा होने पर ही सीओपी की विज्ञान और प्रौद्योगिकी उप-समिति अधिक प्रभावी ढंग से काम कर सकेगी.

● ग्लासगो सम्मेलन के प्रमुख मुद्दों में से एक था कार्बन ट्रेडिंग के लिए नियम पुस्तिका को अंतिम रूप देना. क्या यह काम प्रभावी तरीके से किया जा सका?

भारत हमेशा से तर्क देता रहा है कि क्योटो सीओपी के तहत लागू किए गए सर्टिफिकेट ऑफ एमिशन रिडक्शन (सीईएमआर) और स्वच्छ विकास प्रबंधन (सीडीएम) परियोजनाओं के प्रावधान यथावत रहने चाहिए, वरना संगठन की विश्वसनीयता खतरे में पड़ जाएगी. उन प्रावधानों को जारी रखना स्वीकार किया गया, और इससे एक तरह से कई भारतीय कंपनियों को लाभ मिला है. मेरा मानना है कि हमारे प्रधानमंत्री के नेतृत्व में यह एक बड़ी उपलब्धि है.

> “ जलवायु के मुद्दे पर सब कुछ न्यायसंगत हो, इसके लिए सभी की खातिर बराबरी की जमीन तैयार करनी होगी. विकसित देशों को धन और टेक्नोलॉजी देने का वादा निभाना होगा ”

● भारत ने मीथेन का उपयोग चरणबद्ध तरीके से कम करने के समझौते पर हस्ताक्षर क्यों नहीं किया?

मीथेन संबंधी जिम्मेदारी उन लोगों की है जिनकी जीवनशैली में मांस खाना शामिल है. इसके लिए पश्चिमी जीवनशैली अधिक जिम्मेदार है और इसीलिए प्रधानमंत्री ने पर्यावरण-हितैषी जीवनशैली पर जोर दिया. मीथेन के मुद्दे को हमारी प्राथमिकताओं से नहीं जोड़ा जा सकता. एनडीसी के तहत सभी देश कार्बन उत्सर्जन लक्ष्यों को पूरा करने से जुड़े अपने क्षेत्रों का चयन करने के लिए स्वतंत्र हैं. जब हम इस स्वतंत्रता का प्रयोग कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हम दुनिया के साथ सहयोग कर रहे हैं. हम कभी समस्या पैदा नहीं करेंगे; हम हमेशा समाधान का रास्ता चुनेंगे.

● भारत ने वनीकरण समझौते पर हस्ताक्षर क्यों नहीं किया?

हम अपने वन क्षेत्र को 33 प्रतिशत तक बढ़ाने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं और पिछले पांच वर्षों के दौरान हमने पहले से अधिक क्षेत्र का वनीकरण किया है. हम अपने वन क्षेत्रों की जैव विविधता की रक्षा के लिए भी प्रतिबद्ध हैं. और भविष्य में अगर किसी वन भूमि का उपयोग परिवर्तन किया जाता है, तो उसकी भरपाई के लिए अनिवार्य रूप से वनीकरण किया जाएगा.

● ग्लासगो सत्र के बाद अब विभिन्न देशों को क्या करना चाहिए?

एकसमान परिस्थितियां पैदा की जानी चाहिए. विकसित देशों को पैसे और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर सरीखे वादे निभाने चाहिए. यह किसी की मदद करने का नहीं बल्कि जिम्मेदारी और कर्तव्य निर्वाह का मामला है. अगर दुनिया को बचाना है, तो जिन्होंने अतीत में सबसे ज्यादा ग्रीनहाउस गैस वायुमंडल में छोड़ी है, उन्हें अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी. दूसरे, हर देश को जलवायु परिवर्तन से निबटने की दिशा में अपनी क्षमताओं और गतिविधियों का विकास करना चाहिए. भारत दुनिया के लिए इसका आदर्श उदाहरण है. ■

इंडिया टुडे

ऑटो रिपोर्ट

TN/19/TC/035/153

महिंद्रा की एक्सयूवी
700 में कई आलीशान
खूबियां हैं

हवाई सफर का एहसास

नया ट्रेंड
इलेक्ट्रिक वाहनों
की नई खेप

विंटर गाइड
सर्दियों में सड़क पर
उतरें जरा संभलकर

AutoToday की प्रस्तुति

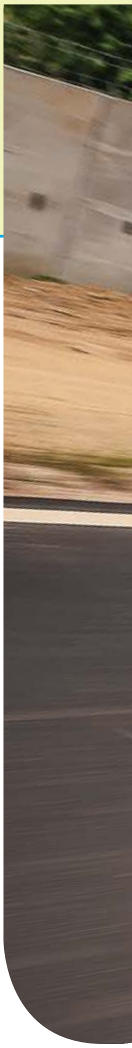

अंतरिक्षयान जैसा अनुभव

महिंद्रा एक्सयूवी 500 की जगह एक्सयूवी 700 लेकर आए हैं जो लग्जरी कारों वाली अपनी खासियतों और उपकरणों के अलावा ब्रांड न्यू इंजन तथा नई चैसिस के साथ बहुत शानदार नजर आती है

योगेंद्र प्रताप

महिंद्रा की नेक्स्ट जेनरेशन 500 प्रतिस्पर्धियों के साथ खेल में इतनी आगे निकली गई कि कंपनी ने और ऊंचा दांव चलते हुए इसे नया नाम एक्सयूवी700 देने का फैसला किया और इस तरह 300 और 700 के बीच एक नई कार की जगह निकाल ली. 700 अब भी 7-सीटर ही है और दो अलग-अलग शृंखलाओं में आएगी, एमएक्स और एड्रीनोक्स सीरीज. एमएक्स एकदम सादी पेशकश होगी और 500 की खाली जगह को भरेगी, जिसमें पुराना डीजल इंजन है और अपनी तरह की कारों की बेहतरीन खूबियां भी इसमें नहीं हैं. लेकिन यह एड्रनोक्स सीरीज ही है, जिसके बारे में हम यहां बात करेंगे. कार में 500 की डिजाइन शैली की बची हुई निशानियां तो हैं पर इसका डिजाइन कहीं ज्यादा सोच-समझकर तैयार किया गया है.

एड्रीनोक्स को एल्यूमिनियम के दो बिल्कुल नए इंजन ताकत दे रहे हैं. एक 2.2 लीटर का डीजल इंजन और दूसरा 2 लीटर का पेट्रोल इंजन. दोनों डायरेक्ट इंजेक्शन वाले टर्बोचार्ज इंजन हैं. जहां डीजल ड्राइव में काफी स्मूद है और तीन अलग-अलग ईसीयू मैप के साथ आता है ताकि तीन ड्राइव मोड—जिप, जैप और जूम—के बीच बदला जा सकता है, वहीं पेट्रोल इंजन कार कहीं ज्यादा हैरतअंगेज है और यह देखते हुए इसे महिंद्रा लेकर आए हैं, यह बहुत आगे का कदम है. दोनों इंजन मैन्यूअल और ऑटोमैटिक गियरबॉक्स से साथ उपलब्ध है और साथ ही ऑल व्हील ड्राइव का विकल्प भी होगा. चैसिस के निर्माण में भी बेहद लचीले स्टील का खुले हाथ से इस्तेमाल किया गया है ताकि कार का धड़ और ज्यादा मजबूत बनाया जा सके और वजन कम करने के साथ सुरक्षा तथा धक्का

रफ्तार ही पहचान

एक्सयूवी 700 आलीशान खूबियों से लैस है और 6-स्पीड ऑटो में भी बढ़िया चलती है

इंजन

2.0-लीटर टर्बो पेट्रोल

2.2-लीटर टर्बो डीजल

पावर

200 बीएचपी @5,000 आरपीएम

185 बीएचपी @3,500 आरपीएम

कीमत

11.99 लाख रु. से 16.49 लाख रु. (एक्स-शोरूम, दिल्ली)

सुरेश नारायण

सहने की पर्याप्त क्षमता लाई जा सके. इसके अलावा फ्रीक्वेंस सेलेक्टिव डैंपर्स के साथ मल्टीपल लिंक रियर सस्पेंशन दिया गया है. साथ ही, स्टैब्लाइज बार भी है. इस तरह बनी है महिंद्रा की बेहद ताकत और रफ्तार से लैस एसयूवी.

हालांकि कुछ अव्वल और महंगी खूबियां और प्रणालियां वैकल्पिक तौर पर मौजूद हैं, फिर भी महिंद्रा ने कार को भारी तादाद में प्रणालियों और खूबियों से लैस किया है. इन खूबियों में ड्राइवर की सहायता करने वाले उन्नत सिस्टम शामिल हैं जो कैमरा और रडार दोनों से मिलने वाले सिग्नलों के जरिए संचालित होते हैं. ये ऐसी खूबियां हैं जो अभी तक केवल लग्जरी ब्रांड की कारों में ही मिलती थीं. इन प्रणालियों में एडैप्टिव क्रूज कंट्रोल भी शामिल है जो स्टार्ट फ्रॉम स्टॉप टेक्नोलॉजी, फ्रंट कोलिजन वार्निंग के साथ इमरजेंसी ब्रेकिंग, लेन असिस्ट, ट्रैफिक साइन रिकग्निशन और साथ ही हाइ बीम असिस्ट से लैस है.

फिर एंड्रीनोक्स तो है ही—भीतर लगे एलेक्सा के साथ कनेक्टेड कार का दिल. इसमें वायरलेस एपल कार प्ले और एंड्रॉयड ऑटो भी है, 60 से ज्यादा इन-बिल्ट ऐप के अलावा, जो कार के उत्पादन के चरण में जाने के वक्त तक आए होंगे. इंटीनियर आलीशान और महंगा है, जैसा टॉप-ऑफ-द-लाइन कारों में होता है. पैनोरैमिक सनरूफ है और सुरक्षा को लेकर सतर्क लोगों के लिए सराउंड व्यू और टर्न इंडिकेटर कैमरे, 7 एयर बैग और ड्राउजीनेस डिटेक्शन भी है. दूसरी कतार में घुटने फैलाने के लिए काफी नी रूम है जो आरामदायक भी है. सीट भी ऐसी हैं कि जांघों के नीचे अच्छा सहारा देती हैं, यहां तक कि औसत से ज्यादा लंबे लोगों को भी.

2.0 लीटर का पेट्रोल इंजन अधिकतम 200 बीएचपी की असरदार शक्ति देता है, सुचारू और बहुत रिस्पांसिव है. यह 6-स्पीड ऑटो के साथ भी अच्छा काम करता है. 300 के साथ, 700 भी महिंद्रा की गाड़ियों में सबसे ज्यादा ताकत और रफ्तार देने वाली कारों में होगी.

कुल मिलाकर गाड़ी दमदार बनाई गई है, हालांकि एर्गोनॉमिक्स या सॉफ्टवेयर की पूर्णता सरीखे कुछ छोटे-मोटे मुद्दे हैं, पर संभवत: इसी महीने कार की बिक्री शुरू होने से पहले इन छोटे-मोटी कमियों को दूर करने के लिए महिंद्रा के पास काफी वक्त है.■

योगेंद्र प्रताप

इलेक्ट्रिक का मैदान-ए-जंग

इलेक्ट्रिक वाहन युद्ध का नया मोर्चा हैं. हालांकि अड़चनें कायम हैं फिर भी सूझबूझ से कीमत तय करके पहला ईवी लॉन्च करने वाली कंपनी यह देखकर दंग रह जाएगी कि भारत नई टेक्नोलॉजी कितनी तेजी से अपनाता है

RENAULT CITY
K-ZE

साल उसी तरह गुजरा जैसी उम्मीद थी. मांग ने आपूर्ति को पीछे छोड़ दिया और इसकी वजह थी सेमीकंडक्टर की लगातार कमी के साथ लॉजिस्टिक्स और सप्लाइ चेन की मुश्किलें. कंपनी जितनी ज्यादा बड़ी थी, उतना ही ज्यादा उस पर असर पड़ा. मसलन, मारुति सुजुकी की प्रतीक्षा सूची में 2,00,000 से ज्यादा कारें हैं और तैयारशुदा केवल एक ही कार मौजूद है शुरुआती स्तर की ऑल्टो. देश की दूसरी सबसे बड़ी वाहन निर्माता कंपनी ह्युडई मोटर के कई मॉडल की प्रतीक्षा अवधि छह महीने से भी ज्यादा है. दूसरी तरफ, प्रीमियम

बिक्री के लिए हाजिर इलेक्ट्रिक स्कूटर

बजाज चेतक

बैटरी पैक: लीथियम-ऑयन
टॉप स्पीड: 70 केएमपीएच
रेंज : 90 किलोमीटर आइडीसी
कीमत: 1.41 लाख रुपए (एक्स शोरूम, पुणे)

टीवीएस आइक्यूब

बैटरी पैक: लीथियम-ऑयन
टॉप स्पीड: 78 केएमपीएच
रेंज : 75 किलोमीटर, एक बार चार्ज करने पर
कीमत: 1.38 लाख रुपए (एक्स शोरूम, दिल्ली)

ओला एस1 प्रो

बैटरी पैक: लीथियम-ऑयन
टॉप स्पीड: 70 केएमपीएच
रेंज : 90 किलोमीटर एआरएआइ
कीमत: 1.29 लाख रुपए (एक्स शोरूम, दिल्ली)

और लग्जरी वाहनों के मैन्युफैक्चरर्स पर भी खासा असर पड़ा और उनके पोर्टफोलियो के कई मॉडलों पर प्रतीक्षा की अवधि महीनों तक फैली है.

आपूर्ति की मुश्किलें अभी और कुछ महीने बनी रहने वाली है, वहीं ईंधन की बढ़ती कीमतों और कई राज्यों की तरफ से प्रोत्साहन लाभों की घोषणा देखते हुए सबकी नजर इलेक्ट्रिक वाहनों और इस मोर्चे पर बड़े मैन्युफैक्चरर्स की योजनाओं की तरफ टिक गई हैं. खासकर तब जब टाटा मोटर्स ने अपने ईवी कारोबार के लिए 1 अरब अमेरिकी डॉलर का धन जुटाने का ऐलान किया है. टाटा मोटर्स असल में ईवी के मामले में देश का अगुआ है, पर उसके वाहन अब भी महंगे हैं. देखने वाली बात होगी कि व्यापक बाजार के लिए देश में पहली इलेक्ट्रिक कार कौन लॉन्च करता है. भारत का पहला लीथियम-ऑयन संयंत्र लगाने का ऐलान करने वाली सुजुकी पहली कंपनी थी, पर वह बाजार में तभी कदम रखेगी जब वह देखेगी कि उसकी इलेक्ट्रिक कार अच्छी-खासी तादाद में बिक सकती है. हालांकि कंपनी वैगन-आर पर आधारित ईवी का परीक्षण कर रही है. ह्युंडई भी पिछले कुछ समय से आइ10 प्लेटफॉर्म पर आधारित ईवी का अध्ययन कर रही है. मगर टाटा मोटर्स के पास पहले ही एक नया ईवी-रेडी प्लेटफॉर्म है, जिससे निकला एक रूप टाटा पंच और अल्ट्रोज को सहारा देता है. महिंद्रा ने इस मामले में बढ़त ली थी, पर वह अपने समूचे पोर्टफोलियो की समीक्षा करने में व्यस्त है और ईवी के मोर्चे पर ढीला पड़ गया है. अलबत्ता एक कंपनी है जिसके पास भारत में इस्तेमाल किए जा रहे एक प्लेटफॉर्म पर ईवी तैयार है और वह है रेनॉ. रेनॉ सिटी के.जी (K.Ze) क्विड पर आधारित है और इसी से निकला एक वाहन, जो ऑटो एक्स्पो 2020 में प्रदर्शित किया गया था, चीन में करीब 6.5 लाख रुपए में बिक्री के लिए पेश किया जा चुका है.

लग सकता है कि देश में इलेक्ट्रिक कारों के लिए बुनियादी ढांचे की कमी है, मगर ईंधन की बढ़ती लागत और ड्राइविंग की भारतीय आदतें इलेक्ट्रिक कारों के लिए मुफीद हैं. व्यापक बाजार में सूझबूझ के साथ जो भी कंपनी पहले इलेक्ट्रिक कार लेकर आएगी, वह निश्चय ही यह देखकर दंग रह जाएगी कि देश इलेक्ट्रिक वाहन कितनी तेजी से अपनाता है. ■

बाजार में इलेक्ट्रिक कारें

ह्युंडई कोना ईवी

बैटरी पैक: 39.2 केडब्ल्यूएच लीथियम-ऑयन
मोटर: 100 केवी पीएमएसएम
रेंज : 452 किलोमीटर एआरएआइ
कीमत: 23.9 लाख रुपए (एक्स शोरूम, दिल्ली)

एमजी जेड एस ईवी

बैटरी पैक: 44.5 केडब्ल्यूएच एचटीबी
मोटर: 142.7 बीएचपी पीएमएसएम
रेंज : 419 किलोमीटर एआरएआइ
कीमत: 23.9 लाख रुपए (एक्स शोरूम, दिल्ली)

टाटा नेक्सन ईवी

बैटरी पैक: 30.2 केडब्ल्यूएच लीथियम-ऑयन
मोटर: 129 बीएचपी पीएमएसएम
रेंज : 312 किलोमीटर एआरएआइ
कीमत: 16.85 लाख रुपए (एक्स शोरूम, दिल्ली)

मर्सिडीज ईक्यूसी

बैटरी पैक: 80 केडब्ल्यूएच लीथियम-ऑयन
मोटर: 300 केडब्ल्यू डुअल मोटर
रेंज : 414 किलोमीटर (डब्ल्यूएलटीपी)
कीमत: 99.3 लाख रुपए (एक्स शोरूम, दिल्ली)

ऑडी ई-ट्रॉन 50

बैटरी पैक: 71 केडब्ल्यूएच लीथियम-ऑयन
मोटर: 230 केडब्ल्यू
रेंज : 379 किलोमीटर डब्ल्यूएलटीपी
कीमत: 99.9 लाख रुपए (एक्स शोरूम, दिल्ली)

बीवाइडी ई-6

बैटरी पैक: 71.7 केडब्ल्यूएच लीथियम-ऑयन
मोटर: 100 केडब्ल्यूएच
रेंज : 415 किलोमीटर डब्ल्यूएलटीसी
कीमत: 29.6 लाख रुपए (एक्स शोरूम, दिल्ली)

एथर 450 एक्स

बैटरी पैक: 39.2 लीथियम-ऑयन
टॉप स्पीड: 80 केएमपीएच
रेंज : 116 किलोमीटर प्रति चार्ज
कीमत: 1.44 लाख रुप (एक्स शोरूम, दिल्ली)

सर्दियों में सड़क पर उतरें पर जरा संभल कर

जाड़े ने दस्तक दे दी है. हम यह पक्का कर लेना चाहते हैं कि आपकी कार सर्दी के महीनों के हिसाब से तैयार हो जाए. हम यहां कुछ खास टिप्स दे रहे हैं जिसके जरिए ठंड के मौसम में अपनी कार से सफर करते हुए आप खुद को सुरक्षित रख सकते हैं

INDIA TODAY

BREAKING NEWS

JUST A TAP AWAY

9:41
INDIA TODAY
LIVE
TOP NEWS
VIDEOS
PROGRAMMES
TOP STORIES

LOK SABHA 2019

Narendra Modi Live: By Congress-mukt India we will fulfil Gandhi's dream

PM Narendra Modi was speaking in Lok Sabha

DOWNLOAD THE APP NOW

AVAILABLE ON

सर्दियों में गाड़ी चलाना थोड़ा मुश्किल हो सकता है. कोहरे की वजह से विजिबिलिटी कम हो जाती है जिससे आप दूर तक देख नहीं पाते. ठंड के कारण आपकी कार के पुर्जों में गड़बड़ हो सकती है. ऐसे में ड्राइवर और सड़क के बीच एक अच्छी-खासी जद्दोजहद वाली स्थिति बन जाती है. गाड़ी के रखरखाव और उसकी सुरक्षा जांच से जुड़े कुछ काम हैं, जो खासतौर से सर्दियों में जरूर किए जाने चाहिए. इसलिए अपनी गाड़ी के रखरखाव में जरा सी भी कोताही न करें, वर्ना सड़क किनारे कुल्फी की तरह जमने की नौबत भी आ सकती है. जब भी मौसम बदलता है, आपको गाड़ी का मेटेंनेंस चेक-अप करवा लेना चाहिए जिससे यह पक्का हो जाए कि गाड़ी में सब कुछ पूरी तरह दुरुस्त है. ऐसा करने से उन स्थितियों को कम करने या यहां तक कि बचने में मदद मिलेगी जिनके कारण कोल्ड-स्टार्टिंग जैसी परेशानियां झेलनी पड़ती हैं. सर्दियों के दौरान निम्नलिखित रखरखाव कार्य आपको और आपकी कार को परेशानियों से दूर रखेंगे.

मैनुअल देखें: गाड़ी के मालिक के लिए दिया गया मैनुअल यह बताएगा कि टायर, ब्रेक, फिल्टर और फ्लूइड कब बदलना है. गाड़ी की सर्विस कब करानी चाहिए, उससे जुड़े निर्देशों का पालन करें.

स्क्रीन पर से धुंध हटाना: ड्राइव शुरू करने से पहले कार के अंदर के हिस्से में स्क्रीन पर जमी नमी को हटाने के लिए पर्याप्त समय दें. पक्का करें कि कार का ब्लोअर भरपूर गर्म हवा फेंक रहा हो और एयर-कंडीशनर भी चालू हो ताकि स्क्रीन पर नमी फिर से न बनने पाए. हीटर गाड़ी के केबिन में प्रवेश करने वाली नमी को जल्दी से भाप बनाकर बाहर निकाल देता है. इंटीरियर्स पर नमी जमने की प्रक्रिया धीमी करने के लिए एयर-कंडीशनर को रिफ्रेश मोड में चलाएं.

अगर जरूरी हो तो इंजन ऑयल और फिल्टर बदल दें: उच्च गुणवत्ता वाला इंजन ऑयल मोटर को कोल्ड स्टार्ट वाली स्थिति (इंजन को जरूरी तापमान से कम पर चालू करने की कोशिश) से बचाता है. कभी भी इंजन स्टार्ट करने के साथ ही गाड़ी भगाना शुरू न करें. स्टार्ट करने के बाद थोड़ा रुकें ताकि लुब्रिकेंट्स पूरे इंजन में पहुंच जाएं.

पहिए फिट रखें: टायरों में एअर प्रेशर सही स्तर पर रखें. यदि आप बर्फीले हालात में गाड़ी चला रहे हैं, तो गाड़ी के चिपककर चलने के लिए टायर प्रेशर निर्धारित पीएसआइ से थोड़ा कम कर दें. अगर रास्ता गीला है या बारिश का समय है तो भी टायरों में प्रेशर कम रखें.

फिट बैटरी: कार की बैटरी और चार्जिंग की जांच करा लें. सर्दियों में तापमान बैटरी के प्रदर्शन को 50 प्रतिशत तक कम कर सकता है. इसलिए बैटरी तीन साल से ज्यादा पुरानी हो तो इसकी जांच करा लें. बैटरी टर्मिनलों को नियमित रूप से साफ करते रहें ताकि चार्ज फ्लो बेहतर बना रहे. देख लें कि टर्मिनल पर जंग तो नहीं लगी है.

गाड़ी की लाइट्स चेक कर लें: सर्दियों में विजिबिलिटी एक अहम पहलू होता है. सो, जांच लें कि कार की सभी लाइट्स: टेललाइट, सिग्नल बल्ब, ब्रेक लाइट, हेडलाइट और यहां तक कि केबिन लाइट ठीक से काम कर रही हैं या नहीं. बल्ब और फ्यूज का एक अतिरिक्त सेट साथ साथ रखें ताकि कोई लाइट अचानक खराब हो जाए तो आप उसे बदल सकें. यह पक्का करें कि गाड़ी की हेडलाइट्स के कारण विपरीत दिशा से आने वाली किसी अन्य गाड़ी के ड्राइवर को देखने में परेशानी न हो. कोहरे की स्थिति में हाइ बीम के प्रयोग से बचें.

गाड़ी के बेल्ट और पाइप जांच लें: आपकी गाड़ी के इंजन के बेल्ट और पाइप अच्छी स्थिति में होने चाहिए. सर्दियों में तापमान गिरने से ये कमजोर हो जाते हैं जिससे इनके चटकने-टूटने का अंदेशा रहता है. इंजन के कमजोर बेल्ट ज्यादा ठंड नहीं झेल पाएंगे.

एअर फिल्टर बदलें: एयर फिल्टर अगर जाम है तो बदल दें. एयर फिल्टर में जमने वाली धूल से यह जाम हो जाता है. कार हीटर चलाने पर फिल्टर में जमा गंदगी ब्लोअर से कार केबिन में पहुंच सकती है.

आपातकालीन किट: एक आपात किट तैयार करके कार में रखें. आपका फोन तो साथ होना ही चाहिए. गाड़ी में खाने-पीने का कुछ सामान, पानी, फ्लैशलाइट, फ्लेयर्स और फर्स्ट एड किट भी तैयार रखना चाहिए.■

जाड़े में जब आप निकलें ड्राइव पर: किन-किन बातों का रखें ख्याल

1. जरूरी लगे तो एअर और ऑयल फिल्टर साफ कर लें या फिर बदल लें

2. ठंड की वजह से आपकी बैटरी की कार्यक्षमता 50 फीसदी तक कम हो सकती है. तीन साल से ज्यादा पुरानी है तो अच्छा रहेगा कि आप एक बार इसे टेस्ट करवा लें

3. जाड़े में सड़कों पर दूर तक देख पाने में दिक्कत होती है. लाइट्स जांच लें, अतिरिक्त बल्ब और फ्यूज रख लें

4. इंजन के बेल्ट और पाइप अच्छी स्थिति में होने चाहिए

FROM THOSE WHO ARE FULL OF HOPE TO THOSE WHO NEED IT THE MOST

We believe in just one thing. Your voice matters. Irrespective of who you are, where you come from, where you stand, what you do and, who you support. We are the India Today Group. Where every voice finds its right. And every right finds a voice.

WE'RE ALWAYS IN CONVERSATION WITH YOU.

INDIA TODAY GROUP

INDIA'S DEMOCRATIC NEWSROOM

PRESENTING SPONSOR
Incredible India
ASSOCIATE SPONSORS
BIHAR TOURISM
Incredible India
INDIA TODAY
Tourism
SURVEY & AWARDS

INDIA TODAY Tourism SURVEY & AWARDS 2021

फिर जमने लगे कदम

कोविड से सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाले क्षेत्रों में से एक रहा है पर्यटन. लेकिन यह एक बार फिर पटरी पर आने लगा है. इंडिया टुडे टुरिज्म सर्वे ऐंड अवार्ड्स 2021 ने इस उद्योग को नए सिरे से खड़ा करने के लिए राज्यों की भूमिका को सराहा

शैली आनंद

PRESENTING SPONSOR
Incredible !ndia
ASSOCIATE SPONSORS
enchanting tamil nadu

कामयाबः इंडिया टुडे टुरिज्म सर्वे ऐंड अवाड्‌र्स 2021 के विजेता. (बाएं से क्रमशः) विकास कांबले, निशांत जैन, संतोष कुमार मल्ल, मिलिंद बोरीकर, सतपाल महाराज, जी. किशन रेड्डी, राज चेंगप्पा, डॉ. जगमोहन सिंह राजू, संजय कुमार, सिंधु रूपेश, जे.डी. पुष्पराज और तृप्ति व्यास

चंद्रदीप कुमार

सफर न केवल आदमी का दिल-दिमाग खोल देता है बल्कि जगह और गति में बदलाव से उसकी जिंदगी में एक नई ऊर्जा, नई ताकत भरी जा सकती है. महामारी, लॉकडाउन और प्रतिबंधों की बात कुछ हद तक पुरानी पड़ने और बड़े पैमाने पर टीकाकरण मुहिम चलाए जाने की वजह से पर्यटन क्षेत्र धीरे-धीरे खुल रहा है. लोगों में नई चीजों और जगहों का अनुभव लेने के प्रति उम्मीदें फिर बढ़ने लगी हैं.

भारत की अर्थव्यवस्था में पर्यटन की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है—दोनों का उद्धार एक-दूसरे से जुड़ा हुआ है. यह ऐसा क्षेत्र है जिसमें चार करोड़ से ज्यादा लोग प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से रोजगार पाते हैं. यह राजस्व में 200 अरब डॉलर (14.87 लाख करोड़ रु.) का योगदान करता है और हमारे जीडीपी को बढ़ाता है. इंडिया ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन (आइबीईएफ) के मुताबिक, भारत में पर्यटन क्षेत्र 2029 तक 6.7 फीसद की दर से बढ़ने वाला है, जो कुल अर्थव्यवस्था का 9.2 है; और 2028 तक अंतरराष्ट्रीय पर्यटकों का आगमन 3.05 करोड़ तक पहुंच जाने की संभावना है. लेकिन महामारी के लंबे चले दौर के बाद घरेलू पर्यटक ही इस वृद्धि में इजाफा करेंगे.

इसी सकारात्मक नजरिए के मद्देनजर और देश के विभिन्न पहलुओं, संस्कृति, इतिहास और इलाकों की पहचान कर उनका गुणगान करने के लिए नई दिल्ली में 12 नवंबर को इंडिया टुडे टुरिज्म ऐंड अवाड्‌र्स 2021 का आयोजन किया गया. इसमें विशेषज्ञों और भागीदारों ने यात्रा और पर्यटन क्षेत्र के विकास पर बहस और परिचर्चा की. उन्होंने इस पर भी बात की कि मांग बढ़ाने

के लिए आखिर किस तरह के बदलाव किए जाने की जरूरत है. इस कार्यक्रम के पैनल में शामिल विशेषज्ञों ने बताया कि आने वाले समय में यात्रा किस तरह की होगी; महामारी के बाद अब सैलानी के पास किस तरह पहले से ज्यादा जानकारी है और वह किस तरह ज्यादा परिष्कृत है. इस कार्यक्रम में केंद्रीय संस्कृति, पर्यटन और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री जी. किशन रेड्डी ने पुरस्कार भी वितरित किए.

इंडिया टुडे के ग्रुप एडिटोरियल डायरेक्टर (पब्लिशिंग) राज चेंगप्पा ने अपने उद्घाटन भाषण में इस तथ्य पर विचार पेश किया कि यह शिखर सम्मेलन ऐसे समय में आयोजित किया जा रहा है जब पर्यटन लंबी और बेहद काली रात से उबर रहा है, जो करीब डेढ़ साल तक रही. उन्होंने कहा कि छुट्टियों के दौरान सैर करने

> **''भारत में 2022 पर्यटन वर्ष होगा और हम इसके लिए व्यापक नीति तैयार करने की दिशा में काम कर रहे हैं''**
>
> **जी. किशन रेड्डी**
> केंद्रीय संस्कृति, पर्यटन और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री

चंद्रदीप कुमार

विजेता

उत्तराखंड

- **बेस्ट एडवेंचर डेस्टिनेशन**
  *ऋषिकेश, देहरादून**
- **बेस्ट स्पिरिचुअल डेस्टिनेशन**
  *केदारनाथ धाम**
- **बेस्ट वाइल्डलाइफ डेस्टिनेशन**
  *जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क ऐंड म्युजियम, रामनगर**

तमिलनाडु

- **बेस्ट माउंटेन डेस्टिनेशन**
  *कूनूर, नीलगिरि जिला**
- **बेस्ट फेस्टिवल डेस्टिनेशन**
  *पोंगल के लिए**
- **सर्वाधिक मनोरम सड़कें**
  *कोल्ली हिल्स, नमक्कल जिला***

महाराष्ट्र

- **बेस्ट हेरिटेज डेस्टिनेशन**
  *अजंता की गुफाएं**
- **बेस्ट माउंटेन डेस्टिनेशन**
  *महाबलेश्वर***

गोवा

- **बेस्ट एडवेंचर डेस्टिनेशन**
  *बंजी जंपिंग, मायम लेक, उत्तरी गोवा***
- **बेस्ट बीचेज ऐंड कोस्टल डेस्टिनेशन**
  *अश्वम बीच, मंदरम, उत्तरी गोवा***

पंजाब

- **सर्वाधिक मनोरम सड़कें**
  *नांगल से भाखड़ा बांध मार्ग**
- **बेस्ट आइकॉनिक लैंडस्केप डेस्टिनेशन** *नांगल बांध, रोपड़***

बिहार

- **बेस्ट स्पिरिचुअल डेस्टिनेशन**
  *बोध गया, गया जिला***

गुजरात

↘ बेस्ट बीचेज ऐंड कोस्टल डेस्टिनेशन
*शिवराजपुर बीच (समुद्र तट)**

↘ बेस्ट वाइल्डलाइफ डेस्टिनेशन
*गिर नेशनल पार्क***

↘ बेस्ट हेरिटेज डेस्टिनेशन
*धौलावीरा, कच्छ***

राजस्थान

↘ बेस्ट आइकॉनिक लैंडस्केप डेस्टिनेशन
*गरडिया महादेव, कोटा**

↘ बेस्ट फेस्टिवल डेस्टिनेशन
*डेजर्ट फेस्टिवल, जैसलमेर***

कर्नाटक

↘ बेस्ट फेस्टिवल डेस्टिनेशन
*मैसूरु दशहरा***

↘ बेस्ट माउंटेन डेस्टिनेशन
*नंदी हिल्स***

*विजेता **रनर-अप

का रुझान अब तेजी से बढ़ रहा है और 2022 इस उद्योग के लिए एक तरह से उफान का वर्ष हो सकता है, खासकर घरेलू पर्यटन के लिए, जो इस क्षेत्र की कमाई में 90 फीसद का योगदान करता है. लिहाजा, जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना है, यह समय, ''वोकल फॉर लोकल'' के लिए आगे बढ़ने का है और 'देखो अपना देश' कार्यक्रम का हिस्सा बनने का है, जिसे उन्होंने महामारी से ऐन पहले शुरू किया था.

घरेलू पर्यटन को प्रोत्साहन

केंद्रीय मंत्री रेड्डी ने ''घरेलू पर्यटन और महामारी के बाद की दुनिया में विकास के लिए अगले बड़े कदम'' पर अपने बीज भाषण में कहा कि पर्यटन उन क्षेत्रों में शामिल है जिन्हें महामारी के दौरा सबसे ज्यादा झटका लगा. उन्होंने पर्यटन को प्रोत्साहन देने और इस तरह के गंभीर और चुनौतीपूर्ण समय में राज्यों की ओर से किए गए काम की पहचान करने के लिए इंडिया टुडे ग्रुप को धन्यवाद दिया. उन्होंने टीकाकरण—100 करोड़ वैक्सीन शॉट लगने—के क्षेत्र में भारत की शानदार उपलब्धि के बारे में भी बताया और यह भी कि किस तरह इसने लोगों में अपने घरों से बाहर निकलकर एक बार फिर पर्यटन स्थलों की सैर करने के लिए भरोसा जगाया है. उन्होंने कहा, ''यह भारतीय लोकतंत्र और सहकारी संघीय व्यवस्था की बड़ी जीत है.'' उन्होंने बताया कि 2022 भारत के लिए पर्यटन वर्ष होगा. उन्होंने करीब 30 संग्रहालयों को खोलने की सरकार की योजना के बारे में बताया; यह भी कि किस तरह विभिन्न सरकारी विभाग अगले साल पर्यटन क्षेत्र की मदद करेंगे. उन्होंने कहा, ''हमने इस बात पर चर्चा की है कि विस्तृत पर्यटन नीति होनी चाहिए. हमने भागीदारों, टुअर ऑपरेटरों और होटलों से बात की है, और विभिन्न राज्य सरकारों से उनकी सलाह मांगी.''

केंद्रीय मंत्री ने यह भी बताया कि महामारी के मद्देनजर उन्होंने कर्ज के जरिए टुअर ऑपरेटरों को वित्तीय मदद मुहैया कराने के लिए काम शुरू कर दिया है. उन्होंने जानकारी दी कि सरकार ने फैसला किया है, भारत आने वाले पहले पांच लाख अंतरराष्ट्रीय सैलानियों से कोई पर्यटन शुल्क नहीं लिया जाएगा. रेड्डी ने बताया, ''हमने 70 देशों से आने वाले सैलानियों के लिए भी ई-वीजा प्रोग्राम शुरू कर दिया है.''

> **''उत्तराखंड राज्य में धार्मिक क्षेत्र और एडवेंचर टुरिज्म के क्षेत्र में विंटर टुरिज्म को प्रोत्साहन देने पर ध्यान दे रहा है. चार धाम में पर्यटकों की अगवानी के लिए इन्फ्रास्ट्रक्चर तैयार है... साथ ही हम औली विंटर स्पोर्ट्स को बड़े पैमाने पर बढ़ावा दे रहे हैं''**
>
> **सतपाल महाराज**
> पर्यटन मंत्री, उत्तराखंड

चंद्रदीप कुमार

वोकल फॉर लोकल

'देखो अपना देश—राज्य किस तरह पर्यटन के पुनरुद्धार का नेतृत्व कर रहे हैं', शीर्षक वाले सत्र में इस बात का जिक्र किया गया कि राज्यों ने कोरोना वायरस से लड़ने में अहम भूमिका निभाई है और वे पर्यटन उद्योग को अपने पैरों पर खड़ा करने की दिशा में काम कर रहे हैं. इस पैनल में तीन वक्ता थे—मिलिंद बोरीकर, निदेशक, पर्यटन निदेशालय, महाराष्ट्र पर्यटन; संजय कुमार, अतिरिक्त मुख्य सचिव (पर्यटन), पंजाब पर्यटन; और संतोष कुमार मल्ल,

हार्दिक छाबड़ा

MILIND BORIKAR
SANJAY KUMAR
SANTOSH KUMAR MALL
Incredible India
INDIA TODAY Tourism SURVEY & AWARDS 2021

मिलिंद बोरीकर
निदेशक, पर्यटन निदेशालय,
महाराष्ट्र पर्यटन

"हमने ढेर सारी सुविधाओं के साथ हॉस्पिटेलिटी या सत्कार उद्योग को औद्योगिक दर्जा दे दिया है. हम पर्यटन क्षेत्र को खुला हाथ दे रहे हैं"

संजय कुमार
अतिरिक्त मुख्य सचिव (पर्यटन),
पंजाब पर्यटन

"हर राज्य सूखे कचरे के प्रबंधन सिस्टम को लेकर जागरूक हो रहा है. यह हमारे जीवन का हिस्सा बन गया है. हम इलेक्ट्रिक वाहन की ओर कदम बढ़ा रहे हैं"

संतोष कुमार मल्ल
पर्यटन सचिव, बिहार पर्यटन

"गया में लाखों लोग दर्शन के लिए आते हैं. हमारे पर्यटन में सबसे बड़ा हिस्सा हमेशा इसी का होता है लेकिन कई ऐसी जगहें हैं जिनकी संभावनाओं का दोहन नहीं किया गया है"

पर्यटन सचिव, बिहार पर्यटन.

तीनों वक्ताओं ने ईको-फ्रेंड्ली या जिम्मेदार पर्यटन की जरूरत के बारे में बातचीत की और इस बात पर सहमति जताई कि लंबे अरसे में इस क्षेत्र के स्वास्थ्य के लिए पर्यावरण के अनुकूल रवैए के साथ ही नई जगहों की संभावनाओं का दोहन करने की जरूरत है. इसके लिए संजय कुमार ने सुझाव दिया कि राज्यों को ईको टूरिज्म को प्रोत्साहन देने के लिए सूखे कचरे और वाहनों की आवाजाही के मुद्दों पर ध्यान देना होगा. बोरीकर ने बताया कि नीति में बदलाव से महाराष्ट्र को कैसे मदद मिली है. मिसाल के तौर पर, होटल खोलने के लिए 100 अनुमतियों की संख्या घटाकर 70 कर दी गई हैं.

उन्होंने बताया कि युवाओं को आकर्षित करने के लिए राज्य एडवेंचर टुरिज्म, शहरी सैलानियों के लिए कृषि पर्यटन पर ध्यान दे रहा है, और महामारी के बाद पर्यटन का स्वरूप बदलने के लिए अपने 400 किलों, समुद्रतटों और वन्यजीव वाले इलाकों को प्रोत्साहन देने पर खास ध्यान दे रहा है.

बड़ा बदलाव

डिजिटल क्रांति ने जीवन के सभी क्षेत्रों को प्रभावित किया है और पर्यटन कोई अपवाद नहीं है. 'डिजिटल लैंडस्केप में घरेलू पर्यटन' नाम के सत्र के दौरान वक्ताओं ने बताया कि ऑफलाइन से ऑनलाइन के बीच कैसे बड़ा परिवर्तन हुआ है. डिजिटल सैलानी महामारी की देन हैं और अब पर्यटन में भौतिक और वर्चुअल अनुभव शामिल होंगे. पैनल में ध्रुव श्रृंगी, सीईओ, यात्रा.कॉम; रोहित कपूर, सीईओ, ओयो इंडिया और साउथ एशिया; और बाबू पणिक्कर, मैनेजिंग डायरेक्टर, पणिक्कर्स ट्रैवल शामिल थे. श्रृंगी ने इस क्षेत्र के उद्धार की चर्चा करते हुए कहा कि सामान्य यात्रा में पिछले तीन महीने में 30-40 फीसदी इजाफा हुआ है, जिससे यह महामारी से पहले के स्तर के करीब पहुंच गई है. घरेलू यात्रा लगभग पटरी पर आ चुकी है, और हालांकि

INDIA TODAY GROUP

Incredible India

PRESENTS

INDIA TODAY Tourism SURVEY & AWARDS 2021

We are very **grateful** to all our **sponsors** for making the event a grand **success**!

ASSOCIATE SPONSORS

BIHAR TOURISM Blissful Bihar | Gujarat Tourism | MAHARASHTRA TOURISM | PUNJAB tourism India Begins Here | enchanting tamil nadu experience yourself | Uttarakhand Simply Heaven! | RAJASTHAN The Incredible State of India !

हार्दिक छाबड़ा

DHRUV SHRINGI
ROHIT KAPOOR
BABU PANICKER
Incredible India
INDIA TODAY Tourism SURVEY & AWARDS 2021

ध्रुव श्रृंगी
सीईओ, यात्रा.कॉम

> ''न केवल उद्योग के नजरिए से बल्कि एक उपभोक्ता के नजरिए से भी ऑनलाइन से ऑफलाइन जाने के मामले में व्यवहार संबंधी बहुत बड़ा बदलाव हुआ है''

रोहित कपूर
सीईओ, ओयो इंडिया और साउथ ईस्ट एशिया

> ''यात्रा का सारा सरोकार अनुभवों से है. अनुभव लेने के लिए अब पैसे का आवंटन ज्यादा होता है और यह तेजी से चढ़ता रुझान है, उतरता रुझान नहीं है''

बाबू पणिक्कर
प्रबंध निदेशक, पणिक्कर्स ट्रैवल

> ''लॉकडाउन की वजह से एक जगह कैद लोग धीरे-धीरे जरूर निकलेंगे और अगले साल से वे बाहर निकलेंगे. ऐसा अभी से होने लगा है लेकिन धीरे-धीरे इसमें वृद्धि होगी''

बिजनेस ट्रैवल फिलहाल कुछ शांत है लेकिन अगले साल के शुरू में इसमें तेजी आनी चाहिए.

कपूर ने कहा कि महामारी के बाद का सैलानी साफ-सफाई और आरोग्य व्यवस्था को लेकर खासा फिक्रमंद है और होटलों को कॉन्टैक्टलेस चेक-इन व्यवस्था कायम करने की जरूरत है. उन्होंने उत्सर्जन कम करने और पर्यटन केंद्रों को खुद बदलने की जरूरत के बारे में भी बात की. उन्होंने यह भी कहा कि महामारी के बाद 'कहीं से भी काम' करने की अवधारणा के जोर पकड़ने से लोग अक्सर कम समय की छुट्टी लेंगे, एक साल में शायद मुश्किल से आठ या 10 बार. पणिक्कर के मुताबिक, भूतल परिवहन के कारोबार में होने की वजह से पिछले 18 महीनों में महामारी से वे प्रभावित हुए हैं और उन्हें अब भी यह देखना है कि वे इस नुक्सान की भरपाई आखिर कैसे करेंगे.

पुरस्कार और प्रशंसा

इस सम्मेलन का समापन केंद्रीय मंत्री रेड्डी के हाथों विजेता राज्यों के प्रतिनिधियों को इंडिया टुडे टुरिज्म अवार्ड्स देने के साथ हुआ. विजेताओं का चयन करने के लिए देशव्यापी सर्वेक्षण किया गया था. विभिन्न श्रेणियों के पर्यटन केंद्रों को एक मल्टीमीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रचारित किया गया और पाठकों से अपना वोट डालने के लिए कहा गया. उसके बाद आइपीएसओएस ने नतीजों को जमा किया, और आखिरकार उसी ने अंतिम नतीजा निकालने के लिए ऑन-ग्राउंड सर्वेक्षण भी किया. ■

मन्नू भंडारी 1931-2021

कभी न होगा उनका अंत

ममता कालिया

बड़ा मनहूस रहा 15 नवंबर, 2021 का दिन. साहित्य-जगत का एक जगमग सितारा टूटकर गिरा. हमारी प्रिय रचनाकार मन्नू भंडारी का निधन हो गया. तकलीफ में तो कई वर्षों से थीं जब उन्हें न्यूरोल्जिया (नस का दर्द) शुरू हुआ. फिर भी वे हिम्मत कर लिखती रहीं. आंखों की समस्या और भी भीषण साबित हुई. समस्त उपचार के बावजूद काला मोतियाबिंद आंखों में पसरता गया. तरह-तरह की शारीरिक, भावात्मक और स्नायविक व्याधियों में एक पूर्णकालिक नौकरी निभाई, बीसियों पुस्तकें लिखकर हिंदी कथा साहित्य को समृद्ध किया, कई दर्जन कहानियों में स्मरणीय पात्र और परिस्थितियां दिखाईं, नाटक लिखे, अपने उपन्यास *महाभोज* की पटकथा लिखी, टीवी के लिए *रजनी* जैसा यादगार धारावाहिक लिखा और *यही सच है* कहानी पर आधारित यादगार सर्वश्रेष्ठ फिल्म *रजनीगंधा* लिखी.

उनकी बहुआयामी प्रतिभा हरफनमौला कमलेश्वर से कतई कम न थी पर वे रचनाओं की सौदागर न थीं. बासु चटर्जी सम्मानपूर्वक उनसे फिल्म और दूरदर्शन के लिए लिखने का अनुरोध करते और वे मनोयोग से यह काम कर देतीं. कह सकते हैं जब तक लेखक साथी राजेंद्र यादव का प्रेम और उत्साह उनके साथ रहा, उनकी रचनाशक्ति जाग्रत और जीवंत रही.

अपने शीर्ष रचनात्मक वर्षों में उन्होंने कमतर और कमजोर लेखिकाओं को अपने व्यक्तित्व और कृतित्व पर हावी होते देखा. कम दवा से कोई नहीं मरता, कम प्रेम से जरूर मर जाता है. उन्होंने स्त्री-विमर्श का बाजारवादी शोर देखा. इसीलिए सन् 2003 में *उत्तर प्रदेश* स्त्री-विमर्श विशेषांक में उन्होंने विशेष रूप से लेख लिखा 'स्त्री-विमर्श का यथार्थ', जिसमें बिना तिक्तता के उन्होंने अपने विचार रखे: ''आज स्त्री-विमर्श से कहीं ज्यादा पुरुष-विमर्श की जरूरत है. पिछले 35-40 वर्षों में स्त्री ने अपने को जड़ संस्कारों से मुक्त किया है, पुरुष आज भी जिसमें बंधा बैठा है''

''नहीं, मुझे ऐसी कोई शिकायत नहीं रही कि स्त्री होने के नाते लेखन के क्षेत्र में मेरे साथ कोई भेदभाव किया गया हो या कि मुझे खामियाजा भुगतना पड़ा हो. साथ ही यह भी कह दूं कि स्त्री होने का कोई फायदा भी मैंने कभी नहीं उठाया.''

ये हैं एक संतुलित, जागरूक, प्रबुद्ध स्त्री के विचार जिसने अपने रचनात्मक दृष्टिकोण से साहसिक रचनाएं दीं. उन्होंने दलित-विमर्श और दलित-समाज के राजनीतिक दुरुपयोग की बात तब लिखी जब दलित-विमर्श का झंडा बुलंद नहीं हुआ था. उन्होंने विभाजित परिवार का बच्चे के मनोविज्ञान पर प्रहार जैसा अग्रगामी विषय तब उठाया जब इस पर भारतीय कलम नहीं चली थी.

भरत तिवारी

मन्नूजी की पहली या दूसरी कहानी इलाहाबाद से *कहानी* पत्रिका में छपी थी. हम सभी रचनाकारों की तरह मन्नूजी ने भी अपनी रचना की हस्तलिखित प्रति संपादक के नाम बुकपोस्ट की थी. इस बीच पत्रिका के संपादक श्यामू सन्यासी की बजाय भैरवप्रसाद गुप्त हो गए थे. उन्हें कहानी पसंद आई और उन्होंने स्वीकृति-पत्र भेज दिया. यह तो बाद में पता चला कि उनकी कहानी भैरवजी जैसे घनघोर मार्क्सवादी के हाथों से गुजरी है. आज चंद लोग जो उन पर प्रतिक्रियावादी होने का आरोप लगाते हैं, नहीं जानते कि भैरवजी की अदालत में किसी को लिहाज या डिस्काउंट पर नहीं छापा जाता था. मन्नू भंडारी ने पहले से उस सिर उठाती, सवाल पूछती स्त्री के बारे में लिखा जो पढ़-लिख कर नौकरी के क्षेत्र में प्रवेश कर चुकी है.

आपका बंटी की नायिका शकुन कॉलेज की प्राचार्य है. *एक इंच मुस्कान, त्रिशंकु, आंखों देखा झूठ, तीन निगाहों की एक तस्वीर, ऊंचाई, सजा, अकेली,* न जाने कितनी रचनाएं हैं जो हमारी स्मृतियों का अक्षय कोष बनी हुई हैं. बेबाक बयानी, निश्छल मन, स्वाभिमान और उदारता उनके व्यक्तित्व के अभिन्न गुण थे. ख्याति और लोकप्रियता के शीर्ष पर भी उन्हें दंभ कभी छू न पाया.

मन्नू भंडारी अपनी समकालीन रचनाकारों की कॉन्ट्रास्ट थीं. कृष्णा सोबती, उषा प्रियंवदा और मन्नू भंडारी में सबसे सहज कलम मन्नूजी की थी. सजगता के साथ सहजता कायम रखना एक बड़े लेखक की पहचान है. मन्नू भंडारी स्व और पर के बीच सम्यक संतुलन बैठाते हुए *आपका बंटी* जैसा जटिल उपन्यास लिख गईं कि स्वयं मोहन राकेश को उनसे कोई शिकायत न हुई. *आपका बंटी* मोहन राकेश के जीवन से प्रेरित रचना है. *एक कहानी यह भी* में मन्नूजी ने अपने विद्यार्थी जीवन की सक्रियताएं तो दर्ज कीं ही, उन घटनाओं को भी कुरेदा जो पति-पत्नी संबंधों में कील-से कसकते रहे. लेखक के अंदर उमड़ते उत्साह, उमंग, असमंजस, प्रबोध, प्रबुद्धता, द्वंद्व और दुविधा, आशा और हताशा, इन सभी भावों का इस पुस्तक में बेहद सजीव और संयत आकलन हुआ है. 16 नवंबर को भारी मन से हम सब मन्नूजी को विदा देकर लौटे हैं. वे फिर-फिर मिलेंगी हमें, किताबों में, यादों में. ■

बेहतरीन बागबान
जयराम मीणा पौधा
रोपते हुए

रोप रहे एक अदद उम्मीद

असल कामः मात्र 12 साल की उम्र से जयराम मीणा खाली पड़ी सार्वजनिक जमीन पर पौधे लगा रहे हैं. अब तक वे 11 लाख से ज्यादा पौधे रोप चुके हैं और निकट भविष्य में भी यह काम रोकने की उनकी कोई योजना नहीं है

राहुल नरोन्हा

जयराम मीणा, 52 वर्ष,

किसान

गांवः बसोंद; जिलाः
शिवपुर, मध्य प्रदेश

जयराम मीणा को याद है कि 12 साल की उम्र में वे अपने दादा मथुरालाल मीणा के साथ अपने गांव बसोंद के आसपास जब भी और जहां भी जगह मिलती, वहां पौधे लगाने पहुंच जाते थे. बीते लगभग 40 साल से जयराम ने न केवल इस आदत को कायम रखा है, बल्कि इसे अपनी जिंदगी का मिशन बना लिया है.

जयराम जब 16 साल के थे तब उनके दादा जी का देहावसान हो गया और बीते वर्षों में उनकी याद में जयराम ने अपने घर के परिसर में 11 पौधे लगाए. ये 11 पौधे रोपने के बाद जयराम के मन में 1,100 पौधे लगाने की बात आई. यह लक्ष्य पूरा हुआ तो उन्होंने 31,000 पौधे और लगाने का संकल्प लिया. फिर इसके बाद 11 लाख पौधे लगाने का. इतना बड़ा लक्ष्य भी उन्होंने दो साल पहले हासिल कर लिया. जयराम के शब्दों में, ''मेरे दादाजी अक्सर कहा करते थे कि पौधे लगाना उतना ही पवित्र कार्य है जितना कि यज्ञ करना. सालों बाद मैंने ऋषिकेश में एक धर्माचार्य को यही शब्द दोहराते हुए सुना.''

मुख्य सड़क से उनके गांव की ओर जाने वाली सड़क के दोनों किनारों पर नीम और बरगद के पेड़ लगे हैं जो अपने मकसद में उनके जी-जान से लगे होने का सबूत देते लगते हैं. बसोंद में नहरों के किनारे, सरकारी जमीन पर, पुलिस थाना परिसर, औषधालय, स्कूल और मंदिर परिसर में सब ओर पेड़ हैं—इन सभी को जयराम ने लगाया था. उनका वृक्षारोपण कार्य अब राज्य की सीमाओं से आगे बढ़ चला है. उन्होंने पड़ोसी राज्य राजस्थान और यहां तक कि सुदूर उत्तराखंड में भी वृक्षारोपण अभियान चलाया है.

जयराम यह काम अपने संसाधनों से करते हैं. कुल 11 बीघा जमीन वाले छोटे किसान जयराम के परिवार में चार लोग हैं और उन्हें अपने जुनून पर किए जा सकने वाले खर्च का ख्याल रखना पड़ता है. उनकी अपनी नर्सरी है, जहां वे बीजों से पौधे तैयार करते हैं. इस काम में वे स्थानीय बच्चों की मदद लेते हैं. वे मुस्कुराते हुए बताते हैं कि मौसम आने पर जब नीम के पेड़ पर फल लगते हैं, तो मैं गांव के बच्चों से उन्हें इकट्ठा करके लाने के लिए कहता हूं. बदले में मैं उन्हें बिस्कुट देता हूं. अंकुरित पौधों को जयराम एकत्रित की गई पॉलीथीन की थैलियों और प्लास्टिक कंटेनरों में लगाते हैं. मीणा अपने तरीके के बारे में बताते हैं कि ''बहुत सारे उर्वरक, खरपतवारनाशी और कीटनाशक प्लास्टिक की बोतलों या पैकेट में आते हैं. सामग्री का उपयोग करने के बाद किसान आमतौर पर इन्हें फेंक देते हैं. कुछेक साल पहले मैंने तय किया कि मैं चारों ओर जा-जाकर इन पैकेटों को इकट्ठा करूंगा और पौधों को रखने के लिए उनका इस्तेमाल करूंगा.''

पौधे रोपने के लिए दूर तक जाने की यात्राएं उन्होंने अकेले शुरू की थीं. अपनी साइकिल पर बाल्टियों में पानी लेकर वे दूर-दूर तक जाकर पौधों को पानी देते थे. लेकिन अब उनके पास ऐसे लोगों का समुदाय है जो पौधों की देखभाल करने के काम में स्वैच्छिक सहयोग देते हैं. लगभग 20 साल पहले राज्य के वन विभाग ने भी उनका सहयोग करना

राजवंत रावत

खुशी का मंत्र

> *''आप अपना काम कीजिए. शुरू में लोग आप पर हंसेंगे. धीरे-धीरे जब उन्हें एहसास होगा कि आप कितनी लगन से इस काम में लगे हैं तो वे आपके साथ-साथ हंसेंगे''*

शुरू किया और उन्हें एक साइकिल तथा कुछ पौधे और बीज देकर पौधे तैयार करने का काम सौंपा. जयराम बताते हैं कि पानी की कमी और थोड़ी पथरीली मिट्टी को देखते हुए नीम इन क्षेत्रों में लगाने के लिए आदर्श पेड़ है. केवल कक्षा 4 तक पढ़े जयराम क्षेत्र में पाए जाने वाले पेड़ों की प्रजातियों और उनकी देखभाल करने के तौर-तरीकों के बारे में अच्छा-खासा ज्ञान रखते हैं.

जयराम के घर का अहाता मोर और दूसरे पक्षियों के लिए भरे-पूरे पारिस्थितिकी तंत्र के रूप में विकसित हो गया है और मोर तथा तीतर उनके घर के आसपास खुले मैदान में घूमते दिख सकते हैं. वे बताते हैं कि पौधे लगाने के मेरे जुनून के कारण शुरुआती दिनों में मेरे परिजनों, दोस्तों और यहां तक कि मेरी पत्नी और बच्चों को भी लगता था कि मैं मानसिक रूप से बीमार हूं. बाद में उन्हें महसूस हुआ कि यह कोई सनक भरा दौर नहीं था. पर्यावरण के क्षेत्र में काम करने के लिए 2006 में प्रतिष्ठित अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार मिलने के बाद से सभी का नजरिया बदल गया. वे कहते हैं, ''कुछ लोगों को शराब पीने से, तरह-तरह का भोजन करने या पैसा जोड़ने से खुशी मिलती है, मुझे मेरे लगाए पौधों को पेड़ बनते देखकर खुशी मिलती है.''

तो, आपका अगला बड़ा लक्ष्य क्या है? पूछने पर जयराम कहते हैं कि मैं अपना शेष जीवन लोगों, विशेषकर बच्चों को पेड़ों, पक्षियों और जानवरों और हमारे जीवन में उनके महत्व के बारे में जानकारी देने में बिताना चाहता हूं. कृषि इस क्षेत्र का मुख्य आधार है. पिछले कुछ वर्षों में फसलों का पैटर्न बदल गया है और भूमिगत जल बहुत ज्यादा तेजी से खींचा जा रहा है. अगर यहां कृषि को कायम रखना है तो पेड़ों की भूमिका महत्वपूर्ण होगी.

जुलाई में आई बाढ़ में जयराम की नर्सरी का एक बड़ा हिस्सा बह जाने के अलावा उनके घर का एक हिस्सा भी तबाह हो गया था. इन दिनों वे अपनी नर्सरी के पुनर्निर्माण में व्यस्त हैं और जो कुछ भी बच सकता है उसे बचाने की कोशिश में लगे हैं. बाढ़ से उनके उत्साह पर कोई फर्क नहीं पड़ा है. ■

खुशी की तलाश: *इंडिया टुडे तथा आरपीजी समूह का संयुक्त उद्यम है जो प्रसन्नता फैलाने वाली अनुकरणीय पहलकदमियों को रेखांकित करता है*

जिससे मिलती है मुझे खुशी

भुवन बाम

यूट्यूबर और कॉमेडियन

''मुझे मेरा काम बिना किसी अड़ंगेबाजी के करने दिया जाए तो मुझे खुशी होती है क्योंकि दिमाग में ऑलरेडी बहुत कुछ चलता रहता है. भूख लगने पर अगर मैं कुछ खाना चाहता हूं तो खाता नहीं, रुक जाता हूं. अगर मैं कुछ शूट करना या लिखना चाह रहा हूं और उस वक्त मुझे मेरा फोन नहीं मिल रहा है, तो मैं रुक जाता हूं. मैं हर पल को जीना चाहता हूं. आगे क्या होगा, इस बारे में सोचना मैंने छोड़ दिया है. पिछले कुछ महीनों के अनुभव ने बता दिया है कि कल का आपको कुछ भी नहीं पता.''

सवाल + जवाब

अपनी जिंदगी का ऐंकर

नेटफ्लिक्स पर आई नई फिल्म *धमाका* में **कार्तिक आर्यन** एक अलग अंदाज वाले न्यूज ऐंकर के किरदार में हैं. और उनके मुताबिक, असल जिंदगी में वे एक ऐसे दौर में हैं जहां उनका मनचाहा सब कुछ उन्हें मिल रहा है

● ***धमाका* एक ऐसे टीवी न्यूज ऐंकर पर केंद्रित है जिसके साथ खड़े हो पाना मुश्किल है. ग्रे शेड वाला यह किरदार आपको पसंद आया?**

वह बहुत प्यारा किरदार नहीं है, यह बात मुझे पसंद आई थी. वह नितांत मौकापरस्त बंदा है, जो अपनी ही धुन में पागल है. वह बस वहां पहुंचना चाहता है. कुछ हालात उसने बनाए और कुछ बन जाते हैं. नैतिकता इस बंदे के लिए कोई मूल्य नहीं. वह आपको खुद पर सवाल करने को मजबूर करता है.

● **आप टीवी न्यूज देखते हैं?**

परिवार वाले, खासकर मेरे पापा हिंदी न्यूज चैनल बड़ी शिद्दत से देखते हैं. लॉकडाउन के दौरान मैंने भी काफी देखा. मैंने नोटिस किया है कि पत्रकारिता बड़ी जिम्मेदारी वाला काम है. मुझे लगता है, बतौर ऐक्टर मैं बहुत काम करता हूं लेकिन पत्रकार तो 24x7 काम पर रहते हैं. और अक्सर ही अपनी जाती जिंदगी तो पीछे रखकर. इस बात का मैं बहुत सम्मान करता हूं.

● **इस रोल के लिए कैसे तैयारी की. आपके पास कोई संदर्भ था?**

उस दुनिया के भीतर के पहलू जानने के लिए मैंने कई सारे ऐंकर्स, रिपोर्टर्स और रेडियो जॉकी से बातचीत की. मुद्दा यह होता कि कुछ मामलों को उन्होंने कैसे कवर किया, वे क्या सोचते हैं, क्या बोलते और क्या नहीं बोलते हैं. हालांकि धमाका टीवी न्यूज इंडस्ट्री पर नहीं बल्कि वह तो पूरी जिंदगी पर केंद्रित है.

● ***धमाका* और आपकी आने वाली फिल्मों से लगता है कि अब आप उस रोमांटिक कॉमेडी से आगे निकलना चाहते हैं जिसने आपको पॉपुलर बनाया.**

मेरा ध्यान अपने काम पर है. बेशक अटेंशन मिलना अच्छा लगता है पर मैं चाहता हूं कि वह मेरे काम पर ही रहे. मेरे ख्याल से मेरी फिल्मों से यह बात जाहिर हो जाती है, चाहे वह हंसल मेहता के साथ हो या शशांक घोष के साथ. फिल्मकार मुझमें भरोसा जता रहे हैं. मैं कैंडी शॉप में जा पहुंचे बच्चे की तरह हूं. वह जिस पर भी उंगली रख रहा है, उसे मिल रहा है. अब भला मुझे क्या शिकायत होगी!

–सुहानी सिंह

फोटोः बंदीप सिंह, जैकेटः एमऐंडएस विंटर कलेक्शन, लोकेशन साभारः द क्वेरी कोःलैब

वर्षः 36; अंकः 1; 25 नवंबर-1 दिसंबर, 2021; प्रत्येक शनिवार को प्रकाशित, *कुल पन्नेः* 74 *(कवर सहित)*

भगवान बुद्ध की ज्ञान स्थली बिहार!

महाबोधि मंदिर,
बोध गया

विश्व शांति स्तूप, राजगीर

घोड़ा कटोरा, राजगीर

अशोक स्तंभ, वैशाली

BIHAR
TOURISM
Blissful Bihar

बिहार की धरती महात्मा बुद्ध के दर्शन एवं उपदेशों को जीवंत बनाती है। महाबोधि मंदिर, अशोक स्तंभ, घोड़ा कटोरा, विश्व शांति स्तूप, केसरिया स्तूप जैसे अनेक स्थल जो सदियों से भगवान बुद्ध के अवतरण का एहसास कराती है।

भगवान बुद्ध के उपदेशों का अनुसरण करें, आओ बिहार भ्रमण करें।

/tourismbihargov

www.tourism.bihar.gov.in

IndiaContent

SEARCH FOR
EDITORIAL IMAGES
ENDS HERE